

अर्थव्यवस्था की स्थिति *

वैश्विक अर्थव्यवस्था स्थिर वृद्धि और नरम मुद्रास्फीति के साथ आघात-सहनीयता प्रदर्शित करना जारी रखती है। 2024-25 की तीसरी तिमाही के लिए उच्च आवृत्ति संकेतक (एचएफआई) यह संकेत देते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था दूसरी तिमाही में देखी गई मंदी से उबर रही है, जो मजबूत त्यौहारी गतिविधि और ग्रामीण मांग में निरंतर वृद्धि से प्रेरित है। रबी की बुवाई के तेज विस्तार के साथ कृषि और इसलिए ग्रामीण खपत की संभावनाएं बेहतर दिख रही हैं। खाद्य कीमतों में कमी के कारण नवंबर 2024 में हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति 5.5 प्रतिशत तक कम हो गई।

परिचय

वैश्विक अर्थव्यवस्था स्थिर वृद्धि और नरम मुद्रास्फीति के साथ आघात-सहनीयता प्रदर्शित करना जारी रखती है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) के आकलन¹ में, वैश्विक व्यापार में सकारात्मक वृद्धि की गति कंटेनर और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों में बढ़ोतरी के साथ-साथ वैश्विक तकनीकी चक्र में वृद्धि द्वारा कायम है। लाल सागर से दूर मार्ग बदलने के कारण प्रमुख एशियाई केंद्रों में शिपिंग जमावड़ा के बावजूद आपूर्ति श्रृंखलाएं अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। ई-कॉमर्स और शिपिंग में हो रही देरी से लाभ उठाते हुए हवाई माल ढुलाई की मात्रा बढ़ रही है।

2024 के दौरान पण्य की कीमतों में गिरावट आई है, जो कई कारकों के संगम को दर्शाता है। ऊर्जा बाजारों में, अक्टूबर 2024 से कच्चे तेल की कीमतों में नरमी आ रही है क्योंकि वैश्विक जीडीपी की घटती ऊर्जा तीव्रता के साथ वैश्विक तेल की खपत में गिरावट आई है। आपूर्ति में भी विविधता आ रही है, गैर-ओपेक प्लस की बाजार हिस्सेदारी धीरे-धीरे बढ़ रही है। ओपेक प्लस खुद अतिरिक्त क्षमता को कम करने के लिए तैयार है। धातु बाजारों

में, चीनी प्रोत्साहन के जवाब में सितंबर के अंत में हुई रैली तब से कमजोर होती जा रही है। भू-राजनीतिक तनावों के कारण सोने की कीमतों में उछाल आया, लेकिन अमेरिकी डॉलर की निरंतर मजबूती ने इसे पीछे छोड़ दिया। कृषि पण्य बाजारों में, कई प्रमुख फसलों की कीमतें अच्छी फसल के कारण कम हुई हैं, सिवाय कुछ को छोड़कर जो मौसम और बीमारी से संबंधित आघातों और व्यापार प्रतिबंधों से प्रभावित हुई हैं। 2025 में, कृषि पण्य की कीमतों में 4 प्रतिशत की गिरावट आ सकती है।

फिर भी, खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) और विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) द्वारा नवंबर 2024 से मई 2025 की अवधि के लिए जारी की गई प्रारंभिक चेतावनी के अनुसार, निम्न और मध्यम आय वाले देशों में खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति उच्च बनी हुई है, 22 देशों और क्षेत्रों को कवर करने वाले 16 भूख हॉटस्पॉट में खाद्य असुरक्षा बिगड़ रही है। संघर्ष और सशस्त्र हिंसा इन हॉटस्पॉट में भूख के प्राथमिक चालक बने हुए हैं, इसके बाद मौसम की चरम सीमा, आर्थिक असमानताएं और उच्च ऋण स्तर हैं। दुनिया 2030 तक शून्य भूख के लक्ष्य को प्राप्त करने से बहुत दूर है। विश्व बैंक के समग्र वस्तु मूल्य सूचकांक में 2025 में मुख्य रूप से आपूर्ति की स्थिति में सुधार और वैश्विक विकास में कमी के कारण 5 प्रतिशत की गिरावट का अनुमान है²।

वित्तीय स्थितियों में सुधार जारी रहने के बावजूद, वैश्विक वित्तीय बाजार मिश्रित संकेत दे रहे हैं। शेयर बाजार ट्रम्प के व्यापार में जीत की राह पर लौट आए - S&P 500 और डॉव जोन्स ने नवंबर के अंत तक रिकॉर्ड बनाए - लेकिन फेडरल मार्केट्स ओपन कमिटी (एफओएमसी) के आर्थिक अनुमानों के सारांश के जारी होने के बाद इसमें गिरावट देखी गई, जिसमें 2025 में पहले से कम अनुमानित दर कटौती की ओर इशारा किया गया था। बड़े राजकोषीय असंतुलन और मौद्रिक सहजता की गति में अनुमानित मंदी की संभावना के कारण बॉण्ड प्रतिफल में भी वृद्धि हुई है। नवंबर के अंत से, तुलनात्मक परिपक्वता के ट्रेजरी पर यूएस उच्च-प्रतिफल वाले बॉण्ड पर प्रसार पहली बार रिकॉर्ड निचले स्तर पर स्थिर-दर वाले आवासीय बंधक पर प्रसार से नीचे गिर गया, जो यूएस चुनावों के बाद जंक बॉण्ड बाजारों के उत्साहपूर्ण मूड को दर्शाता है। प्रतिफल की तलाश स्पष्ट रूप

* यह लेख माइकल देवब्रत पात्र, जीवी नथनेयल, श्रेया कंसल, दुर्गा जी, हर्षिता केशन, यामिनी झांब, हर्षेंद्र बेहरा, केएम नीलिमा, शेषाद्रि बनर्जी, अमित कुमार, जेसिका मारिया एंथनी, लव कुमार शांडिल्य, रागिनी, सिद्धार्थ आर्य, अमृता बसु, आयुषी खंडेलवाल, श्रीतमा रे, शिवम, शुभम अग्निहोत्री, मयंक शंकर दयाल राय, लाल बहादुर सिंह, साई धीरज वायुगुंडला चेंबू, सत्यम कुमार, अवनीश कुमार, खुशी सिन्हा, युवराज कश्यप, निखिल प्रकाश कोसे, अक्षरा अवरस्थी, आशीष थॉमस जॉर्ज, समीर रंजन बेहरा, विनीत कुमार श्रीवास्तव और रेखा मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। इस आलेख में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं और भारतीय रिजर्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

¹ ओईसीडी, आर्थिक दृष्टिकोण, दिसंबर 2024।

² विश्व बैंक द्वारा वस्तु मूल्य अनुमान।

से भीड़ में बदल रही है। उभरते बाजार के उच्च-प्रतिफल वाले सॉवरेन डॉलर ऋण में उछाल आया है, भले ही उभरते बाजार के शेयर यूएस इक्विटी के सापेक्ष कम कारोबार कर रहे हों क्योंकि यूएस के लिए पोर्टफोलियो प्रवाह भगदड़ मचा रहा है। दूसरी ओर, चीन के दीर्घकालिक बॉण्ड प्रतिफल जापानीकरण से जूझ रहे हैं क्योंकि वे जापानी प्रतिफल से नीचे गिर गए हैं, जिसका वित्तीय स्थिरता पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। अमेरिकी डॉलर भी मजबूत हो रहा है, एफओएमसी के बयान के बाद 19 दिसंबर को डीएसवीआई के लिए 108 से ऊपर टूट गया। इसी तरह, अन्य सभी मुद्राओं पर लगातार नीचे की ओर दबाव उन्हें नए निचले स्तर पर ले जा रहा है क्योंकि वे आने वाले अमेरिकी प्रशासन से निकलने वाले व्यापारिक बयानबाजी के कारण होने वाले गिरावट को संतुलित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी अपने नेता और सरकार चुनने में जुट गई है, ऐसे में वैश्विक अर्थव्यवस्था जो अभी भी मजबूत है, वह संरक्षणवाद के मुहाने पर खड़ी दिखाई दे रही है, जो आर्थिक गतिविधि, व्यापार, अप्रवास से लेकर भूराजनीति तक हर चीज़ को फिर से संगठित करेगी और महामारी के बाद प्रति व्यक्ति आय में सुधार के रास्ते में देशों के बीच मतभेदों को और बढ़ाएगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के अनुसार, अगर दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापक व्यापार युद्ध होता है, तो विश्व अर्थव्यवस्था संयुक्त फ्रांसीसी और जर्मन अर्थव्यवस्थाओं के आकार तक सिकुड़ सकती है, जिससे विश्व जीडीपी को लगभग 7 प्रतिशत का नुकसान होगा।³ इलेक्ट्रिक वाहन पहले ही तनाव का विषय बन चुके हैं। मुद्राओं के इंजीनियर्ड अवमूल्यन, आपूर्ति श्रृंखलाओं और महत्वपूर्ण सामग्रियों को फिर से स्थापित करने में राष्ट्रीय स्वार्थ, टैरिफ से प्रभावित देशों द्वारा अपनी कंपनियों को विदेश ले जाना और वित्त की दुनिया में दरार के रूप में व्यापक स्पिलओवर हो सकते हैं। वैश्विक सार्वजनिक ऋण 'उच्च, बढ़ता हुआ और जोखिम भरा' होने के कारण,⁴ राजकोषीय दबाव 2025 में वैश्विक विकास संभावनाओं को कमजोर कर सकता है, जिसकी शुरुआत विकसित देशों से होगी। आईएमएफ के वैश्विक ऋण डेटाबेस के अनुसार, इसके प्रति उत्तर में, परिवार और व्यवसाय

निजी ऋण का भुगतान करने का विकल्प चुन रहे हैं। मुद्रास्फीति 2024 में एक तरह से आ गई और 2025 में भी जारी रहेगी, लेकिन गहरी मंदी के भयावह पूर्वानुमान नहीं हैं। ओईसीडी के अनुसार, उपभोक्ता विश्वास अन्य वस्तुओं की तुलना में खाद्य और ऊर्जा मूल्य मुद्रास्फीति के प्रति अधिक संवेदनशील है, क्योंकि महामारी की शुरुआत के बाद से खाद्य और ऊर्जा मूल्य मुद्रास्फीति ने नाममात्र घरेलू डिस्पोजेबल आय में वृद्धि को पीछे छोड़ दिया है। श्रम बाजार की स्थिति आसान हो रही है, लेकिन वैश्विक अर्थव्यवस्था के एक बड़े हिस्से में कटौती चक्र शुरू होने के बावजूद ब्याज दरें ऊंची बनी हुई हैं। शायद 2025 में वे पूरी तरह से सामान्य हो जाएँ, लेकिन वे किस स्तर पर स्थिर होंगी, यह सवाल है। ब्याज की प्राकृतिक दरें या आर स्टार कई भौगोलिक क्षेत्रों में बढ़ी हुई प्रतीत होती हैं, जो समग्र नीति अनिश्चितता को दर्शाती हैं।

2035 तक विकासशील देशों में जलवायु कार्रवाई परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए प्रति वर्ष 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर सीओपी29 एक नए जलवायु वित्त लक्ष्य - न्यू क्लेक्टिव क्वांटिफाइड गोल (एनसीक्यूजी) के साथ समाप्त हुआ। यह बहुत कम था, विकासशील देशों की 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की मांग के एक चौथाई से भी कम। भारत ने इसे 'ऑप्टिकल इल्यूजन' कहा। दुनिया भर में विनाशकारी मौसम से उत्पन्न गर्मी के कारण, जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने और स्वच्छ ऊर्जा में बदलाव करने के लिए गरीब देशों द्वारा किए गए खर्च का केवल एक अंश ही कवर किया जाएगा। उन्हें निजी पूंजी भागीदारी को अधिकतम करने के लिए गारंटी और सस्ती मुद्रा हेजिंग सुविधाओं जैसे उपायों के माध्यम से निवेश को जोखिम मुक्त करने के लिए इस अल्पकालिक वित्त सौदे के प्रभाव को अधिकतम करना होगा। नए उपायों में कार्बन बाजारों का संचालन, प्रकृति के लिए ऋण स्वैप और बहुपक्षीय वित्तीय सहायता भी शामिल हो सकती है। वास्तव में, देशों ने सीओपी29 में अंतर्राष्ट्रीय कार्बन व्यापार पर एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया है, जो देश-दर-देश व्यापार, संयुक्त राष्ट्र द्वारा निगरानी किए जाने वाले कार्बन बाजार और गैर-बाजार तंत्रों का प्रावधान करता है, जिसे अनुच्छेद 6 के रूप में संदर्भित किया जाता है। यह औद्योगिक देशों को विकासशील देशों से कार्बन-कटिंग ऑफसेट खरीदने की अनुमति देगा, जिससे वित्त को अनलॉक किया जा सकेगा। हालांकि, उत्सर्जन में कमी के

³ आईएमएफ की पहली डीएमडी गीता गोपीनाथ बीबीसी से, 24 अक्टूबर, 2024।

⁴ आईएमएफ ब्लॉग, निजी उधार में लगातार गिरावट से वैश्विक ऋण में कमी आएगी, 2 दिसंबर, 2024।

ग्रीनवाशिंग की संभावना और प्रकटीकरण में कमियों को सुधारने के लिए समय सीमा की अनुपस्थिति के बारे में चिंताएं मौजूद हैं।

नुकसान और क्षति के लिए प्रतिक्रिया कोष हेतु एक दीर्घकालिक संधारणीय संसाधन रणनीति की भी आवश्यकता है, जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से होने वाले नुकसान की भरपाई करना है। कोष के लिए संचयी प्रतिबद्धताएं आवश्यकता का लगभग 0.25 प्रतिशत हैं। विकासशील देशों को भी जोखिम कम करने वाली क्षेत्रीय नीतियों, उचित वर्गीकरण और जलवायु-संबंधी प्रकटीकरणों के माध्यम से निवेशकों के लिए सक्षम वातावरण बनाकर हाउसकीपिंग में संलग्न होना चाहिए। इसके अलावा, जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए नए और बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी समाधान हैं, जिनके बिना अकेले वित्त केवल उप-इष्टतम समाधानों की ओर ले जा सकता है। इसलिए, बातचीत को जलवायु प्रौद्योगिकी में नवाचारों तक व्यापक किया जाना चाहिए - जब कोई नई स्केलेबल तकनीक उभरती है, तो यह पूरे उद्योगों की मूल्य श्रृंखला को बदल देती है और अपनाने की लागत को उत्तरोत्तर कम करती है। सबसे स्पष्ट उदाहरण फोटोवोल्टिक सेल्स और ईवी को वैश्विक रूप से अपनाना है।

जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए अक्षय ऊर्जा में बदलाव बहुत ज़रूरी है। 2015 में पेरिस समझौते को अपनाने के बाद से अक्षय ऊर्जा में अंतर्राष्ट्रीय निवेश लगभग तीन गुना हो गया है। हालाँकि, विकासशील देशों को वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा निवेश का केवल पाँचवाँ हिस्सा ही मिला है। फिर भी, वैश्विक बिजली उत्पादन में अक्षय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ रही है, जिसमें भारत सबसे आगे है। जबकि प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत प्रचुर मात्रा में हैं, वे दुनिया भर में समान रूप से वितरित नहीं हैं। यह अक्षय ऊर्जा में सीमा पार व्यापार के महत्व को उजागर करता है। सीमाओं के पार अक्षय ऊर्जा का संचरण आपूर्ति-मांग के अंतर को दूर करने में मदद कर सकता है। भंडारण समाधान राष्ट्रों की अकार्बनीकरण प्रतिबद्धताओं को पूरा करके बेहतर ग्रिड उपयोग और नए व्यापार अवसरों के साथ-साथ ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा में योगदान दे सकते हैं। अक्षय ऊर्जा में व्यापार वैश्विक ऊर्जा संक्रमण की कुल लागत को भी कम करेगा। विश्व व्यापार संगठन और विश्व मौसम विज्ञान संगठन जैसी बहुपक्षीय एजेंसियों की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है।

भारत के लिए, नवंबर में जारी 2024-25 की दूसरी तिमाही के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) / सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) और मुख्य उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति के अनुमानों ने अर्थव्यवस्था की स्थिति के नवंबर अंक में की गई आशंकाओं की पुष्टि की है, जो धीमी विकास-उच्च मुद्रास्फीति पहली की दुविधा को दोहराती है। जैसा कि दूरदर्शिता से बताया गया है, व्यय पक्ष से, अर्थव्यवस्था की विकास दर में गिरावट में योगदान देने वाला प्रमुख कारक निश्चित पूंजी निर्माण है। उत्पादन पक्ष से, मुख्य चिंता विनिर्माण है।⁵ दोनों को कमजोर करने वाली मुद्रास्फीति है। बार-बार मुद्रास्फीति के आघातों और लगातार मूल्यगत दबावों के कारण क्रय शक्ति का क्षरण सूचीबद्ध गैर-वित्तीय गैर-सरकारी निगमों की बिक्री वृद्धि को कमजोर करने में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। मांग की स्थिति पर उनका दृष्टिकोण भी मंद बना हुआ है क्योंकि मूल्यगत आघातों की घटनाओं में कोई कमी नहीं दिख रही है; वे तेजी से इनपुट लागत को बिक्री मूल्यों पर डालने के लिए इच्छुक होंगे। परिणामतः, अचल संपत्तियों में निवेश करके कोई मजबूत क्षमता निर्माण नहीं होता है। इसके बजाय, निगम मुद्रास्फीति से प्रभावित उपभोक्ता मांग को पूरा करने के लिए मौजूदा क्षमता का उपयोग कर रहे हैं। इसका परिणाम सुस्त निजी निवेश है। उपभोक्ता मांग में मंदी धीमी कॉरपोरेट वेतन वृद्धि से जुड़ी हुई प्रतीत होती है। एक और बाधा जो उभर रही है वह है नाममात्र जीडीपी की धीमी दर, जो बजटीय घाटे और ऋण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूंजीगत व्यय सहित राजकोषीय व्यय में बाधा डाल सकती है। जैसा कि हमने नवंबर में बताया था, अगर मुद्रास्फीति को अनियंत्रित रूप से बढ़ने दिया जाता है, तो यह वास्तविक अर्थव्यवस्था, विशेष रूप से उद्योग और निर्यात की संभावनाओं को कमजोर कर सकता है।

अब मुद्रास्फीति को कम करने और निवेश को मजबूती से पुनर्जीवित करने के लिए कार्य करने का समय आ गया है, खासकर तब जब सर्दियों में खाद्य कीमतों में सामान्य कमी आ रही है और निजी खपत और निर्यात में तेजी की संभावनाएं उज्ज्वल हो रही हैं। कृषि और इसलिए ग्रामीण खपत की संभावनाएं निश्चित रूप से बेहतर दिख रही हैं, खरीफ की फसल का एक बड़ा हिस्सा तीसरी

⁵ रंगराजन सी. और डी.के. श्रीवास्तव, दूसरी तिमाही की वृद्धि में गिरावट के निहितांश।

तिमाही के जीडीपी के अनुमानों में दिखाई देने की संभावना है और भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा पूर्वानुमानित सामान्य से अधिक गर्म सर्दियों से पहले खरी की बुवाई में तेजी से विस्तार होगा। ई-नाम प्लेटफॉर्म पर कृषि वस्तुओं के व्यापार को खोलने और सुविधाजनक बनाने वाले राज्यों की संख्या बढ़ रही है। प्लेटफॉर्म पर अंतर-मंडी और अंतर-राज्य व्यापार में तेजी से किसानों को बेहतर मूल्य मिल रहा है। सेवा गतिविधि सुदृढ़ बनी हुई है; विशेष रूप से होटलों में महीने-दर-महीने (माह दर माह) सुधार देखने को मिल रहा है और जैसे-जैसे विदेशी पर्यटक आ रहे हैं, उन्हें इस वित्तीय वर्ष में पूरी तरह सुधार की उम्मीद है।

खपत के मोर्चे पर, एफएमसीजी कंपनियों ने खाद्य मुद्रास्फीति की चिंताओं पर शहरी सुस्ती को मांग में कमी का कारण बताया और उनका मानना है कि मंदी का दौर खत्म हो चुका है और यह स्थिर हो रहा है क्योंकि यह ऊपर की ओर बढ़ने का इंतजार कर रहा है। इसलिए, वे अपने सबसे बड़े वितरण चैनल, यानी सामान्य व्यापार को पुनर्जीवित करने के लिए क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी को बढ़ावा देना चाह रहे हैं, साथ ही कम इन्वेंट्री और बेहतर सर्विसिंग के रूप में समर्थन भी दे रहे हैं। इस बीच, वे भारी छूट और प्रिडेटरी मूल्य निर्धारण के लिए क्विक कॉमर्स कंपनियों द्वारा निधि जुटाने पर भी सवाल उठा रहे हैं। कुल मिलाकर, भारतीय उपभोक्ता दैनिक आवश्यक वस्तुओं के लिए क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म को पसंद कर रहे हैं, लेकिन उच्च मूल्य की खरीदारी के लिए इन-स्टोर खरीदारी करना जारी रखते हैं। 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक अमेरिका से आयातित ब्लैक फ्राइडे ने इस साल लोकप्रियता हासिल की।

खपत के लिए सकारात्मकता उन रिपोर्टों में भी दिखाई देती है, जिनमें नई नियुक्तियों में तेजी को दर्शाया गया है, जो संभवतः लॉजिस्टिक्स, ईवी और ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि और कृषि रसायन, और ई-कॉमर्स जैसे क्षेत्रों द्वारा संचालित है।⁶ नौकरी बाजार में भौगोलिक बदलाव चल रहा है। कोयंबटूर और गुडगांव जैसे शहर नौकरी के केंद्र बन रहे हैं, जो महानगरों से परे रोजगार के अवसरों के विकेंद्रीकरण का प्रतिनिधित्व करते हैं। संविदात्मक

स्टाफिंग या अस्थायी भर्ती में उल्लेखनीय वृद्धि देखी जा रही है, जिसमें आईटी पेशेवर भी शामिल हैं।⁷ गिग इकोनॉमी से 2024 में 90 मिलियन नौकरियां जुड़ने की उम्मीद है।⁸ वैश्विक क्षमता केंद्र तेजी से प्रौद्योगिकी और अनुसंधान और विकास में उच्च कौशल वाली नौकरियां पैदा कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर मिशन 1.25 लाख करोड़ रुपये के निवेश के माध्यम से 2025 तक 80,000 नौकरियां जोड़ने का लक्ष्य रखता है।

घरेलू वित्तीय बाजारों ने नवंबर के अंत और दिसंबर की शुरुआत में अमेरिकी चुनावों के प्रतिकूल प्रभावों को नजरअंदाज कर दिया, हालांकि अमेरिकी डॉलर में उछाल और लगातार मुद्रास्फीति के कारण अमेरिकी बॉण्ड प्रतिफल में मजबूती आई। घरेलू इक्विटी ने 22 नवंबर को पांच महीने से अधिक समय में सर्वश्रेष्ठ एकल-दिवसीय उछाल दर्ज किया। हालांकि, बाजारों ने बाद में लाभ का कुछ हिस्सा कम कर दिया क्योंकि वैश्विक मौद्रिक नीति अनिश्चितता और अमेरिकी डॉलर के निरंतर सख्त होने से ईएमई में भावनाओं पर असर पड़ा। भारत की अस्थिरता सूचकांक (VIX) सीमित दायरे में रहा, लेकिन बाजारों को लंबी अवधि के समर्थन के लिए आय वृद्धि की आवश्यकता होगी। बाजार की धारणा में गिरावट के बीच नवंबर में अधिकांश आरंभिक सार्वजनिक प्रस्तावों (आईपीओ) ने मामूली लिस्टिंग प्रतिलाभ दर्ज किया। हालांकि, दिसंबर में प्राथमिक बाजार गतिविधि ने गति पकड़ी। योग्य संस्थागत प्लेसमेंट रूट के माध्यम से निधि उगाहना कैलेंडर वर्ष 2024 में अब तक ₹1 ट्रिलियन को पार कर गया, जो इसके इतिहास में सबसे अधिक है। 2024 के पहले दस महीनों में वेंचर कैपिटल फंडिंग 44 फीसदी बढ़कर 9.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई।⁹ ऋण बाजार में, सूक्ष्म-वित्त क्षेत्र ने सितंबर तिमाही में बढ़ती गिरावट के साथ आसित की गुणवत्ता में गिरावट देखी। दूसरी ओर, इसी तिमाही के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) द्वारा प्रावधान में कमी आई। निजी बैंकों ने प्रावधान में वृद्धि दर्ज की, लेकिन आय के मोर्चे पर पीएसबी की

⁷ “जब भारतीय कंपनियों में अस्थायी भर्ती एक स्थायी व्यवस्था बन जाती है”, मिंट।

⁸ प्रगतिशील गिग वर्कर्स के लिए फोरम, काम के भविष्य को आकार देना: भारत की गिग अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना, बिजनेस स्टैंडर्ड।

⁹ ग्लोबलडाटा डील्स डेटाबेस।

⁶ टीमलीज रोजगार आउटलुक रिपोर्ट H2 FY25.

तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया। कुल मिलाकर, उच्च गैर-ब्याज आय और बेहतर वसूली ने निवल लाभ को बढ़ावा दिया। बड़े बैंकों द्वारा जारी किए गए जमा प्रमाणपत्रों (सीडी) पर दरों में ढील देने से छोटे साधियों द्वारा जुटाई गई निधियों की लागत भी कम हो रही है। भारतीय रुपया मजबूत अमेरिकी डॉलर और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के निवल विक्रेता बने रहने से दबाव में रहा है।

इस पृष्ठभूमि में, लेख का शेष भाग चार खंडों में संरचित है। खंड II में वैश्विक अर्थव्यवस्था में तेजी से विकसित हो रहे घटनाक्रमों को शामिल किया गया है। खंड III में घरेलू समष्टि आर्थिक स्थितियों का आकलन किया गया है। खंड IV में भारत की वित्तीय स्थितियों का सार प्रस्तुत किया गया है, जबकि अंतिम खंड में निष्कर्ष स्वरूप टिप्पणियाँ दी गई हैं।

II. वैश्विक स्थिति

आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) ने दिसंबर 2024 के अपने आर्थिक परिदृश्य में 2024 के लिए वैश्विक विकास पूर्वानुमान को 3.2 प्रतिशत पर बरकरार रखा और 2025 के अनुमान को 10 आधार अंक (बीपीएस) बढ़ाकर 3.3 प्रतिशत कर दिया, जो अमेरिका, यूके जैसी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (ईई) और चीन तथा भारत जैसी उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में सुधार को दर्शाता है (सारणी II.1)। जी20 अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति 2024 में 5.4 प्रतिशत से घटकर 2025 में 3.5 प्रतिशत और 2026 में 2.9 प्रतिशत होने की उम्मीद है। यह मौद्रिक नीति सामान्यीकरण के लिए संभावना उत्पन्न कर सकता है, हालांकि भू-राजनीतिक जोखिम, व्यापार नीति अनिश्चितता, वित्तीय कमजोरियों के बीच राजकोषीय और मुद्रा दबाव नकारात्मक जोखिम पैदा करना जारी रखते हैं।

वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का हमारा मॉडल-आधारित पूर्वानुमान 2024 की चौथी तिमाही में वैश्विक विकास की गति में नरमी की ओर इशारा करता है (चार्ट II.1)।

वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला दबाव सूचकांक (जीएससीपीआई) नवंबर 2024 में लगातार दूसरे महीने स्थिर रहा, जो इसके ऐतिहासिक औसत से नीचे है (चार्ट II.2ए)। मध्य पूर्व में चल रहे

सारणी II.1: जीडीपी विकास अनुमान – चुनिंदा आई और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएं (ईएमई)

(Per cent)

देश	2024		2025	
	दिसंबर 2024	सितंबर 2024	दिसंबर 2024	सितंबर 2024
 विश्व	3.2	3.2	3.3	3.2
विकसित अर्थव्यवस्था				
 यूएस	2.8	2.6	2.4	1.6
 यूके	0.9	1.1	1.7	1.2
 यूरो क्षेत्र	0.8	0.7	1.3	1.3
 जापान	-0.3	-0.1	1.5	1.4
उभरती हुई अर्थव्यवस्था				
 ब्राजील	3.2	2.9	2.3	2.6
 भारत*	6.8	6.7	6.9	6.8
 चीन	4.9	4.9	4.7	4.5
 दक्षिण अफ्रीका	1.0	1.0	1.5	1.4

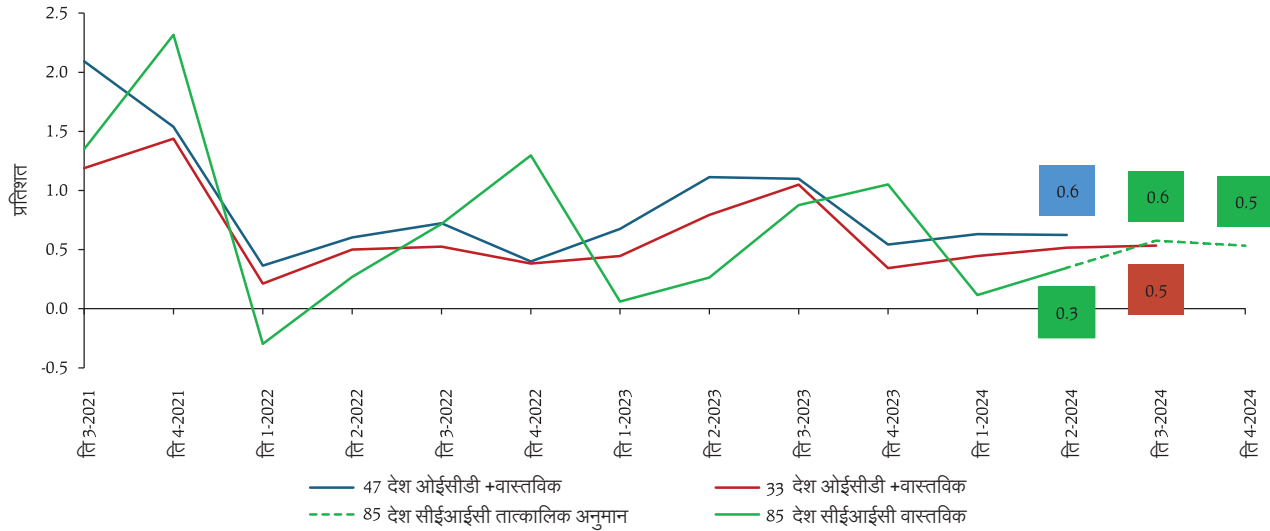
टिप्पणी: *, भारत के आंकड़े राजकोषीय वर्ष के आधार पर हैं।
स्रोत: ओईसीडी

तनाव के कारण भू-राजनीतिक जोखिम बढ़े हुए हैं, हालांकि नवंबर 2024 में इसमें कुछ कमी आएगी (चार्ट II.2बी)। सितंबर और अक्तूबर के दौरान कुछ राहत दिखाने के बाद, नवंबर से शिपिंग लागत में वृद्धि शुरू हो गई है (चार्ट II.2सी)।

यू.एस. और यू.के. में उपभोक्ता विश्वास में सुधार हुआ, लेकिन यूरो क्षेत्र¹⁰ में स्थिति खराब हो गई (चार्ट II.3ए)। आई और ईएमई पर उच्च आवृत्ति डेटा ने नवंबर में वित्तीय स्थितियों में सहजता का संकेत दिया (चार्ट II.3बी)।

वैश्विक समग्र क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) नवंबर में तीन महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, जिसने लगातार तेरहवें महीने वृद्धि दर्ज की। यह तेजी मुख्य रूप से सेवा क्षेत्र द्वारा

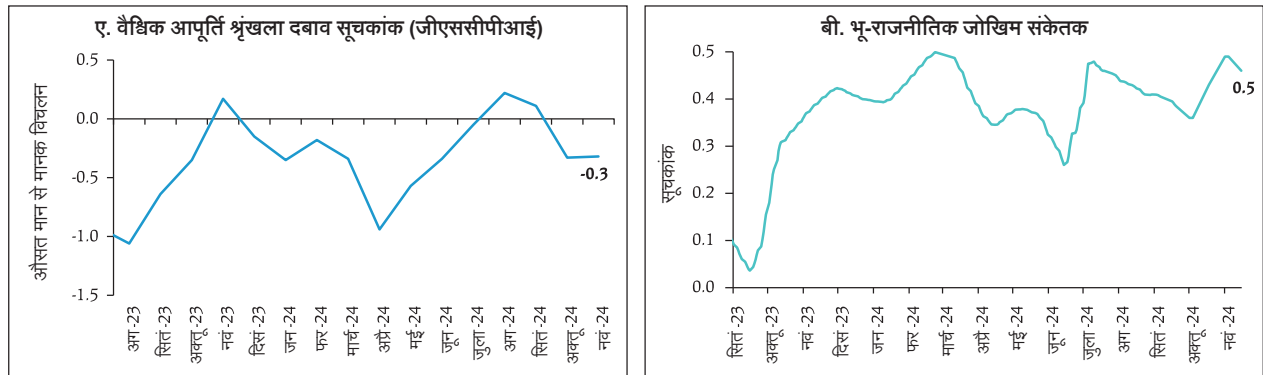
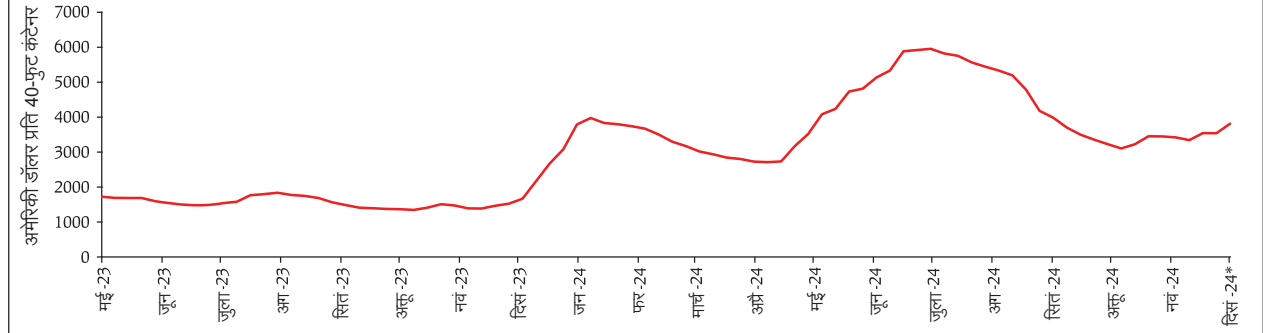
¹⁰ आर्थिक और वित्तीय मामलों के महानिदेशालय (डीजी ईसीएफआईएन), यूरोपीय आयोग सेवाओं द्वारा दिसंबर 2024 यूरो क्षेत्र सीसीआई के लिए फ्लैश अनुमान।

चार्ट II.1: वैश्विक जीडीपी तात्कालिक अनुमान (तिमाही दर तिमाही)


स्रोत: सीईआईसी, ओईसीडी और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

संचालित थी, जो नवंबर में लगातार बाईसवें महीने विस्तार क्षेत्र में रहा। विशेष रूप से, उपभोक्ता सेवा गतिविधि में और विस्तार

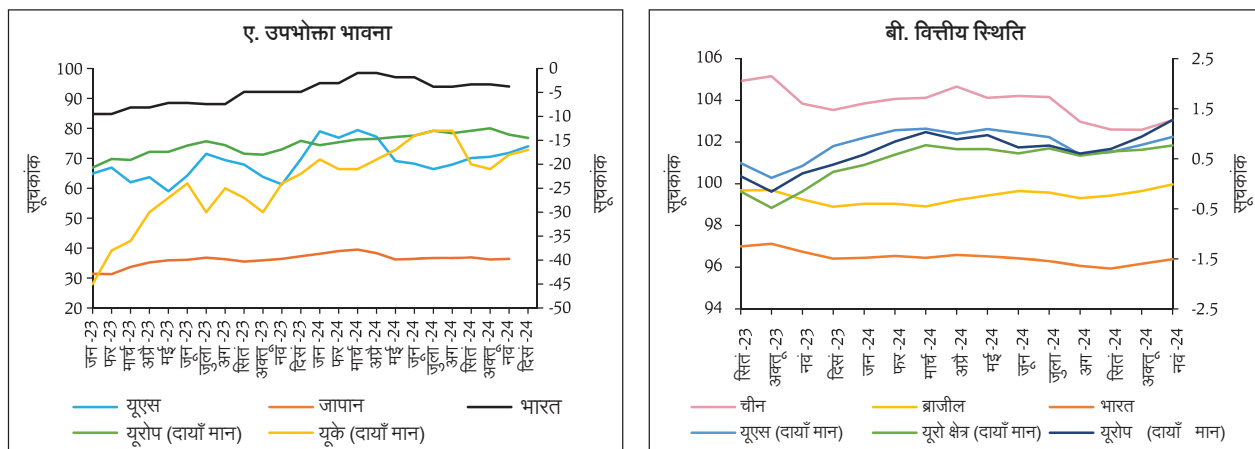
हुआ, जिसने विनिर्माण के तुलनात्मक रूप से फीके प्रदर्शन की भरपाई की। वैश्विक विनिर्माण पीएमआई, चार महीने के संकुचन

चार्ट II.2: वैश्विक आपूर्ति शृंखला दबाव और भू-राजनीतिक जोखिमों में रुझान

सी. ड्रयूरी वर्ल्ड कंटेनर इंडेक्स (डब्ल्यूसीआई)


टिप्पणियाँ : 1. जीएससीपीआई परिवहन लागत और विनिर्माण संकेतकों पर डेटा दर्शाता है।
2. ड्रयूरी द्वारा साप्ताहिक रूप से मूल्यांकन किया गया डब्ल्यूसीआई प्रमुख पूर्व-पश्चिम व्यापार मार्गों के लिए वास्तविक स्पॉट कंटेनर माल ढुलाई दरों की रिपोर्ट करता है। यह समग्र मार्गा के आधार पर 8 शिपिंग मार्गों की भारत औसत का प्रतिनिधित्व करता है तथा प्रति 40-फुट कंटेनर की रिपोर्ट अमेरिकी डॉलर में की जाती है।
3. *: 19 दिसंबर तक के आंकड़े हैं।

स्रोत : फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क; ब्लैकरोक इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट, नवंबर 2024; और ब्लूमबर्ग।

चार्ट II.3: उपभोक्ता भावना और वित्तीय स्थिति



टिप्पणियाँ: 1. जापान: 50 से ऊपर का स्कोर उपभोक्ता आशावाद को दर्शाता है, 50 से नीचे का स्कोर उपभोक्ता विश्वास की कमी को दर्शाता है और 50 तटस्थता को दर्शाता है।
2. यूरो ज़ोन और यूके: -100 अत्यधिक अविश्वास को दर्शाता है, 0 तटस्थता को दर्शाता है जबकि 100 अत्यधिक आत्मविश्वास को दर्शाता है।
3. भारत और अमेरिका: सूचकांक मूल्य जितना अधिक होगा, उपभोक्ता विश्वास भी उतना ही अधिक होगा।
4. वित्तीय स्थिति सूचकांक (गोल्डमैन सैक्स द्वारा निर्मित ईएमई से संबंधित) के लिए, 100 से नीचे का रीडिंग समायोजनात्मक है और इसके विपरीत। ईई के लिए, ब्लूमबर्ग द्वारा तैयार सूचकांक एक जेड-स्कोर है जहाँ एक सकारात्मक मूल्य समायोजनात्मक/आसान वित्तीय स्थितियों को इंगित करता है और इसके विपरीत।

स्रोत: ब्लूमबर्ग।

के बाद नवंबर में क्रमिक रूप से बढ़कर 50 के तटस्थ निशान पर पहुंच गया (चार्ट II.4)।

सभी क्षेत्रों में, भारत के नेतृत्व में उभरती अर्थव्यवस्थाओं ने मजबूत विस्तार जारी रखा, जबकि जर्मनी और फ्रांस जैसी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में संकुचन दर्ज किया गया (चार्ट II.5)।

निर्यात ऑर्डर के लिए समग्र पीएमआई जून 2024 से संकुचन क्षेत्र में रहा क्योंकि कमजोर विनिर्माण निर्यात ने सेवा

ऑर्डर में वृद्धि को ऑफसेट करना जारी रखा। हालांकि, नवंबर में विनिर्माण और सेवा दोनों क्षेत्रों में निर्यात ऑर्डर में क्रमिक वृद्धि दर्ज की गई (चार्ट II.6)।

नवंबर में वैश्विक पण्य की कीमतों में अलग-अलग उतार-चढ़ाव दर्ज किए गए क्योंकि ऊर्जा और कृषि पण्य की कीमतों में बढ़ोतरी की भरपाई धातु की कीमतों में गिरावट से हुई। ब्लूमबर्ग

चार्ट II.4: वैश्विक पीएमआई



नोट: 50 का स्तर गतिविधि में कोई बदलाव नहीं करता है और 50 से ऊपर की रीडिंग विस्तार और इसके विपरीत को दर्शाती है।

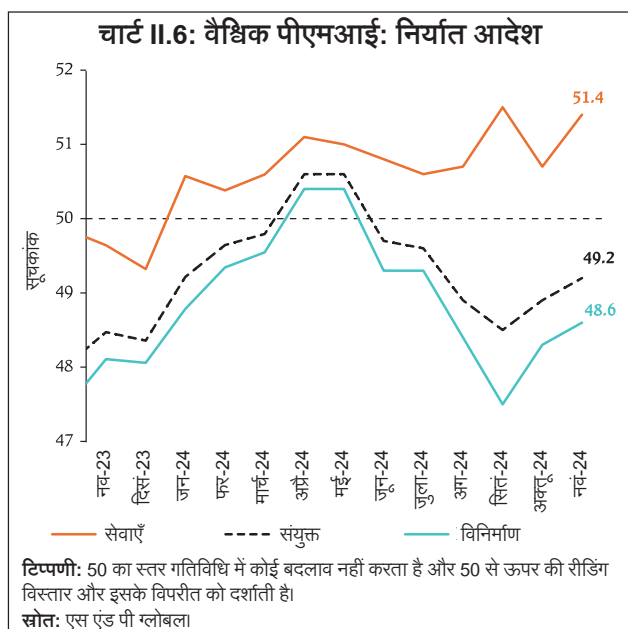
स्रोत: एस&पी ग्लोबल।

चार्ट II.5: एस&एंडपी वैश्विक संयुक्त पीएमआई का क्षेत्रवार तुलना



टिप्पणी: 50 का स्तर गतिविधि में कोई परिवर्तन नहीं होने को दर्शाता है तथा 50 से ऊपर का स्तर विस्तार को दर्शाता है और इसके विपरीत।

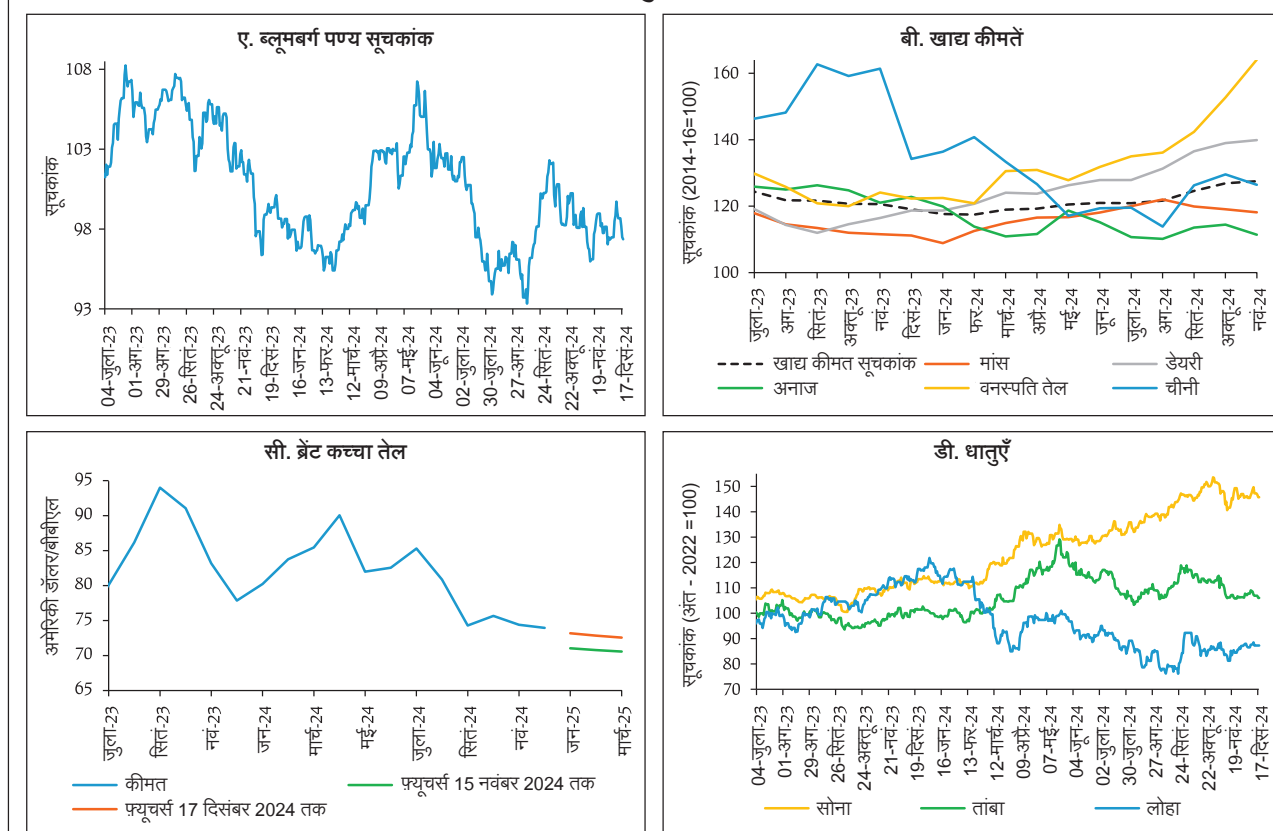
स्रोत: एस एंड पी ग्लोबल।



पण्य सूचकांक नवंबर में अस्थिर रहा, पहले पखवाड़े में गिरावट के बाद दूसरे पखवाड़े में बढ़ोतरी हुई (चार्ट II.7ए)। खाद्य और

कृषि संगठन (एफएओ) के खाद्य मूल्य सूचकांक में नवंबर में 0.5 प्रतिशत (माह दर माह) की बढ़ोतरी हुई, जो मुख्य रूप से वनस्पति तेल (7.5 प्रतिशत) और डेयरी की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण हुई, जो आंशिक रूप से अनाज, चीनी और मांस की कीमतों में कमी से ऑफसेट हुई (चार्ट II.7बी)। भू - राजनीतिक घटनाक्रमों ने नवंबर में तेल की कीमतों को अस्थिर रखा है, मध्य पूर्व में युद्ध विराम ने नीचे की ओर दबाव डाला जबकि ईरान पर प्रतिबंधों के जोखिम ने समर्थन दिया। कुल मिलाकर, ओपेक प्लस द्वारा 2025 की पहली तिमाही में आपूर्ति में कटौती जारी रखने की अटकलों के बीच नवंबर में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतों में 1.3 प्रतिशत (माह दर माह) की वृद्धि हुई (चार्ट II.7सी)। नवंबर में धातु की कीमतों में गिरावट आई क्योंकि दुनिया में आधार धातुओं के सबसे बड़े उपभोक्ता चीन के लिए परिदृश्य अनिश्चित बना रहा। नवंबर के पहले पखवाड़े में सोने की कीमतों में गिरावट आई क्योंकि मजबूत अमेरिकी डॉलर ने निवेशकों के लिए अवसर लागत बढ़ा दी और

चार्ट II.7: पण्य वस्तु और खाद्यान कीमतें



स्रोत: ब्लूमबर्ग: विश्व बैंक पिक शीट: और एफएओ

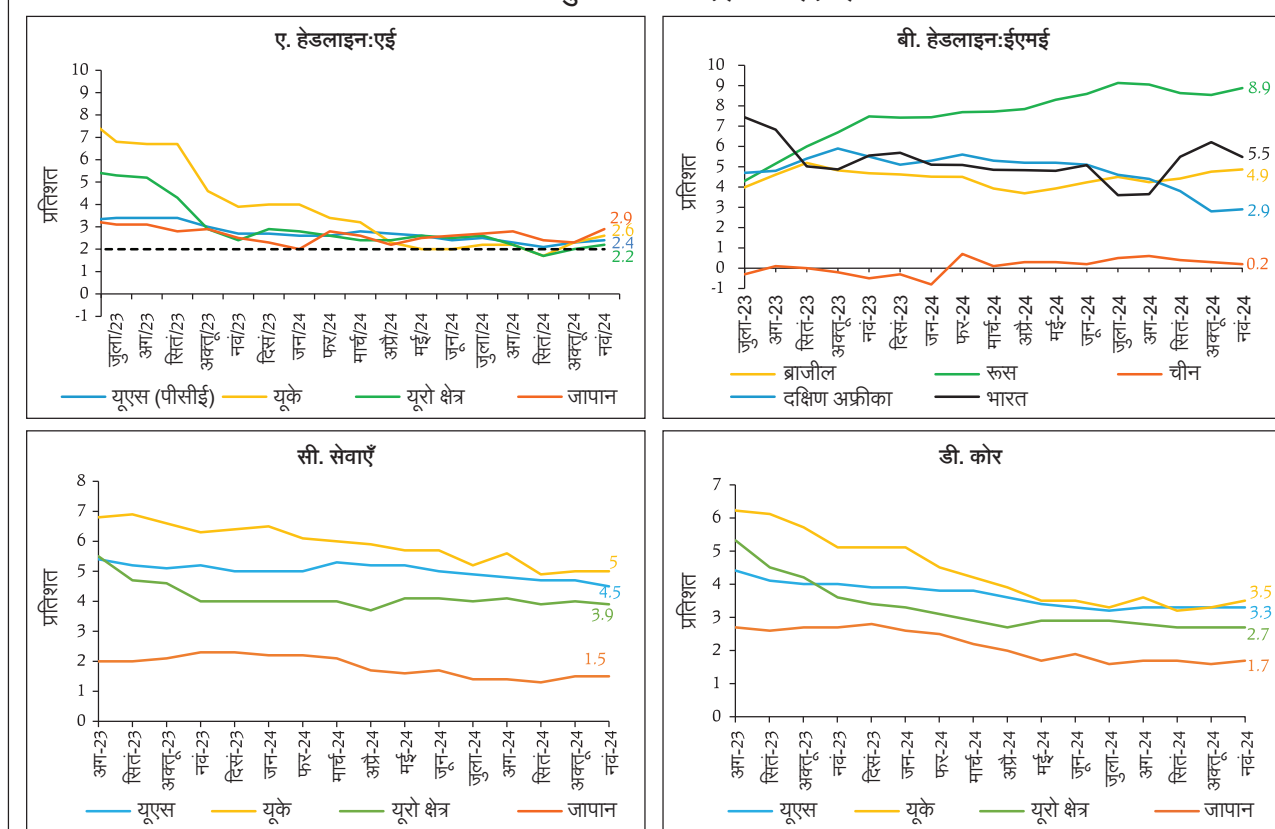
मध्य पूर्व में तनाव में आंशिक कमी ने सुरक्षित पनाहगाह की मांग को कम कर दिया। हालांकि, नवंबर के उत्तरार्ध और दिसंबर की शुरुआत में कीमतों में सुधार हुआ, क्योंकि अमेरिकी फेड द्वारा नीति में ढील की उम्मीद थी (चार्ट 11.7डी)।

हेडलाइन मुद्रास्फीति लक्ष्य के करीब घूमती रहती है, लेकिन सेवा क्षेत्र की मुद्रास्फीति के बीच कुछ प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के लिए उनसे ऊपर बनी हुई है। अमेरिका में, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति अक्तूबर में 2.6 प्रतिशत से नवंबर में बढ़कर 2.7 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) हो गई। व्यक्तिगत उपभोग व्यय (पीसीई) डिफ्लेटर के संदर्भ में मुद्रास्फीति भी अक्तूबर में 2.3 प्रतिशत से नवंबर में बढ़कर 2.4 प्रतिशत हो गई। यूरो क्षेत्र में हेडलाइन मुद्रास्फीति अक्तूबर में 2.0 प्रतिशत से नवंबर में 2.2 प्रतिशत हो गई और यूके में अक्तूबर में 2.3 प्रतिशत से नवंबर में 2.6 प्रतिशत हो गई। जापान में मुद्रास्फीति (ताजे भोजन को छोड़कर शेष सीपीआई) नवंबर में बढ़कर 2.9 प्रतिशत

हो गई (चार्ट 11.8ए)। ईएमई में, ब्राजील, रूस और दक्षिण अफ्रीका में मुद्रास्फीति बढ़ी, लेकिन नवंबर में चीन में नरमी आई (चार्ट 11.8बी)। अधिकांश उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में कोर और सेवा मुद्रास्फीति हेडलाइन से अधिक रही (चार्ट 11.8सी और 8डी)।

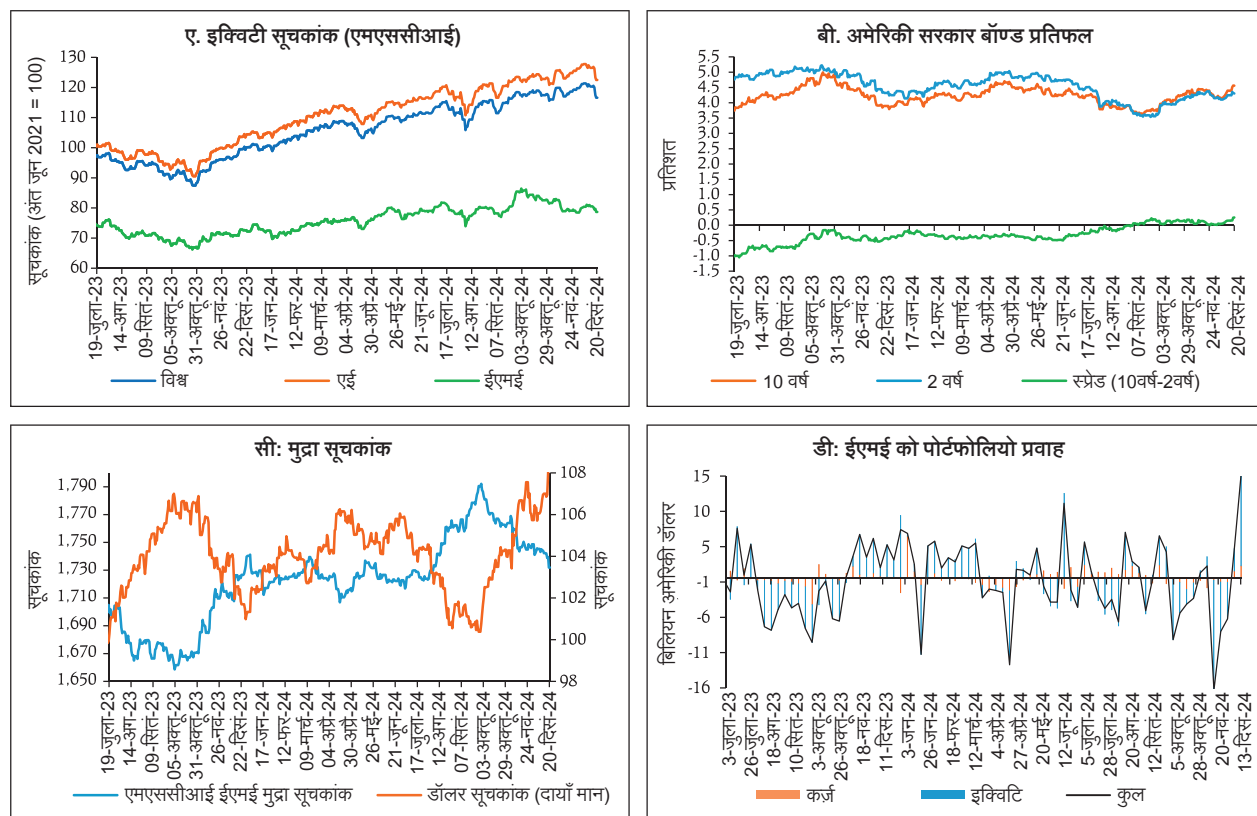
मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल (एमएससीआई) विश्व सूचकांक ने उन्नत अर्थव्यवस्थाओं, विशेष रूप से अमेरिका में इक्विटी बाजारों ने मजबूत उछाल दर्ज किए जाने के कारण नवंबर में 3.6 प्रतिशत (माह दर माह) की वृद्धि दर्ज की, जो कर कटौती की उम्मीदों के साथ-साथ आने वाले आंकड़ों से पता चला, जो लचीली आर्थिक गतिविधि की ओर इशारा करते थे (चार्ट 11.9ए)। हालांकि, नवंबर में एमएससीआई उभरते बाजार सूचकांक में 3.7 प्रतिशत की गिरावट आई, क्योंकि टैरिफ वृद्धि पर अटकलों ने जोर पकड़ लिया। दिसंबर में अब तक, एमएससीआई क्षेत्र ने गिरावट दर्ज की, जब उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय बैंकों ने अवस्फीति की गति धीमी होने के साथ आगे चलकर अपनी दर

चार्ट 11.8: मुद्रास्फीति – ई और ईएमई



स्रोत: ब्लूमबर्ग और ओईसीडी।

चार्ट II.9: वैश्विक वित्तीय बाजार



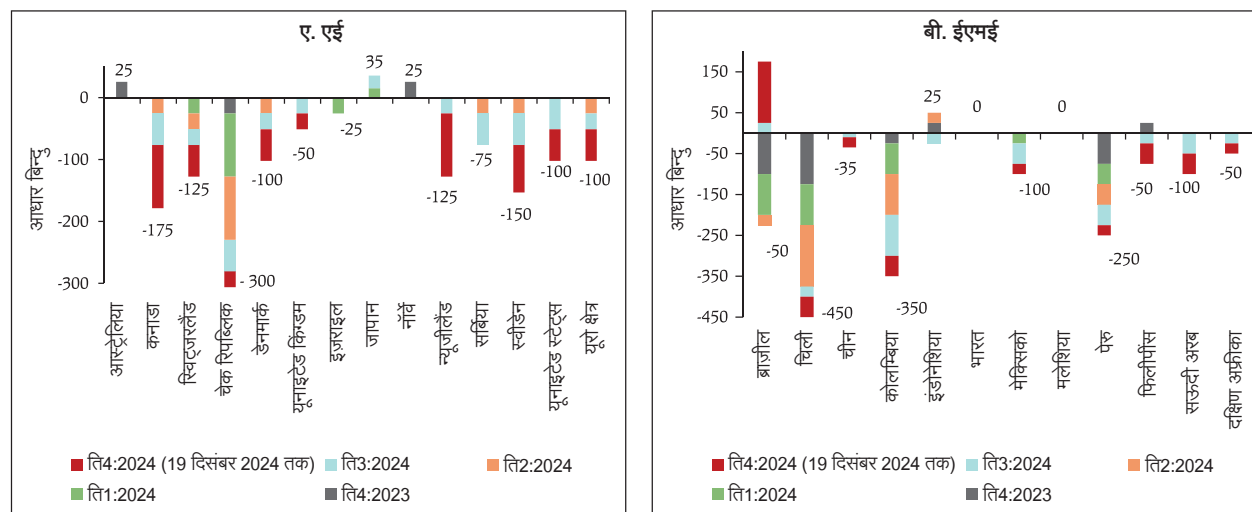
स्रोत: ब्लूमबर्ग और आईआईपी।

कटौती में अधिक सावधानी बरतने का संकेत दिया। नवंबर में 10-वर्ष और 2-वर्ष के बॉण्ड दोनों के लिए अमेरिकी सरकार की प्रतिभूतियों का प्रतिफल क्रमशः 12 बीपीएस और 2 बीपीएस कम हुआ (चार्ट II.9बी)। हालांकि, दिसंबर में प्रतिफल में मजबूती आई और यूएस 10-वर्षीय खजाना प्रतिफल मई 2024 के बाद के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई, साथ ही प्रतिफल वक्र में भी तेजी आई, क्योंकि एफओएमसी के आर्थिक अनुमानों के सारांश ने 2025 में ब्याज दरों में कटौती की अनुमानित गति से धीमी गति का संकेत दिया। अमेरिकी जीडीपी डेटा और अमेरिकी चुनाव परिणामों के चलते नवंबर में अमेरिकी डॉलर में 1.7 प्रतिशत (माह दर माह) की मजबूती आई। दिसंबर में यह उछाल जारी रहा क्योंकि फेड के डॉट प्लॉट ने उनके मध्य प्रक्षेपण के माध्यम से रेखांकित किया, 2025 के अंत तक पहले से अनुमानित मुद्रास्फीति और नीति दरों की तुलना में अधिक मजबूत अमेरिकी अर्थव्यवस्था रही। सहवर्ती रूप से, ईएमई के लिए एमएससीआई मुद्रा सूचकांक

नवंबर और दिसंबर में लगभग 1 प्रतिशत कम हुआ (चार्ट II.9सी और II.9डी)।

एई केंद्रीय बैंकों में, यूएस फेडरल रिजर्व ने 18 दिसंबर, 2024 को संघीय निधि दर के लिए लक्ष्य सीमा को 25 बीपीएस से घटाकर 4.25-4.50 प्रतिशत करने का फैसला किया और संकेत दिया कि संघीय निधि दर के लिए लक्ष्य सीमा में आगे समायोजन की सीमा और समय आने वाले डेटा, विकसित दृष्टिकोण और जोखिमों के संतुलन के सावधानीपूर्वक आकलन पर आधारित होगा। इसीबी ने दिसंबर में अपनी नीति दर में 25 बीपीएस की कटौती की और कनाडा और स्विट्जरलैंड ने अपनी बेंचमार्क दरों में 50-50 बीपीएस की कमी की, जबकि यूके, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने अपनी नीति दरों को अपरिवर्तित रखा (चार्ट II.10 ए)। दक्षिण कोरिया और चेक गणराज्य ने नवंबर में अपनी नीति दर में 25 बीपीएस की कमी की थी। ईएमई केंद्रीय बैंकों में, दक्षिण अफ्रीका ने नवंबर में अपनी नीतिगत दरों में 25 बीपीएस

चार्ट II.10: मौद्रिक दरों में परिवर्तन



स्रोत: ब्लूमबर्ग।

की कटौती की और चिली ने दिसंबर में अपनी बेंचमार्क दर में 25 बीपीएस की कटौती की। दूसरी ओर, ब्राजील ने अपनी नवीनतम बैठक में अपनी दर में 100 बीपीएस की वृद्धि की (चार्ट II.10बी)।

III. घरेलू घटनाक्रम

2024-25 की तीसरी तिमाही के लिए उच्च आवृत्ति संकेतक (एचएफआई) संकेत देते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था दूसरी तिमाही में देखी गई गति में नरमी से उबर रही है, जो मजबूत त्यौहारी गतिविधि और ग्रामीण मांग में निरंतर उछाल से प्रेरित है। आने वाले वर्ष के लिए उच्च आशावाद से उपभोक्ता विश्वास को बढ़ावा मिला, जो स्थितियों के वर्तमान आकलन में क्रमिक नरमी से बाहर निकला (चार्ट III.1ए)। आपूर्ति श्रृंखला दबाव ऐतिहासिक औसत स्तरों से नीचे रहा, नवंबर में और कम हुआ (चार्ट III.1बी)। आर्थिक गतिविधि सूचकांक¹¹ के आधार पर, जो मौसमी रूप से समायोजित आधार पर नवंबर में गति में तेजी का संकेत देता है, 2024-25 की तीसरी तिमाही के लिए जीडीपी वृद्धि का अनुमान 6.8 प्रतिशत रखा गया है (चार्ट III.1सी और 1डी)।

आंतरिक डायनेमिक स्टोकेस्टिक जनरल इक्विलिब्रियम (डीएसजीई) पर आधारित अनुमानों के अनुसार, वास्तविक

जीडीपी वृद्धि 2024-25 की तीसरी और चौथी तिमाही में क्रमशः 6.8 प्रतिशत और 6.5 प्रतिशत तक पहुंचने की संभावना है। 2025-26 के लिए वृद्धि 6.7 प्रतिशत अनुमानित है, जबकि हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति 2025-26 में औसतन 3.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है (सारणी III.1 और चार्ट III.2)।

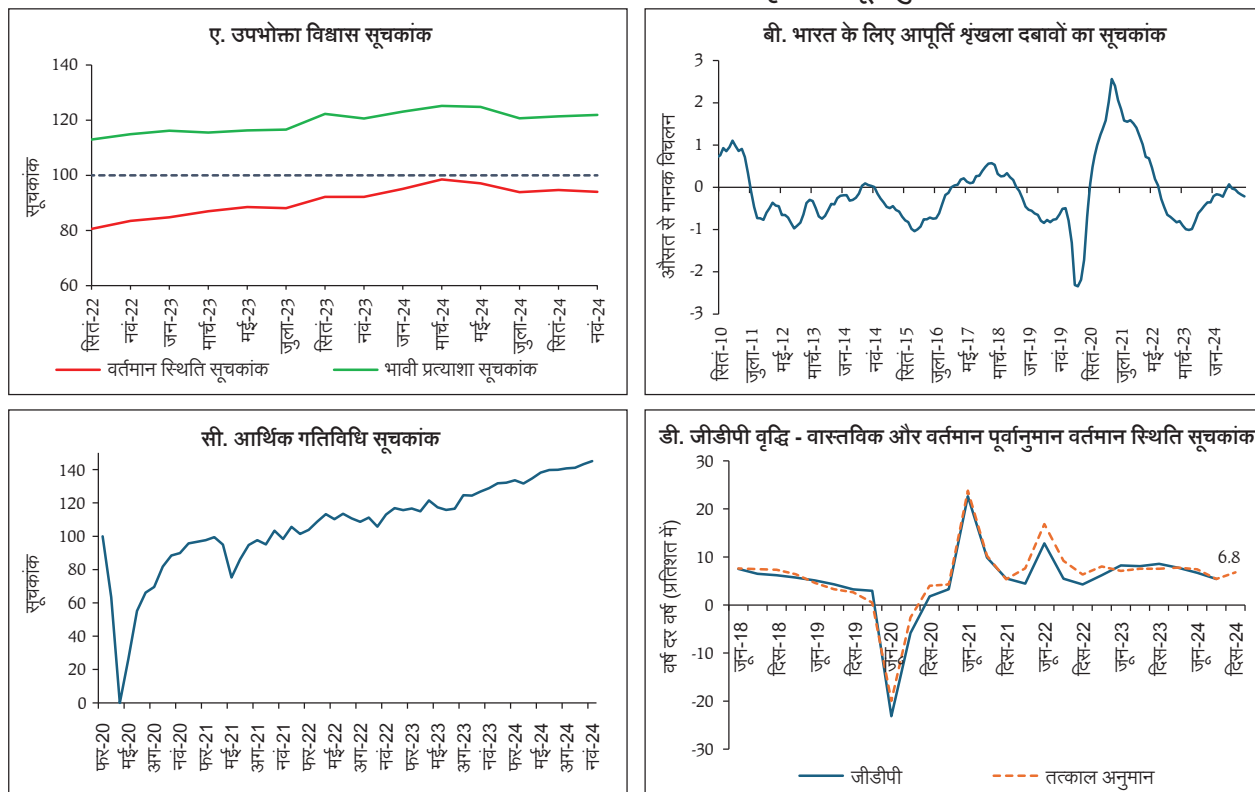
समग्र मांग

वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 2024-25 की दूसरी तिमाही में 5.4 प्रतिशत पर आ गई, जो सात तिमाहियों में सबसे कम है, जबकि 2023-24 की दूसरी तिमाही में यह 8.1 प्रतिशत और 2024-25 की पहली तिमाही में 6.7 प्रतिशत थी। क्रमिक नरमी घरेलू कारकों, निजी खपत और स्थिर निवेश में कमी के कारण थी। हालांकि, सरकार के अंतिम उपभोग व्यय में सुधार हुआ और निवल निर्यात ने 2024-25 की दूसरी तिमाही में वृद्धि में सकारात्मक योगदान दिया (चार्ट III.3)।

कुल मांग का प्रमुख घटक, निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई) 2024-25 की दूसरी तिमाही में 6.0 प्रतिशत (वार्षिक आधार पर) बढ़ा, जो एक साल पहले दर्ज 2.6 प्रतिशत से अधिक है। बाद की एचएफआई का सुझाव है कि ग्रामीण मांग की स्थिति में सुधार जारी है, जबकि शहरी मांग में सुधार के संकेत दिखाई दे रहे हैं। सकल स्थिर पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ) ने 2024-25 की दूसरी तिमाही में 5.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की,

¹¹ यह सूचकांक उद्योग, सेवा, वैश्विक और विविध गतिविधियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 27 मासिक संकेतकों में अंतर्निहित गतिशील सामान्य कारक को निकालता है।

चार्ट III.1: आर्थिक गतिविधि और जीडीपी वृद्धि का पूर्वानुमान



टिप्पणी: आर्थिक गतिविधि सूचकांक (ईएआई) का निर्माण डायनेमिक फैक्टर मॉडल का उपयोग करके आर्थिक गतिविधि के सत्ताईस उच्च आवृत्ति संकेतकों में अंतर्निहित सामान्य प्रवृत्ति को निकालकर किया जाता है। फरवरी 2020 में ईएआई को 100 और अप्रैल 2020 में 0 पर रखा गया है, जो गतिशीलता प्रतिबंधों के कारण सबसे अधिक प्रभावित महीना है।

स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ); उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (सीसीएस); आरबीआई; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

जो 2023-24 की दूसरी तिमाही के 11.6 प्रतिशत (2024-25 की पहली तिमाही में 7.5 प्रतिशत) से कम है। यह नरमी पूंजी निर्माण के संयोग संकेतकों में भी स्पष्ट थी, जिसमें इस्पात की खपत, सीमेंट उत्पादन और पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन और आयात शामिल हैं। पिछली तिमाही में संकुचन के बाद

सरकारी अंतिम उपभोग व्यय (जीएफसीई) में वृद्धि 2024-25 की दूसरी तिमाही में 4.4 प्रतिशत हो गई। बाहरी मोर्चे पर, जबकि निर्यात में 2024-25 की दूसरी तिमाही में मामूली रूप से 2.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई, आयात में 2.9 प्रतिशत की कमी आई। आयात की तुलना में निर्यात वृद्धि अधिक होने के कारण, निवल निर्यात ने 2024-25 की दूसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में 1.5 प्रतिशत अंकों का सकारात्मक योगदान दिया।

उच्च आवृत्ति संकेतक बताते हैं कि अक्तूबर/नवंबर 2024 में कुल मांग में वृद्धि जारी रहेगी। नवंबर में ई-वे बिल में मात्रा के लिहाज से 16.3 प्रतिशत (वर्ष दर वर्ष) की वृद्धि हुई (चार्ट III.4ए)। नवंबर 2024 में टोल संग्रह में मूल्य और मात्रा दोनों के लिहाज से दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज की गई (चार्ट III.4बी)।

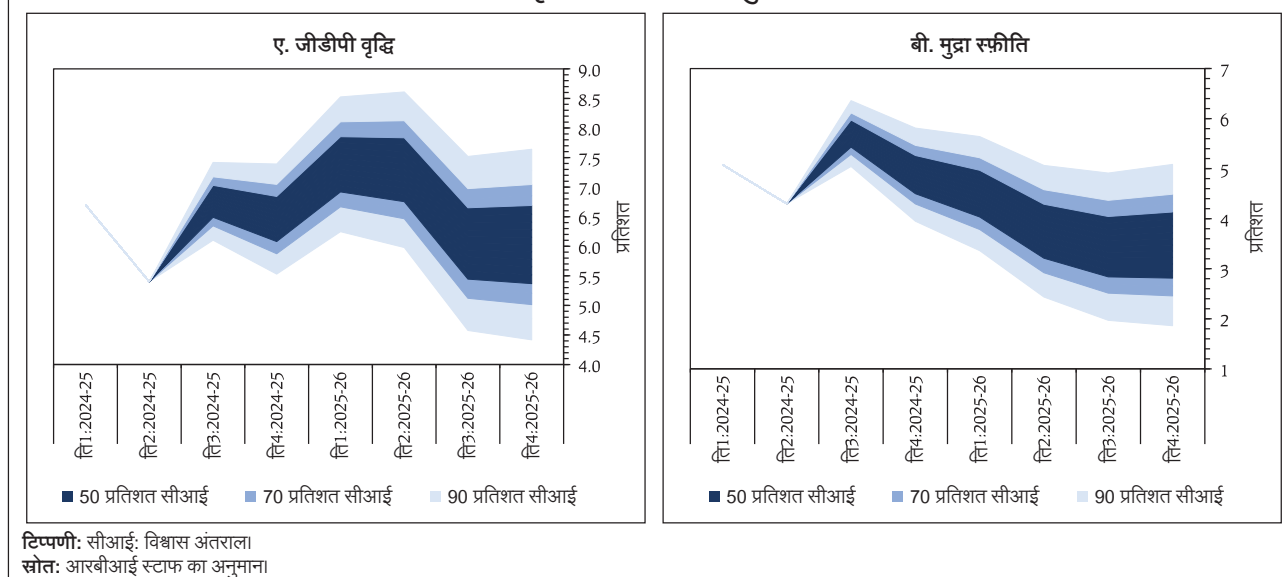
सारणी III.1 आधार अनुमान

(प्रतिशत में वर्ष दर वर्ष)

अवधि	जीडीपी वृद्धि	सीपीआई मुद्रास्फीति
ति3: 2024-25	6.8	5.7
ति4: 2024-25	6.5	4.9
ति1: 2025-26	7.4	4.5
ति2: 2025-26	7.3	3.7
ति3: 2025-26	6.0	3.4
ति4: 2025-26	6.0	3.5
वित्तीय वर्ष 2025-26	6.7	3.8

स्रोत: आरबीआई स्टाफ का अनुमान.

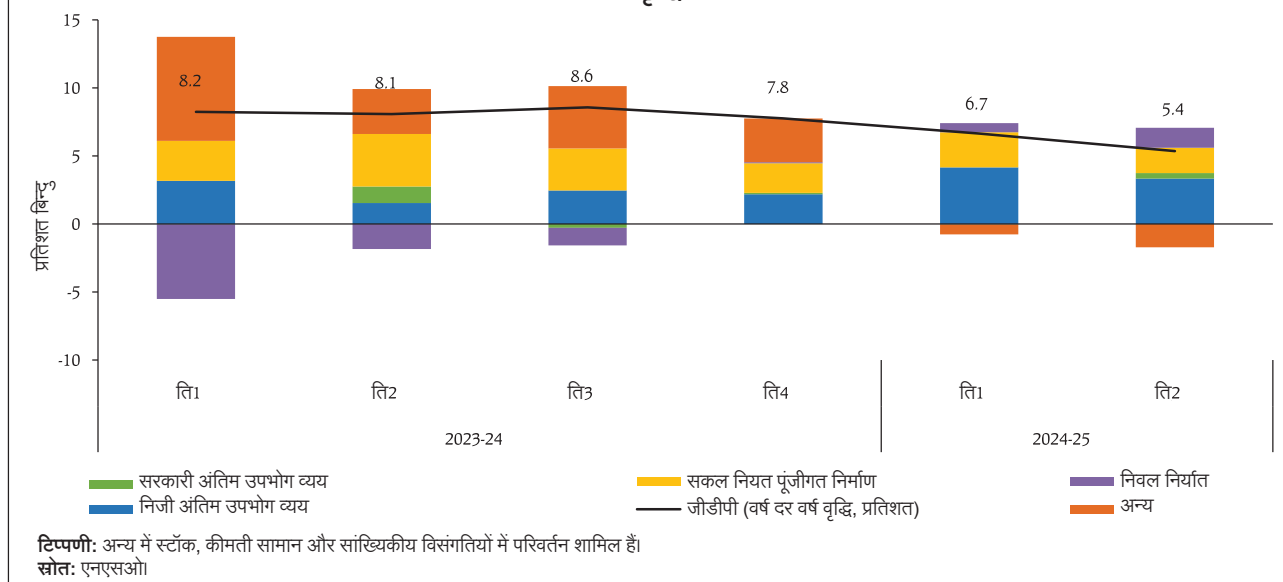
चार्ट III.2: जीडीपी वृद्धि और सीपीआई मुद्रास्फीति के फैन चार्ट



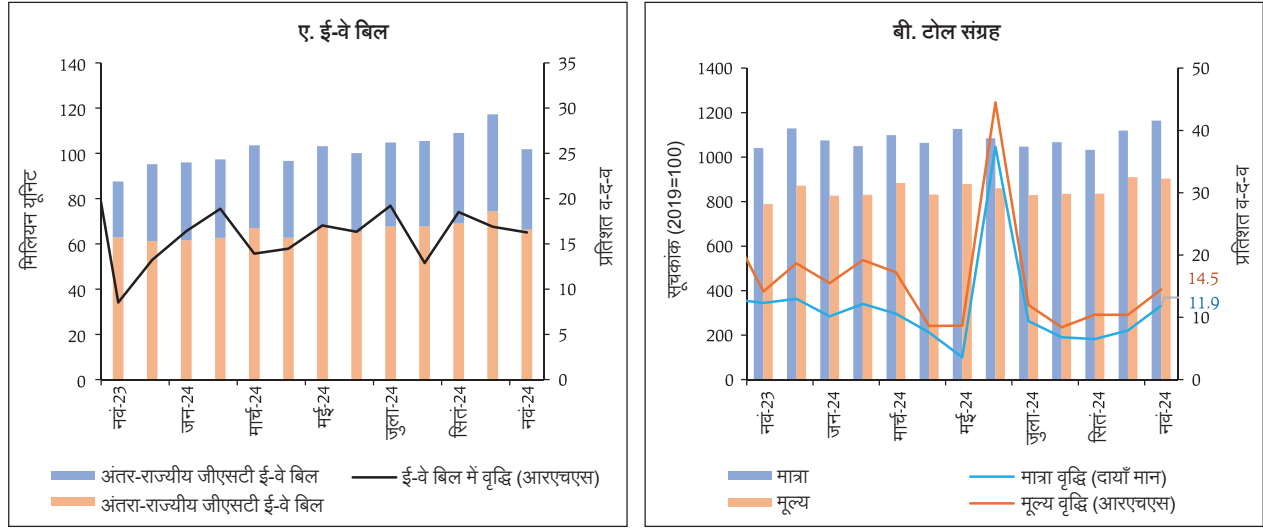
ऑटोमोबाइल की बिक्री 16 महीनों में पहली बार साल-दर-साल आधार पर मामूली रूप से घटी है, जो एक साल पहले के उच्च आधार (नवंबर 2023 में 26.5 प्रतिशत सालाना वृद्धि) के प्रभाव से प्रेरित है [चार्ट III.5ए]। स्कूटर की बिक्री साल-दर-साल बढ़ी है, जबकि अन्य दोपहिया, तिपहिया और ट्रैक्टरों की बिक्री में मामूली संकुचन दर्ज किया गया है (चार्ट III.5बी)।

नवंबर 2024 में वाहन पंजीकरण दोहरे अंकों (साल-दर-साल) में बढ़ना जारी रहा, जबकि गैर-परिवहन वाहनों के पंजीकरण में मामूली तेजी आई है (चार्ट III.5सी)। नवंबर 2024 में भारत की ईंधन खपत में बढ़ोतरी हुई, जो कि खेतों में कटाई, ग्रामीण गतिविधियों में बढ़ोतरी और मजबूत हवाई यात्रा के कारण हुई (चार्ट III.5डी)।

चार्ट III.3: जीडीपी वृद्धि में भारत योगदान



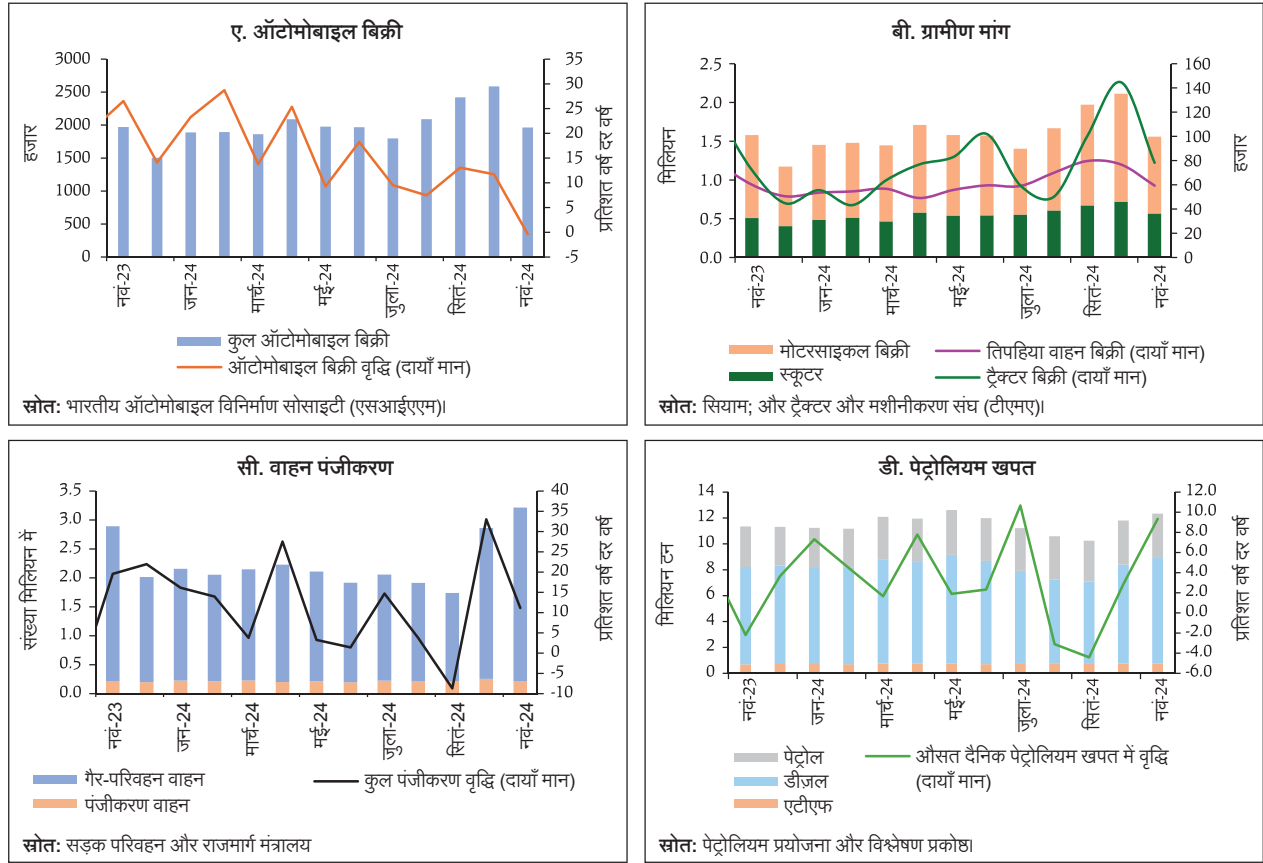
चार्ट III.4 : ई-वे बिल और टोल संग्रह

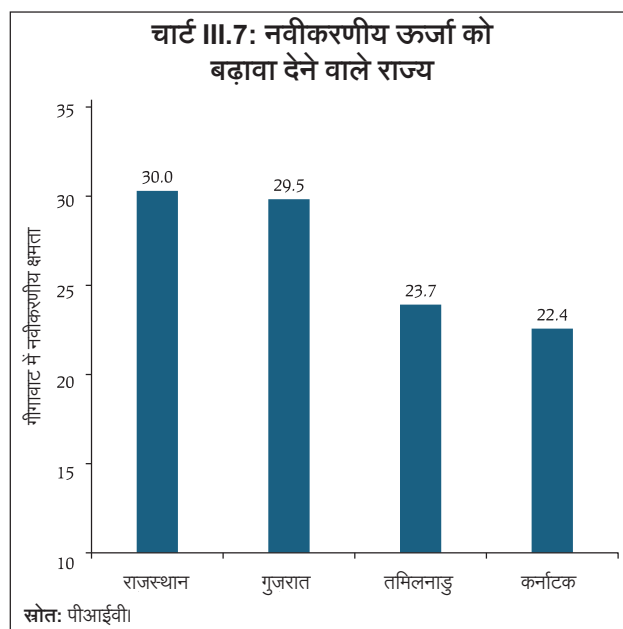
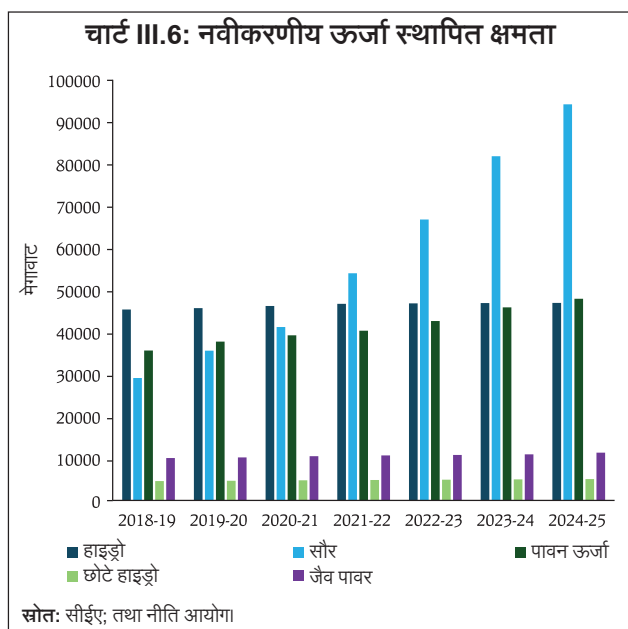


नवीकरणीय ऊर्जा के मोर्चे पर, भारत ने हाल के वर्षों में सौर, पवन और जलविद्युत की स्थापित क्षमता में वृद्धि के कारण

उल्लेखनीय प्रगति की है (चार्ट III.6)। पीएम सूर्य गृह योजना के तहत पर्याप्त प्रगति हुई है। फरवरी 2024 में पीएमएसजीएमबीवाई

चार्ट III.5 : परिवहन क्षेत्र संकेतक





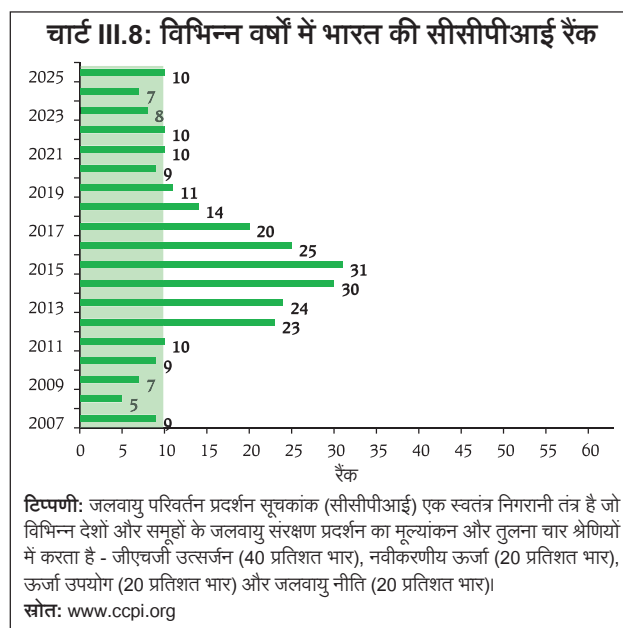
के लॉन्च होने के 9 महीनों के भीतर नवंबर 2024 तक 6.3 लाख इंस्टॉलेशन पूरे किए गए। इस योजना के तहत सब्सिडी¹² के रूप में चार लाख से अधिक उपभोक्ताओं को ₹3,100 करोड़ से अधिक का वितरण भी किया गया। मार्च 2025 तक इस योजना के तहत इंस्टॉलेशन 10 लाख से अधिक होने की उम्मीद है, जिससे रूफटॉप सोलर एनर्जी में एक टिकाऊ भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा।

नवंबर 2024 में भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता 205.5 गीगावाट तक पहुंच गई और कुल गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता 213.7 गीगावाट पर पहुंच गई, जो देश की कुल स्थापित क्षमता का 46 प्रतिशत से अधिक है। राज्यवार, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक ने मिलकर देश की कुल अक्षय क्षमता में लगभग 50 प्रतिशत का योगदान दिया (चार्ट III.7)।

भारत वैश्विक स्तर पर 10वें और जी-20 देशों में दूसरे स्थान पर है¹³। भारत 2020 से शीर्ष 10 प्रदर्शनकर्ताओं में बना हुआ है, जो मुख्य रूप से जलवायु नीति, जीएचजी उत्सर्जन और ऊर्जा

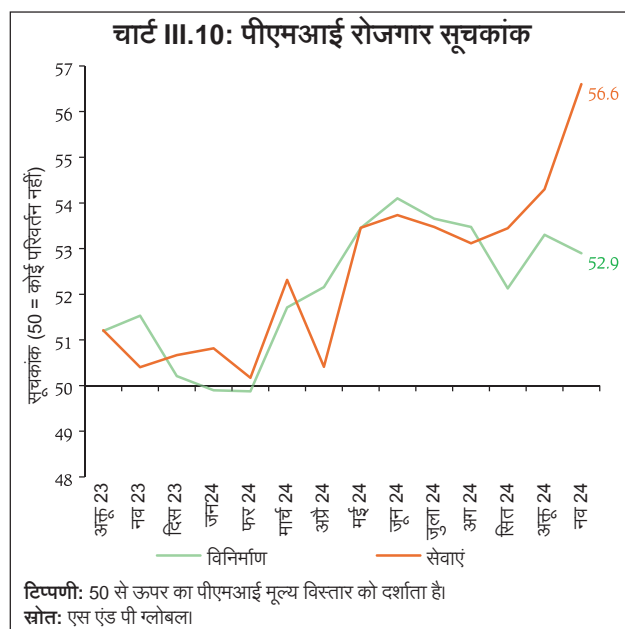
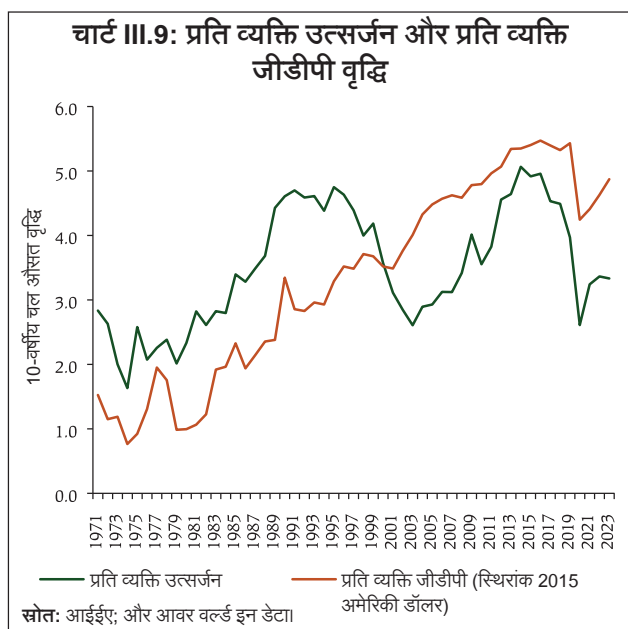
उपयोग घटकों (चार्ट III.8) के क्षेत्रों में प्रभावशाली प्रदर्शन से प्रेरित है।

सीसीपीआई 2025 ने यह भी रेखांकित किया कि भारत ने प्रति व्यक्ति कम जीएचजी उत्सर्जन बनाए रखा है और हाल के दशकों में प्रति व्यक्ति उत्सर्जन में वृद्धि प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (चार्ट III.9) की वृद्धि से कम रही है।



¹² <https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2080833>

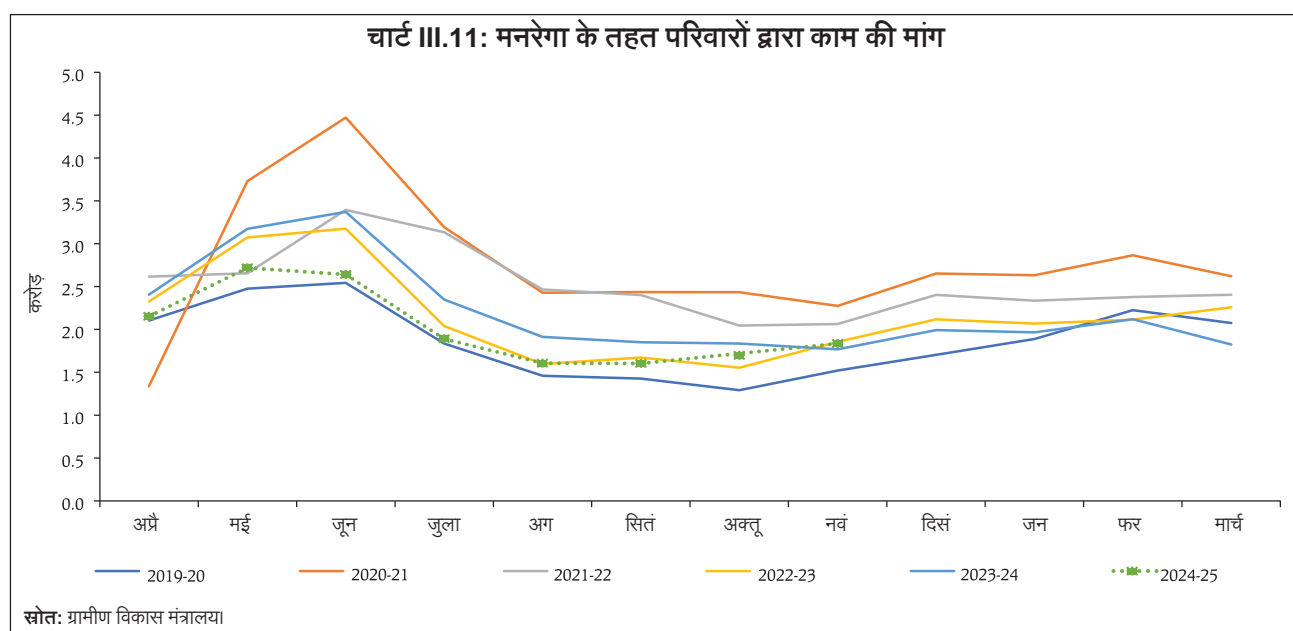
¹³ सूचकांक से पता चलता है कि किसी भी देश ने सभी श्रेणियों में इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया कि उसे समग्र रूप से बहुत उच्च रेटिंग प्राप्त हो सके, इस प्रकार सूचकांक में शीर्ष 3 स्थान रिक्त रह गए हैं, जिससे भारत 7वें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में सामने आया है।



पीएमआई के अनुसार संगठित विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार में लगातार नौवें महीने वृद्धि देखी गई। सर्वेक्षण की शुरुआत के बाद से सेवा क्षेत्र में रोजगार सृजन की दर सबसे तेज़ गति से बढ़ी है (चार्ट III.10)¹⁴।

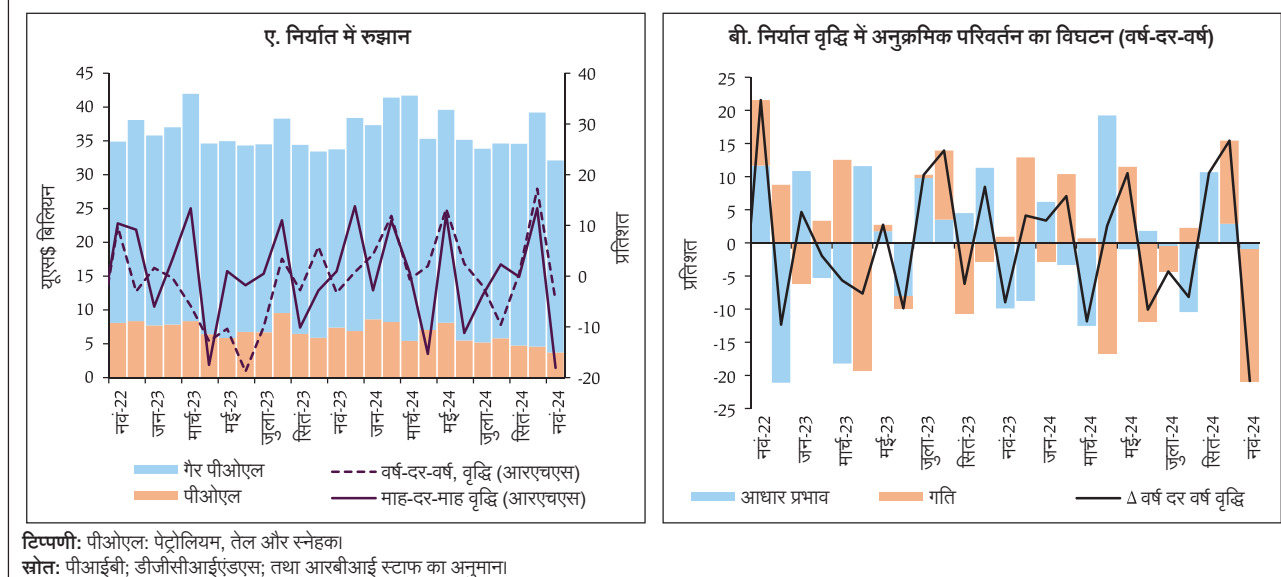
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत काम की मांग में नवंबर 2024 में मासिक

आधार पर 8.2 प्रतिशत और सालाना आधार पर 3.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई, क्योंकि रबी की बुवाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पूरा हो चुका था। चालू वर्ष के दौरान अब तक (अप्रैल-नवंबर) अधिकांश महीनों में मनरेगा के तहत काम की मांग करने वाले परिवारों की कुल संख्या महामारी के बाद के वर्षों की तुलना में कम रही (चार्ट III.11)।



¹⁴ सर्वेक्षण 2005 में शुरू हुआ।

चार्ट III.12: भारत का पण्य निर्यात



नवंबर 2024 में भारत का व्यापारिक निर्यात 4.8 प्रतिशत (वर्ष दर वर्ष) घटकर 32.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया, जो ऋणात्मक गति और प्रतिकूल आधार प्रभाव दोनों के कारण हुआ (चार्ट III.12)।

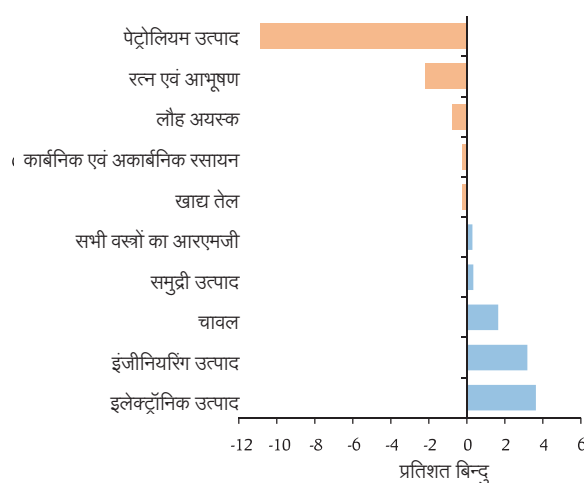
नवंबर में 30 प्रमुख वस्तुओं में से 9 (निर्यात टोकरी का 38 प्रतिशत हिस्सा) के निर्यात में साल-दर-साल आधार पर कमी आई। पेट्रोलियम उत्पाद, रत्न और आभूषण, लौह अयस्क, कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन, और तेल भोजन ने महीने में निर्यात वृद्धि में ऋणात्मक योगदान दिया, जबकि इलेक्ट्रॉनिक सामान, इंजीनियरिंग सामान, चावल, समुद्री उत्पाद, और सभी वस्त्रों में से तैयार वस्त्र (आरएमजी) निर्यात वृद्धि के शीर्ष चालक थे (चार्ट III.13)। अप्रैल-नवंबर 2024 के दौरान, भारत का व्यापारिक निर्यात 2.2 प्रतिशत बढ़कर 284.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जिसका मुख्य नेतृत्व इंजीनियरिंग सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान, ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स, कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन, और सभी वस्त्रों के आरएमजी ने किया, जबकि पेट्रोलियम उत्पाद, रत्न और आभूषण, लौह अयस्क, सिरमिक उत्पाद और कांच के बने पदार्थ, और अन्य अनाज ने निर्यात को नीचे खींच लिया।

नवंबर में 20 में से 9 प्रमुख गंतव्यों को निर्यात में कमी आई। अप्रैल-नवंबर 2024 के दौरान, 20 में से 12 प्रमुख गंतव्यों को

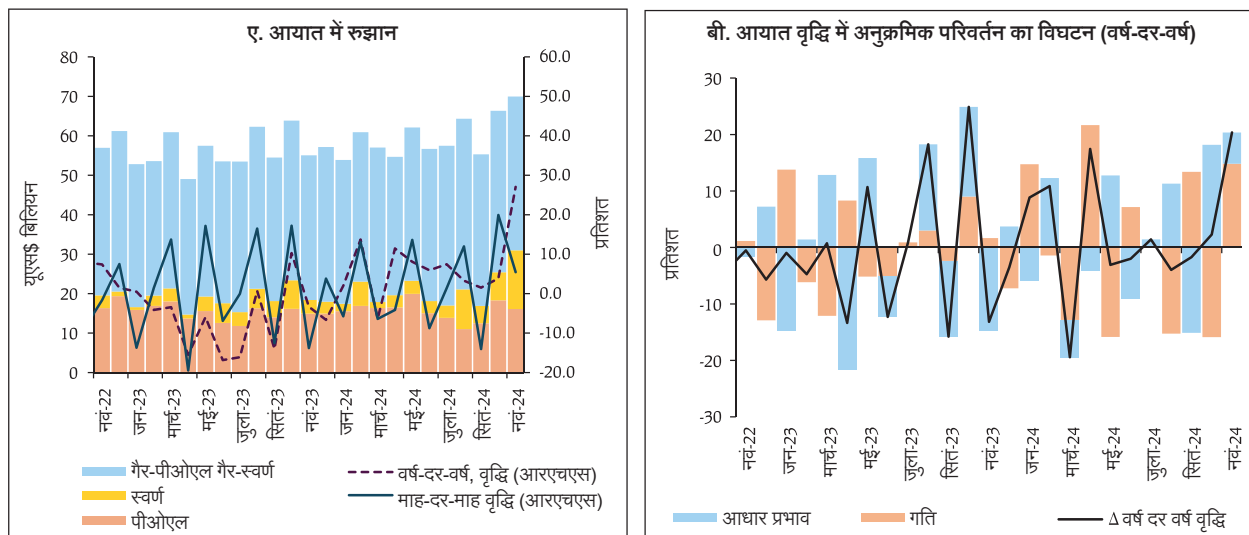
निर्यात में वृद्धि देखी गई, जिसमें अमेरिका, यूएई और नीदरलैंड शीर्ष तीन निर्यात गंतव्य रहे।

नवंबर में लगातार आठवें महीने पण्य आयात में वृद्धि हुई और यह 27.0 प्रतिशत (वर्ष दर वर्ष) की वृद्धि के साथ 70.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया, जो आधार प्रभाव द्वारा समर्थित सकारात्मक गति के कारण हुआ (चार्ट III.14)। 30 प्रमुख वस्तुओं में से 23 वस्तुओं (आयात

चार्ट III.13: भारत का पण्य निर्यात - सापेक्ष योगदान (नवंबर 2023 की तुलना में नवंबर 2024)



चार्ट III.14: भारत का पण्य आयात



स्रोत: पीआईबी; डीजीसीआईएंडएस; तथा आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

बास्केट का 76.0 प्रतिशत हिस्सा) में वर्ष दर वर्ष आधार पर वृद्धि दर्ज की गई।

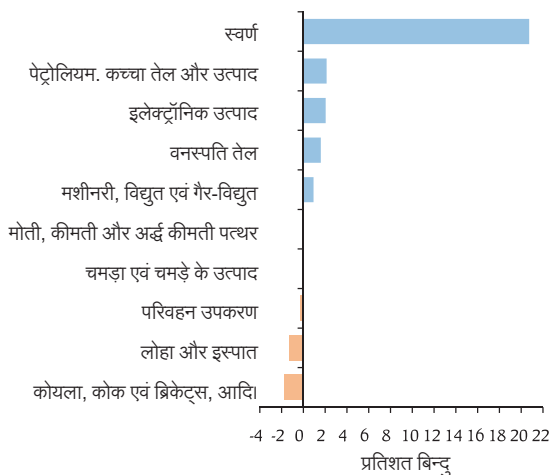
सोना, पीओएल, इलेक्ट्रॉनिक सामान, वनस्पति तेल और मशीनरी ने धनात्मक योगदान दिया, जबकि कोयला, कोक और ब्रिकेट, लोहा और इस्पात, परिवहन उपकरण, चमड़ा और इसके उत्पाद तथा मोती, कीमती और अर्ध-कीमती पत्थरों ने आयात

वृद्धि में ऋणात्मक योगदान दिया (चार्ट III.15)। अप्रैल-नवंबर 2024 के दौरान, भारत का व्यापारिक आयात 8.4 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़कर 486.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जिसमें सोना, पीओएल, इलेक्ट्रॉनिक सामान, अलौह धातु और मशीनरी का योगदान सबसे अधिक रहा, जबकि कोयला, कोक और ब्रिकेट, मोती, कीमती और अर्ध-कीमती पत्थर, रासायनिक सामग्री और उत्पाद, उर्वरक और रंगाई, टैनिंग और रंग सामग्री ने ऋणात्मक योगदान दिया।

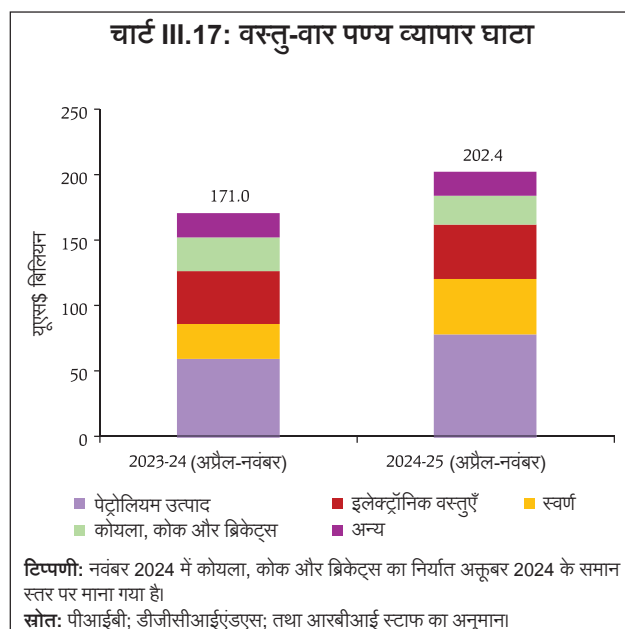
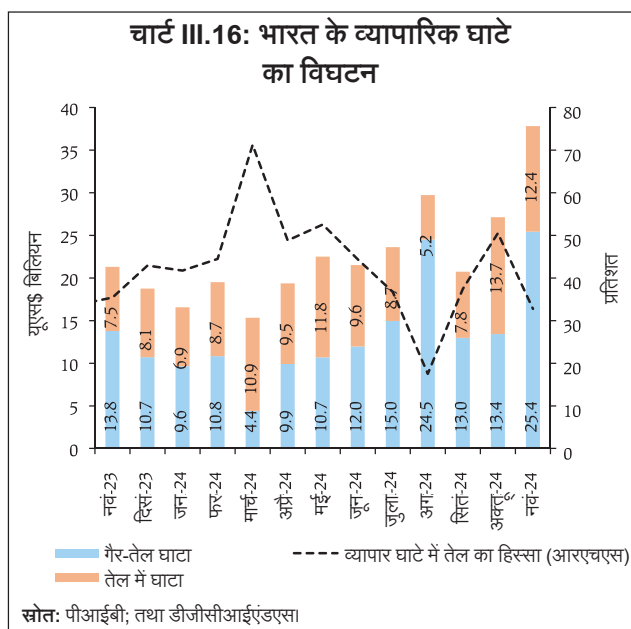
नवंबर में और अप्रैल-नवंबर 2024 के दौरान 20 प्रमुख स्रोत देशों में से 13 से आयात में वृद्धि हुई। प्रमुख स्रोत देशों, अर्थात् चीन, यूई और रूस से आयात में मजबूत वृद्धि देखी गई।

नवंबर 2024 में व्यापारिक व्यापार घाटा बढ़कर 37.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। नवंबर में तेल घाटा बढ़कर 12.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो एक साल पहले 7.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। हालांकि, व्यापार घाटे में तेल घाटे का हिस्सा नवंबर में घटकर 32.8 प्रतिशत रह गया, जो एक साल पहले 35.4 प्रतिशत था। गैर-तेल घाटा नवंबर में बढ़कर 25.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो एक साल पहले 13.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर था (चार्ट III.16)।

चार्ट III.15: भारत का पण्य आयात – सापेक्ष योगदान (नवंबर 2023 की तुलना में नवंबर 2024)



स्रोत: पीआईबी; तथा आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

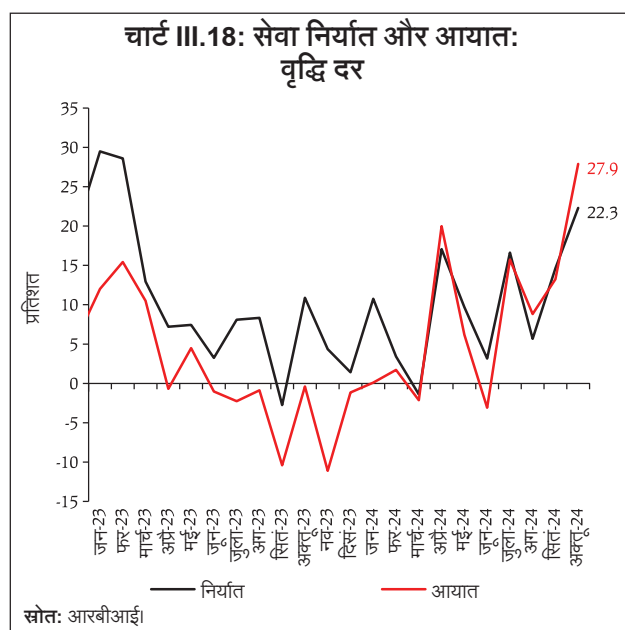


अप्रैल-नवंबर 2024 के दौरान, भारत का व्यापारिक घाटा एक साल पहले के 171.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 202.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। पेट्रोलियम उत्पाद घाटे का सबसे बड़ा स्रोत थे, उसके बाद सोना (चार्ट III.17) था।

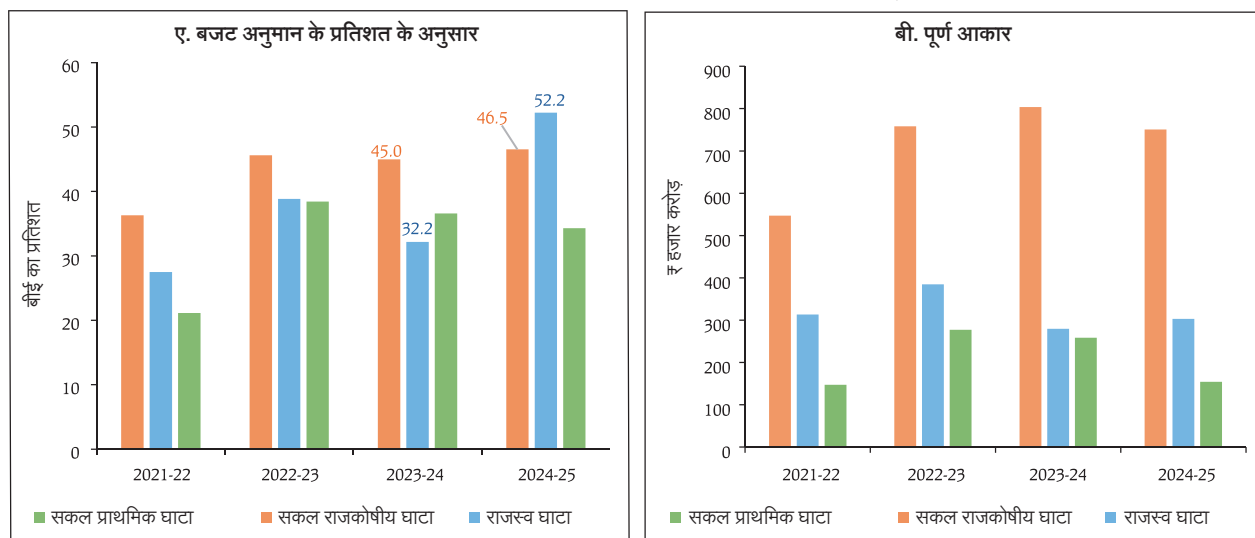
अक्टूबर 2024 के दौरान, सेवाओं का निर्यात 34.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जिसमें 22.3 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की मजबूत वृद्धि देखी गई, जबकि सेवाओं का आयात 27.9 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़कर 17.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया (चार्ट III.18)। महीने के दौरान निवल सेवा निर्यात आय 17.2 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़कर 17.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई।

केंद्र सरकार के सकल राजकोषीय घाटे (जीएफडी) और राजस्व घाटे (आरडी) [बजट अनुमान (बीई)] के प्रतिशत के रूप में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अप्रैल-अक्टूबर 2024 में वृद्धि देखी गई (चार्ट III.19)। बजटीय घाटे में वृद्धि मुख्य रूप से राजस्व व्यय के कारण हुई, जो एक साल पहले 6.5 प्रतिशत की तुलना में 8.7 प्रतिशत बढ़ा। दूसरी ओर, कुल प्राप्तियों में 8.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो एक साल पहले इसी अवधि के दौरान 14.8 प्रतिशत से कम है।

राजस्व व्यय में वृद्धि प्रमुख सब्सिडी पर व्यय के कारण हुई, जिसमें खाद्य और पेट्रोलियम सब्सिडी के कारण अप्रैल-अक्टूबर 2024 में 7.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। हालांकि, पूंजीगत व्यय में वृद्धि में कमी देखी गई। शीर्ष छह मंत्रालय, जो 2024-25 के लिए बजटीय पूंजीगत व्यय का 95 प्रतिशत से अधिक हिस्सा रखते हैं, ने पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अप्रैल-अक्टूबर 2024-25 के दौरान अपने पूंजीगत व्यय में गिरावट देखी



चार्ट III.19: केंद्र सरकार का बजटीय घाटा (अप्रैल-अक्तूबर)



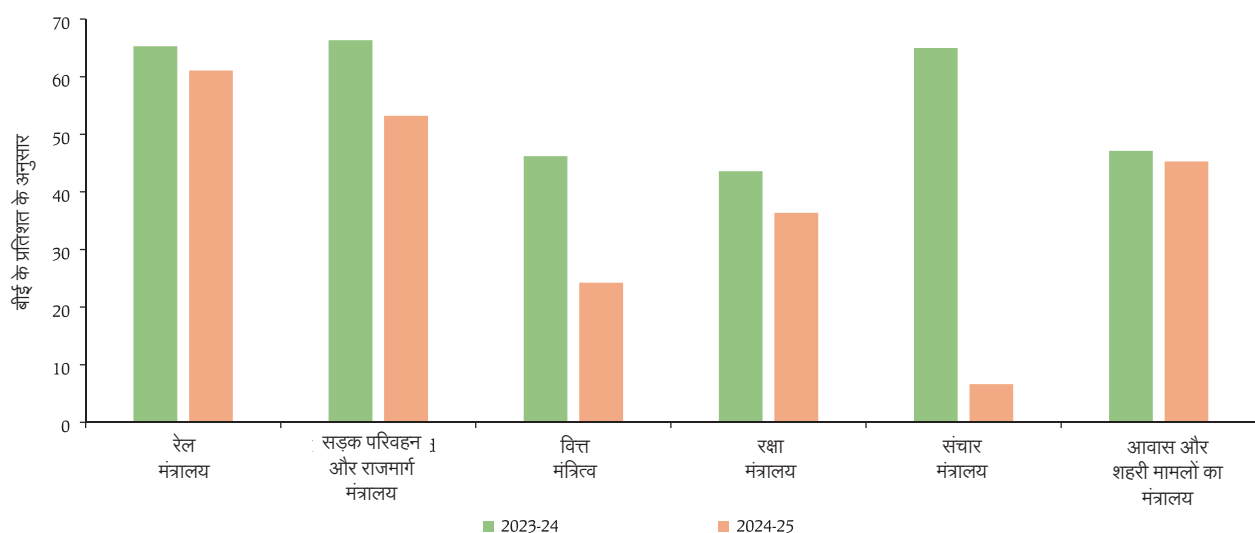
स्रोत: महालेखा नियंत्रक (सीजीए)

(चार्ट III.20)। राजस्व व्यय में वृद्धि ने अप्रैल-अक्तूबर 2024 के दौरान कुल व्यय में 3.3 प्रतिशत की वृद्धि का समर्थन किया।

प्राप्तियों के मामले में, केंद्र सरकार की राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की इसी अवधि में 16.1 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले 8.7 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। आयकर में 20.2

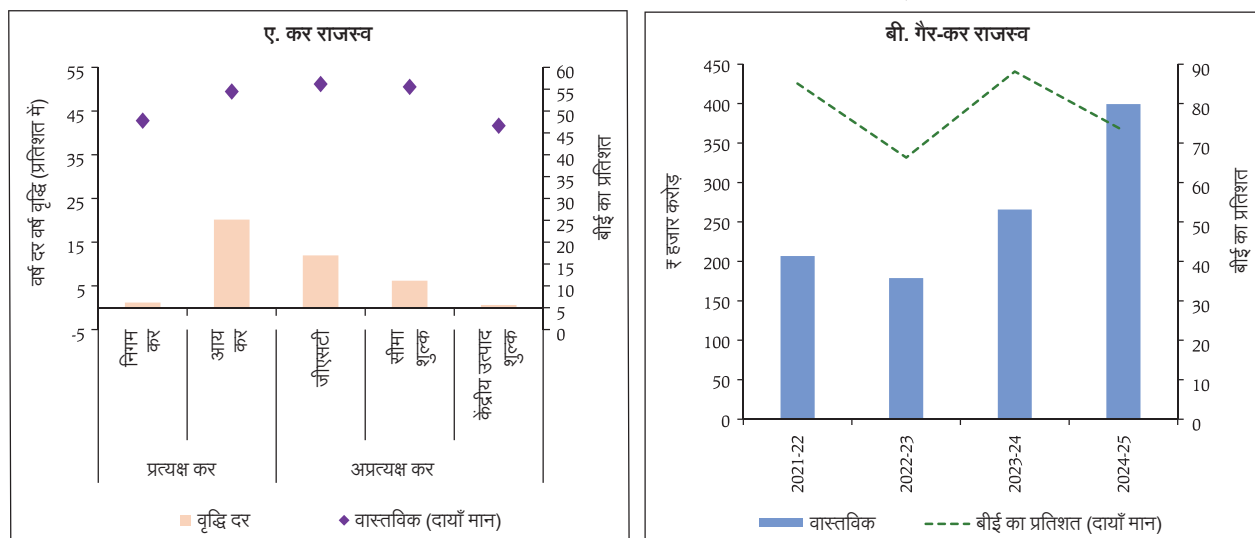
प्रतिशत की वृद्धि के कारण प्रत्यक्ष करों में 11.9 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई। हालांकि, कॉर्पोरेट कर संग्रह सुस्त रहा। अप्रत्यक्ष करों में 9.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जीएसटी और सीमा शुल्क राजस्व में क्रमशः 12.0 प्रतिशत और 6.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई (चार्ट III.21 ए)। इसी तरह, रिजर्व बैंक से 2.11 लाख करोड़ रुपये के अधिशेष हस्तांतरण के कारण गैर-

चार्ट III.20: अप्रैल-अक्तूबर के दौरान मंत्रालयवार पूंजीगत व्यय



स्रोत: सीजीए

चार्ट III.21: केंद्र सरकार की राजस्व प्राप्ति (अप्रैल-अक्तूबर)



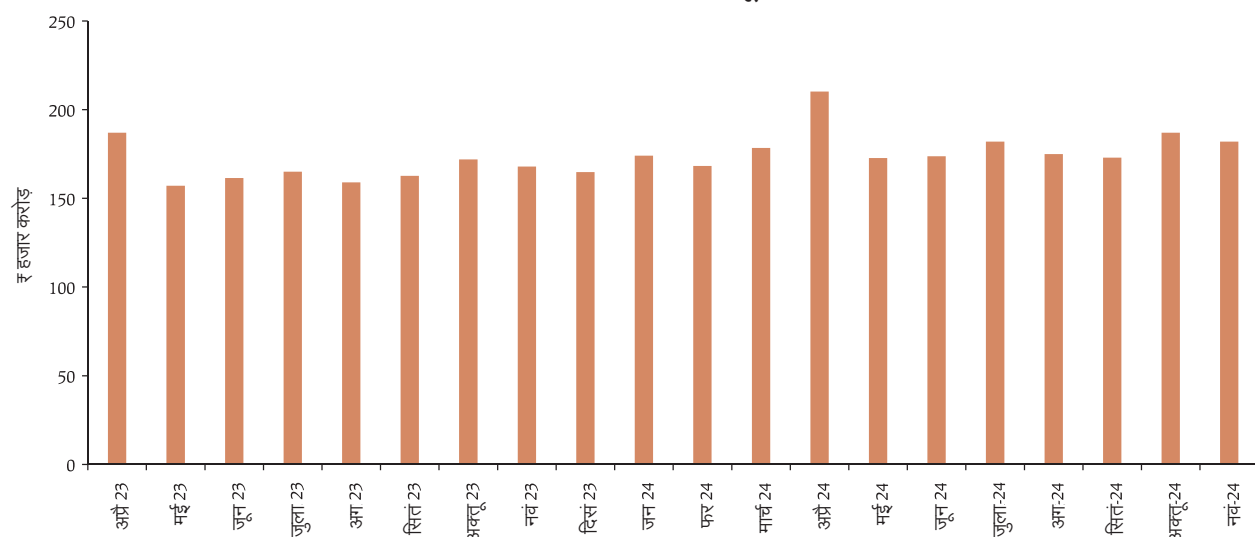
स्रोत: सीजीए

कर राजस्व संग्रह में 50.2 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई (चार्ट III.21 बी)। सकल कर राजस्व में 10.8 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के बावजूद, इस अवधि के दौरान निवल कर राजस्व में केवल 0.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई, कुल मिलाकर, अप्रैल-अक्तूबर 2024-25 के दौरान निवल कर राजस्व बजट अनुमान का 50.5 प्रतिशत था।

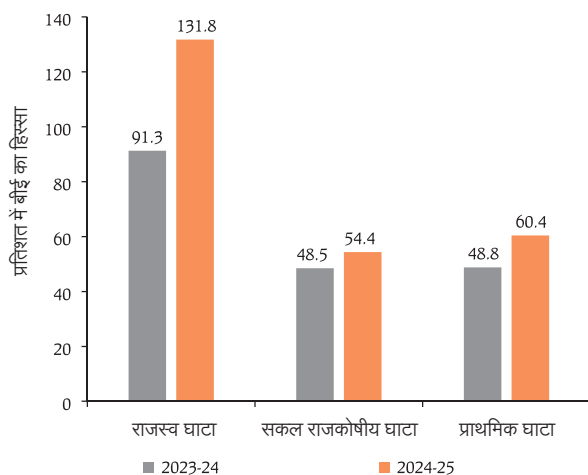
नवंबर 2024 में जीएसटी संग्रह (केंद्र और राज्य) ₹1.82 लाख करोड़ रहा, जिससे अप्रैल-नवंबर 2024 के लिए संचयी जीएसटी संग्रह ₹14.57 लाख करोड़ हो गया (अप्रैल-नवंबर 2023 की तुलना में 9.3 प्रतिशत अधिक) [चार्ट III.22]।

अप्रैल-अक्तूबर 2024-25 के दौरान, राज्यों का सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी), बजट अनुमानों का 54.4

चार्ट III.22: जीएसटी वसूली



स्रोत: प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी); और जीएसटी पोर्टल।

चार्ट III.23: राज्यों के राजकोषीय संकेतक (अप्रैल-अक्तूबर)

टिप्पणी: आंकड़े 21 राज्यों से संबंधित हैं।

स्रोत: भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

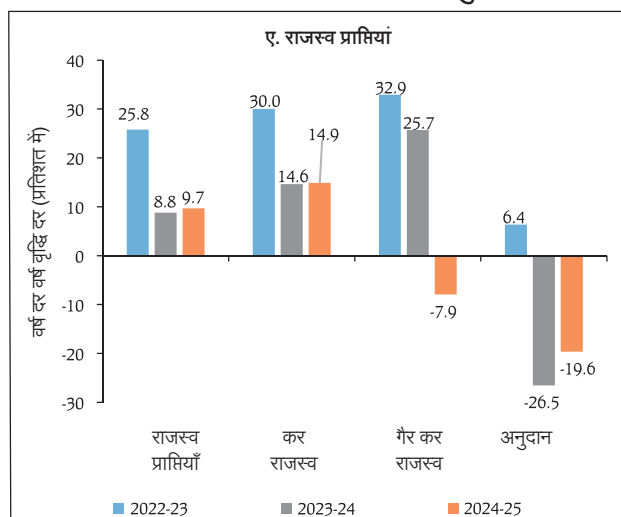
प्रतिशत¹⁵, पिछले वर्ष के स्तर से अधिक था (चार्ट III.23)। जबकि राज्यों की राजस्व प्राप्तियां उच्च कर राजस्व से प्रेरित होकर बढ़ीं, गैर-कर राजस्व और अनुदान में संकुचन दर्ज किया गया (चार्ट III.24ए)। राज्यों के अपने कर राजस्व के भीतर,

बिक्री कर/वैट संग्रह एक वर्ष पहले इसी अवधि के दौरान देखी गई संकुचन से उबर गया, जबकि राज्यों के माल और सेवा कर (एसजीएसटी) और राज्य उत्पाद शुल्क में वृद्धि धीमी रही।

व्यय पक्ष पर, अप्रैल-अक्तूबर 2024 के दौरान राजस्व व्यय में वृद्धि हुई, जबकि पूंजीगत व्यय पिछले वर्ष के स्तर से कम रहा (चार्ट III.24बी)। आगे चलकर, पूंजीगत व्यय में वृद्धि होने की उम्मीद है, जिसका आंशिक कारण केंद्र द्वारा ₹1.5 लाख करोड़ के दीर्घकालिक ब्याज मुक्त ऋण की विशेष सहायता का प्रावधान है। 2024-25 के दौरान अब तक (24 नवंबर, 2024 तक), उक्त योजना के तहत पात्र राज्यों को ₹50,571.4 करोड़ की पूंजीगत व्यय राशि जारी की जा चुकी है।¹⁶

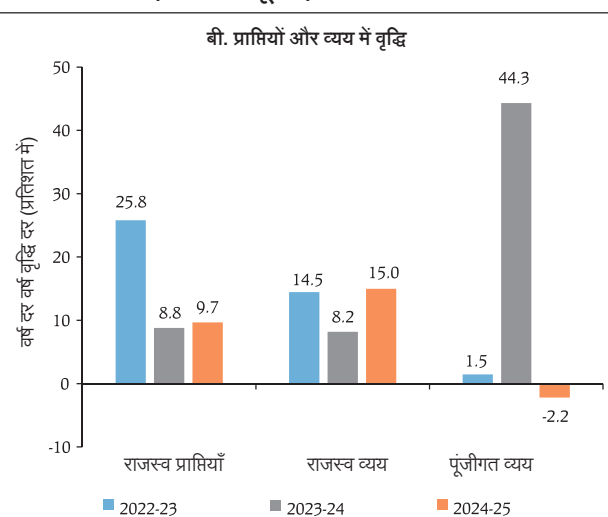
समग्र आपूर्ति

सकल आपूर्ति - जिसे मूल कीमतों पर सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) द्वारा मापा जाता है - में 2024-25 की दूसरी तिमाही में 5.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि एक वर्ष पहले यह 7.7 प्रतिशत थी (ति1:2024-25 में 6.8 प्रतिशत)। विकास में मंदी मुख्य रूप से औद्योगिक गतिविधि में कमी के कारण थी, जबकि

चार्ट III.24: प्रमुख राजकोषीय प्रदर्शन संकेतक (अप्रैल-अक्तूबर)

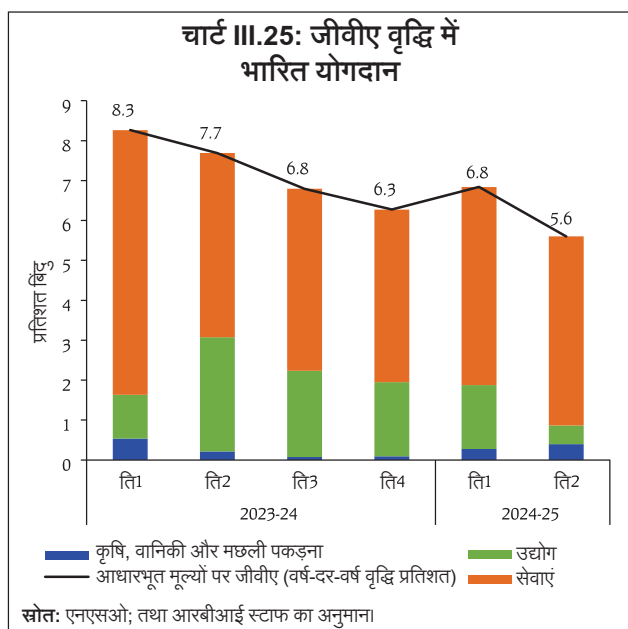
टिप्पणी: आंकड़े 21 राज्यों से संबंधित हैं।

स्रोत: भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक



¹⁵ अनंतिम लेखा आंकड़ों के अनुसार।

¹⁶ डिजिटल संसद, संसद सदस्य (एमपी) दिलीप सैकिया के प्रश्न का उत्तर।



सेवा क्षेत्र ने सुदृढ़ता दिखाया और कृषि में सुधार दर्ज किया (चार्ट III.25)।

कृषि, वानिकी और मछली पकड़ने में वृद्धि दर 2024-25 की दूसरी तिमाही में 3.5 प्रतिशत हो गई, जो एक साल पहले 1.7 प्रतिशत थी। यह वृद्धि 2024-25 में खरीफ खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के कारण हुई, जिसे सामान्य से बेहतर दक्षिण-पश्चिम मानसून का समर्थन प्राप्त था।¹⁷ औद्योगिक गतिविधि ने पिछले वर्ष की इसी तिमाही में 13.6 प्रतिशत के प्रतिकूल आधार पर 2024-25 की दूसरी तिमाही में 2.1 प्रतिशत की मामूली वृद्धि दर्ज की। औद्योगिक क्षेत्र में, भारी वर्षा के कारण खनन और उत्खनन गतिविधि में कमी आई, जबकि विनिर्माण - प्रमुख घटक - में वृद्धि पांच तिमाहियों के निचले स्तर 2.2 प्रतिशत पर आ गई। बिजली, गैस, जलापूर्ति और अन्य उपयोगिता सेवाओं में भी वृद्धि धीमी रही। सेवा क्षेत्र सुदृढ़ बना रहा, 2024-25 की दूसरी तिमाही में 7.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि 2023-24 की दूसरी तिमाही में 6.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी (2024-25 की पहली तिमाही में 7.7 प्रतिशत)। विनिर्माण गतिविधि में

वृद्धि 2023-24 की दूसरी तिमाही में 13.6 प्रतिशत से घटकर 2024-25 की दूसरी तिमाही में 7.7 प्रतिशत हो गई, जो आंशिक रूप से केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा अनुमानित पूंजीगत व्यय से कम होने को दर्शाती है। व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण से संबंधित सेवाओं ने साल-दर-साल और क्रमिक आधार पर वृद्धि में तेजी दर्ज की। वित्तीय, रियल एस्टेट और पेशेवर सेवाओं में वृद्धि 2024-25 की दूसरी तिमाही में 6.7 प्रतिशत हो गई, क्योंकि ऋण और जमा वृद्धि में नरमी देखी गई। हालांकि, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) कंपनियों के प्रदर्शन में पिछली तिमाही की तुलना में सुधार हुआ। सार्वजनिक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाओं (पीएडीओ) में वर्ष दर वर्ष आधार पर 2024-25 की दूसरी तिमाही में 9.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

01 अक्तूबर से 19 दिसंबर के दौरान संचयी पूर्वोत्तर मानसून (एनईएम) वर्षा अपने दीर्घ अवधि औसत (एलपीए) से 8 प्रतिशत कम रही, जबकि पिछले साल यह एलपीए से 4 प्रतिशत कम थी। चक्रवात फेंगल की असामान्य रूप से लंबी अवधि ने दक्षिण भारत में वर्षा की गतिविधि को तेज कर दिया, जिससे इस वर्ष कुछ हद तक कमी पूरी हो गई। हालांकि, कम/बहुत कम वर्षा वाले उप-विभागों की संख्या एक साल पहले की तुलना में 2024 में अधिक थी (चार्ट III.26ए)।

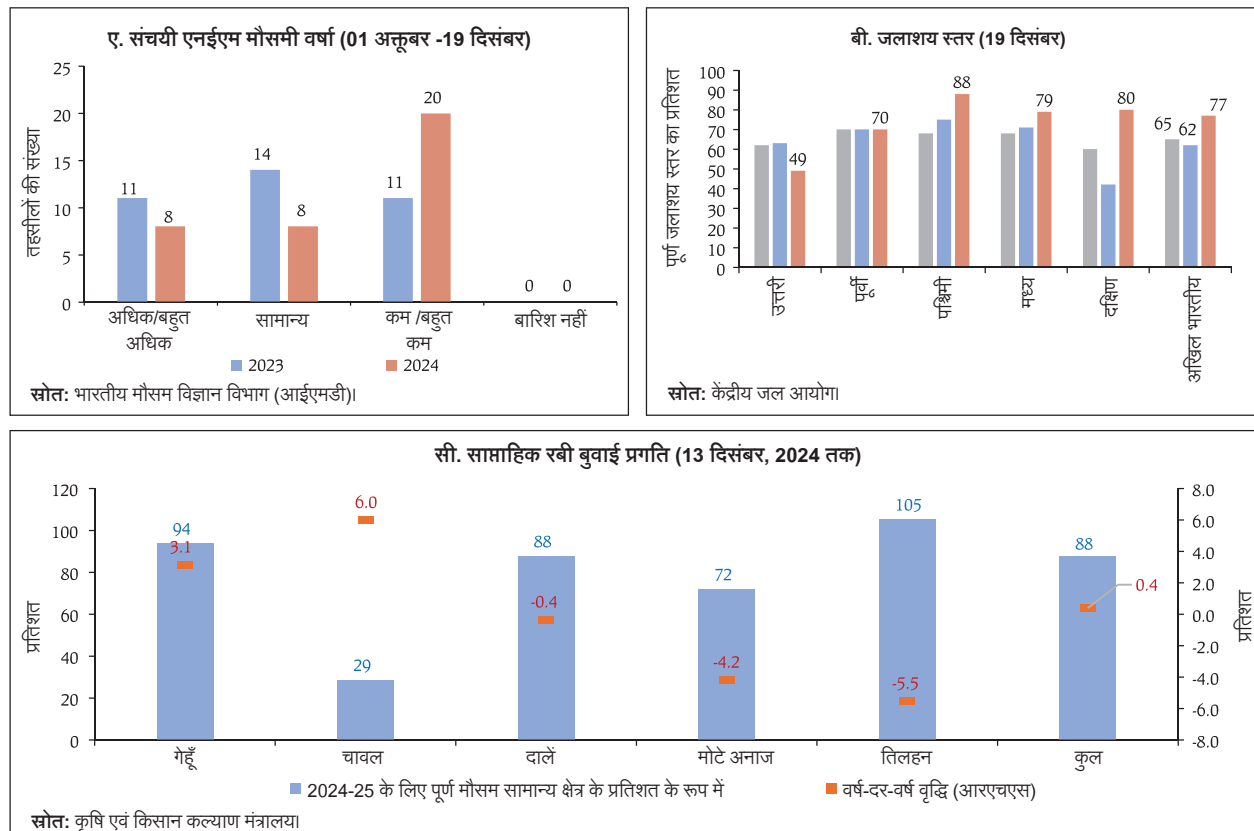
19 दिसंबर 2024 तक अखिल भारतीय औसत जल संग्रहण (155 प्रमुख जलाशयों के आधार पर) कुल क्षमता का 77 प्रतिशत था, जो पिछले वर्ष के संग्रहण और दशकीय औसत से क्रमशः 23.6 प्रतिशत और 17.9 प्रतिशत अधिक है (चार्ट III.26बी)। 13 दिसंबर 2024 तक कुल रबी बोया गया क्षेत्र एक साल पहले के स्तर से 0.4 प्रतिशत अधिक था।¹⁸ जबकि गेहूं और चावल का रकबा पिछले साल के स्तर को पार कर गया, यह दालों, मोटे अनाज और तिलहन के लिए पिछले साल की तुलना में कम रहा (चार्ट III.26सी)।

16 दिसंबर, 2024 तक, खरीफ विपणन सीजन (केएमएस) 2024-25 के लिए संचयी चावल खरीद पिछले वर्ष की इसी

¹⁷ प्रथम अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2024-25 में खरीफ खाद्यान्न उत्पादन 164.7 मिलियन टन अनुमानित है, जो 2023-24 के अंतिम अनुमानों से 5.7 प्रतिशत अधिक है।

¹⁸ कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के आधार पर, जिसमें 13 दिसंबर, 2024 तक पूरे सीजन के सामान्य क्षेत्र का 88 प्रतिशत कवर किया गया।

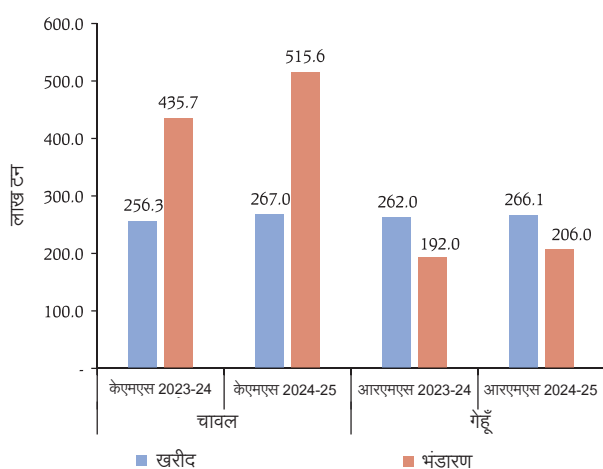
चार्ट III.26: रबी मौसम के लिए परिदृश्य



अवधि की तुलना में 4.2 प्रतिशत अधिक थी (चार्ट III.27)। 01 दिसंबर, 2024 तक चावल का बफर स्टॉक 515.6 लाख टन

था, जो मानक से 5.0 गुना अधिक था।¹⁹ गेहूं का स्टॉक 206 लाख टन था, जो बफर मानक के लगभग बराबर था।

चार्ट III.27: केंद्रीय सार्वजनिक वितरण प्रणाली में खरीद और भंडारण



टिप्पणी : *: 19 दिसंबर तक; #: 01 दिसंबर तक
स्रोत: भारतीय खाद्य निगम।

28 नवंबर, 2024 को भारत सरकार ने घरेलू आपूर्ति बढ़ाने और मूल्य दबाव को कम करने के लिए मार्च 2025 तक खुला बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस) के अंतर्गत ई-नीलामी के माध्यम से 2.5 मिलियन टन गेहूं की बिक्री की घोषणा की।²⁰ इसके अलावा, 11 दिसंबर, 2024 को सरकार ने बाजार में पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए गेहूं भंडारण संस्थाओं के लिए स्टॉक सीमा को संशोधित किया।²¹

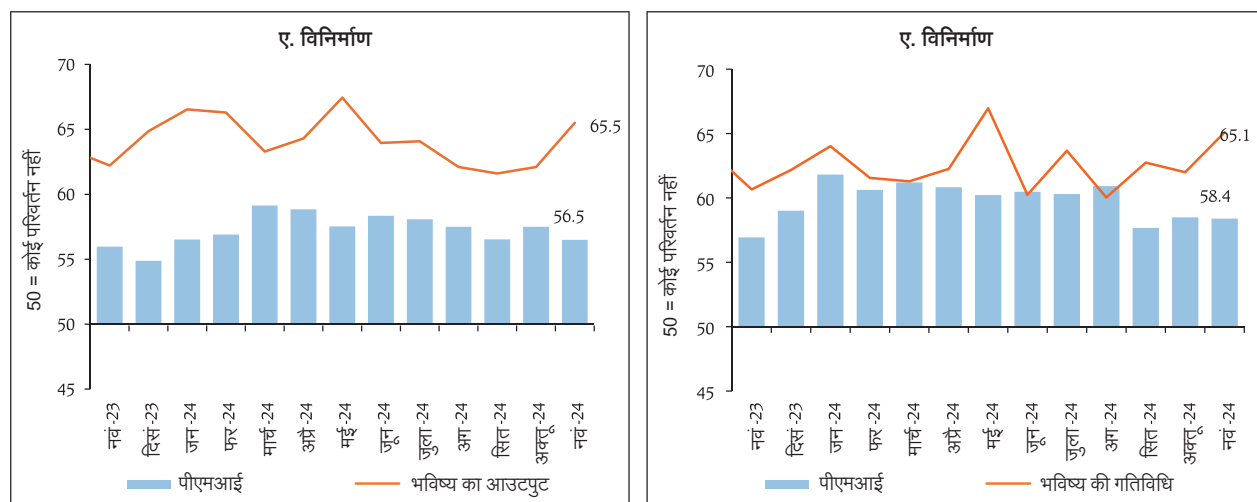
भारत के विनिर्माण पीएमआई ने क्रमिक रूप से नरमी दर्ज की, लेकिन नवंबर के दौरान विस्तार क्षेत्र में रहा क्योंकि

¹⁹ जिसमें बिना पिसाई वाला धान समतुल्य भी शामिल है।

²⁰ यह बिक्री उचित एवं औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) अनाज के लिए 2,325 रुपये प्रति क्विंटल तथा कम गुणवत्ता वाले (यूआरएस) अनाज के लिए 2,300 रुपये प्रति क्विंटल के आरक्षित मूल्य पर होगी।

²¹ <https://pib.gov.in/PressReleaseDetail.aspx?PRID=2083178&lang=1>

चार्ट III.28: क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई)



टिप्पणी : 50 का स्तर गतिविधि में कोई परिवर्तन नहीं होने को दर्शाता है तथा 50 से ऊपर का स्तर विस्तार को दर्शाता है और इसके विपरीत।

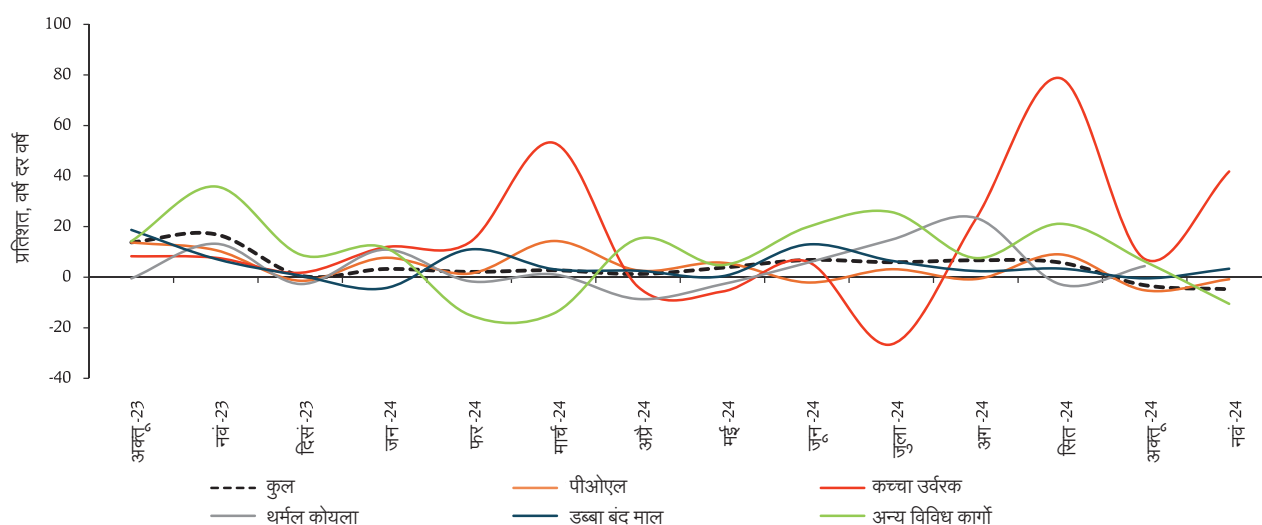
स्रोत: एस एंड पी ग्लोबल।

बाहरी मांग - जैसा कि निर्यात ऑर्डर में वृद्धि से परिलक्षित होता है - ने समर्थन प्रदान किया (चार्ट III.28ए)। सेवाओं के पीएमआई ने मजबूत मांग और नए व्यावसायिक लाभ (चार्ट III.28बी) द्वारा संचालित मजबूत विस्तार दर्ज करना जारी रखा। विनिर्माण और सेवाओं दोनों के लिए व्यावसायिक उम्मीदें आशावादी रहीं, जैसा कि भविष्य के उत्पादन मूल्यांकन से स्पष्ट है।

नवंबर 2024 में बंदरगाह यातायात में कमी आगयी, जिसका कारण लौह अयस्क और पेट्रोलियम, तेल और स्नेहक हैं (चार्ट III.29)।

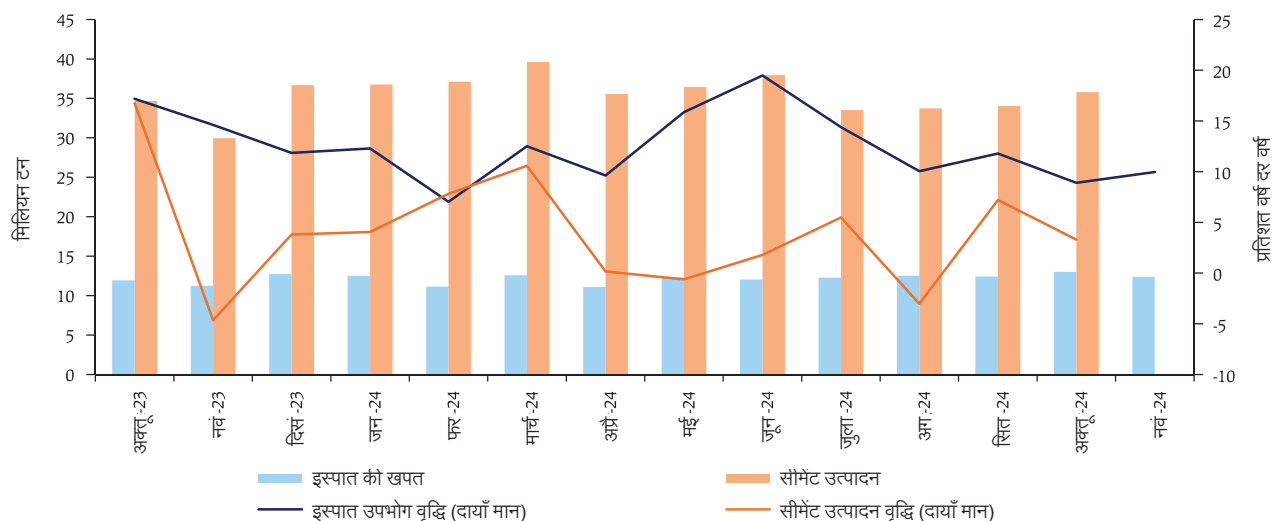
निर्माण क्षेत्र में मिश्रित तस्वीर देखने को मिली; नवंबर में इस्पात की खपत में दो अंकों की वृद्धि (वर्ष दर वर्ष) दर्ज की गई, जबकि अक्तूबर में सीमेंट उत्पादन की वृद्धि में कमी आई (चार्ट III.30)।

चार्ट III.29: पोर्ट कार्गो



स्रोत: भारतीय बंदरगाह संघ।

चार्ट III.30: स्टील की खपत और सीमेंट उत्पादन



स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति; आर्थिक सलाहकार कार्यालय; तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

सेवा क्षेत्र के लिए उपलब्ध उच्च आवृत्ति संकेतक हैं (सारणी III.2)।
अक्तूबर / नवंबर में सुदृढ़ आर्थिक गतिविधि को दर्शाते

सारणी III.2: उच्च आवृत्ति संकेतक- सेवाएं

		(वर्ष-दर-वर्ष प्रतिशत)													
क्षेत्र	संकेतक	अक्टू-23	नव-23	दिस-23	जन-24	फर-24	मार्च-24	अप्रै-24	मई-24	जून-24	जुल-24	अग-24	सित-24	अक्टू-24	नव-24
शहरी मांग	यात्री वाहन बिक्री	33.9	21.0	21.7	31.9	27.0	26.0	1.3	4.0	3.1	-2.5	-1.8	-1.4	0.9	4.4
	दोपहिया वाहन बिक्री	20.1	31.3	16.0	26.2	34.6	15.3	30.8	10.1	21.3	12.5	9.3	15.8	14.2	-1.1
ग्रामीण मांग	तीन पहिया वाहन बिक्री	42.1	30.8	30.6	9.5	8.3	4.3	14.5	14.4	12.3	5.1	8.0	7.1	-0.2	-1.3
	ट्रैक्टर बिक्री	-4.3	6.4	-19.8	-15.3	-30.6	-23.1	-3.0	0.0	3.6	1.6	-5.8	3.7	22.4	-1.3
व्यापार, होटल, यातायात, संचार	वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री		3.2			-3.8			3.5			-11.0			
	रेलवे माल यातायात	8.5	4.3	6.4	6.4	10.1	8.6	1.4	3.7	10.1	4.5	0.0		1.5	
	पोर्ट कार्गो यातायात	13.8	16.9	0.6	3.2	2.1	2.7	1.3	3.8	6.8	5.9	6.7	5.8	-3.2	-5.0
	घरेलू हवाई कार्गो यातायात*	10.6	9.0	8.7	10.0	11.5	8.7	0.3	10.3	10.3	8.8	0.6	14.0	8.9	-28.5
	अंतर्राष्ट्रीय एयर कार्गो यातायात*	15.0	4.9	12.2	19.3	30.2	22.5	16.2	19.2	19.6	24.4	20.7	20.5	18.4	3.2
	घरेलू हवाई यात्री यातायात *	10.7	8.7	8.1	5.0	5.8	4.7	3.8	5.9	6.9	7.6	6.7	7.4	9.6	13.6
	अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्री यातायात *	17.5	19.8	18.1	17.0	19.3	15.0	16.8	19.6	11.3	8.8	11.1	11.2	10.3	8.7
	जीएसटी ई-वे बिल (कुल)	30.5	8.5	13.2	16.4	18.9	13.9	14.5	17.0	16.3	19.2	12.9	18.5	16.9	16.3
	जीएसटी ई-वे बिल (अंतरा-राज्यीय)	30.0	22.7	14.2	17.9	21.1	15.8	17.3	18.9	16.4	19.0	13.1	19.0	18.3	5.4
	जीएसटी ई-वे बिल (अंतर-राज्यीय)	31.2	-16.2	11.4	13.8	15.0	10.7	9.6	13.6	16.3	19.6	12.5	17.7	14.4	44.1
	होटल बुकिंग	9.3	-8.6	1.6	2.6	1.8	2.7	-1.4	-2.6	-3.1	3.6	0.7	2.1	-5.3	
	प्रति कमरा औसत राजस्व	14.8	15.9	12.8	11.0	4.1	6.7	4.8	1.8	2.8	7.6	5.2	3.5	4.8	
	पर्यटक आगमन	19.8	16.8	7.8	10.4	15.8	8.0	7.7	0.3	9.0	-1.3	-4.2			
विनिर्माण	निर्माण इस्पात की खपत	15.3	14.5	13.7	12.3	7.0	12.5	11.5	13.0	21.1	13.8	10.3	11.8	8.9	10.0
	सीमेंट उत्पादन	17.0	-4.8	3.8	4.0	7.8	10.6	0.2	-0.6	1.9	5.5	-3.0	7.2	3.3	
पीएमआई सूचकांक	सेवाएं	58.4	56.9	59.0	61.8	60.6	61.2	60.8	60.2	60.5	60.3	60.9	57.7	58.5	58.4

<< संकुचन ----- प्रसार >>

टिप्पणी: #: डेटा स्तरों के आधार पर है। *: नवंबर 2024 के डेटा दैनिक आंकड़ों के मासिक औसत पर आधारित हैं। जुलाई-2021 से अब तक की अवधि के लिए प्रत्येक संकेतक के लिए हीट-मैप का निर्माण किया गया है।

स्रोत: एसआईएम: रेल मंत्रालय; ट्रैक्टर एवं मशीनीकरण संघ: भारतीय बंदरगाह संघ; आर्थिक सलाहकार कार्यालय; जीएसटीएन; भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण; एचवीएस एनारॉक; पर्यटन मंत्रालय; संयुक्त संयंत्र समिति; तथा आईएचएस मार्किट।

मुद्रास्फीति

अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई)²² में साल-दर-साल बदलाव के आधार पर मापी गई हेडलाइन मुद्रास्फीति अक्तूबर 2024 में 6.2 प्रतिशत से नवंबर 2024 में 5.5 प्रतिशत तक गिर गई (चार्ट III.31)। मुद्रास्फीति में लगभग 70 आधार अंकों (बीपीएस) की गिरावट, कीमतों में महीने-दर-महीने (एमओएम) लगभग 15 बीपीएस की गिरावट और लगभग 55 बीपीएस के अनुकूल आधार प्रभाव के कारण हुई। सीपीआई खाद्य और सीपीआई ईंधन समूहों ने महीने के दौरान क्रमशः (-) 50 बीपीएस और (-) 10 बीपीएस की ऋणात्मक गति दर्ज की, जबकि सीपीआई कोर (खाद्य और ईंधन को छोड़कर) समूह ने लगभग 20 बीपीएस की धनात्मक गति दर्ज की।

नवंबर में खाद्य मुद्रास्फीति घटकर 8.2 प्रतिशत रह गई, जो अक्तूबर में 9.7 प्रतिशत थी। उप-समूहों के संदर्भ में, सब्जियों, दालों और उनके उत्पादों, फलों और चीनी में मुद्रास्फीति में उल्लेखनीय कमी देखी गई, जबकि खाद्य तेलों और वसा, मांस और मछली तथा तैयार भोजन में मुद्रास्फीति बढ़ी। अनाज और गैर-अल्कोहल पेय समूह में मुद्रास्फीति स्थिर रही, जबकि मसालों की कीमतों में गिरावट और अधिक हो गई (चार्ट III.32)।

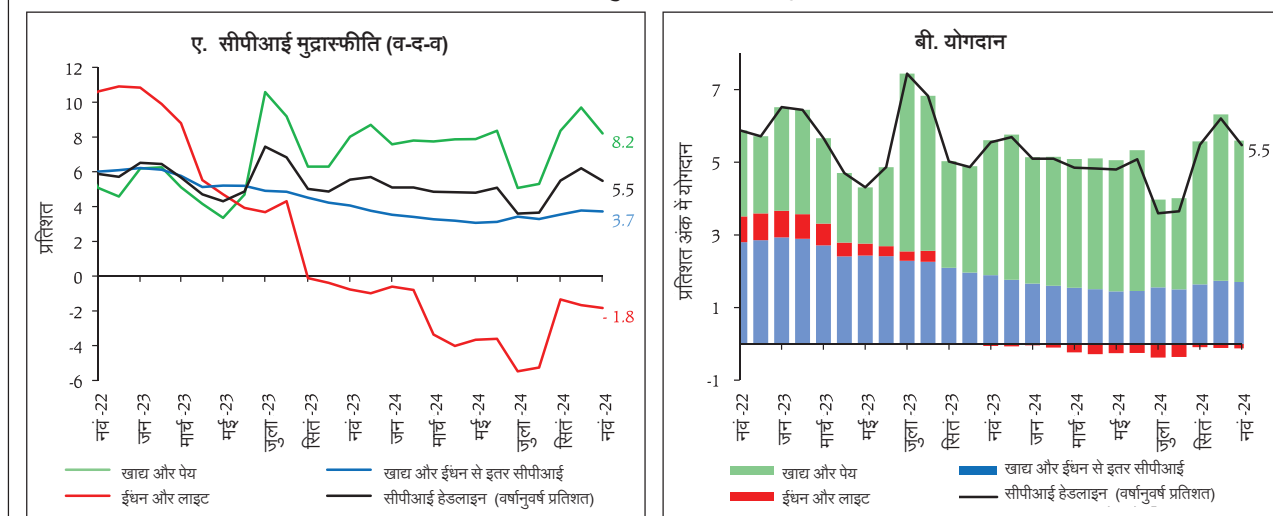
ईंधन और बिजली क्षेत्र में अवस्फीति नवंबर में बढ़कर (-) 1.8 प्रतिशत हो गई, जो अक्तूबर में (-) 1.7 प्रतिशत थी। ऐसा केरोसीन और एलपीजी में अपस्फीति की उच्च दर तथा बिजली में मुद्रास्फीति की कम दर के कारण हुआ।

नवंबर 2024 में कोर मुद्रास्फीति अक्तूबर में 3.8 प्रतिशत से कम होकर 3.7 प्रतिशत हो गई। उप-समूहों में, परिवहन और संचार, व्यक्तिगत देखभाल और प्रभाव, तथा पान, तंबाकू और मादक पदार्थों में मुद्रास्फीति में कमी देखी गई, जबकि स्वास्थ्य, शिक्षा और कपड़े और जूते के लिए मुद्रास्फीति स्थिर रही। हालाँकि, आवास, घूमना-फिरना और मनोरंजन, और घरेलू सामान और सेवाओं में मुद्रास्फीति में वृद्धि दर्ज की गई (चार्ट III.33)।

क्षेत्रीय वितरण के संदर्भ में, नवंबर में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में मुद्रास्फीति कम हुई, ग्रामीण मुद्रास्फीति 6.0 प्रतिशत रही जो शहरी मुद्रास्फीति 4.8 प्रतिशत से अधिक थी। अधिकांश राज्यों में मुद्रास्फीति 4 से 6 प्रतिशत के बीच रही (चार्ट III.34)।

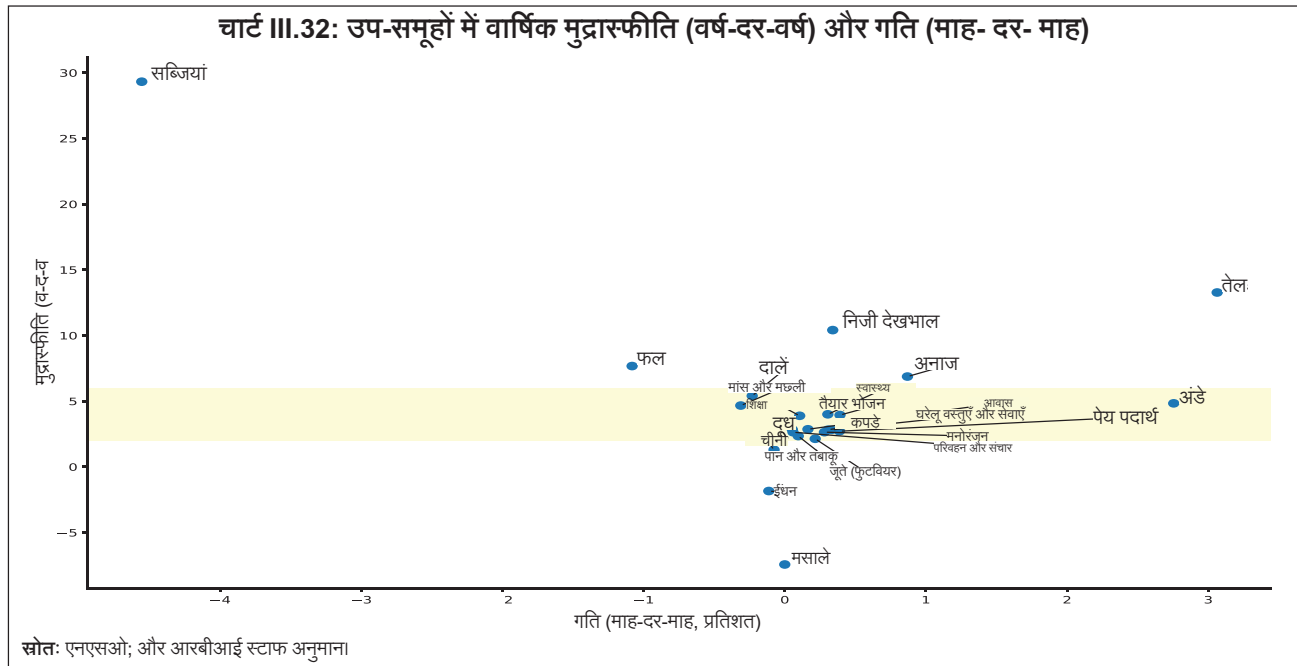
दिसंबर के लिए अब तक (19 तारीख तक) उच्च आवृत्ति वाले खाद्य मूल्य डेटा में चावल की कीमतों में गिरावट देखी गई,

चार्ट III.31 : सीपीआई मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति और वाहक



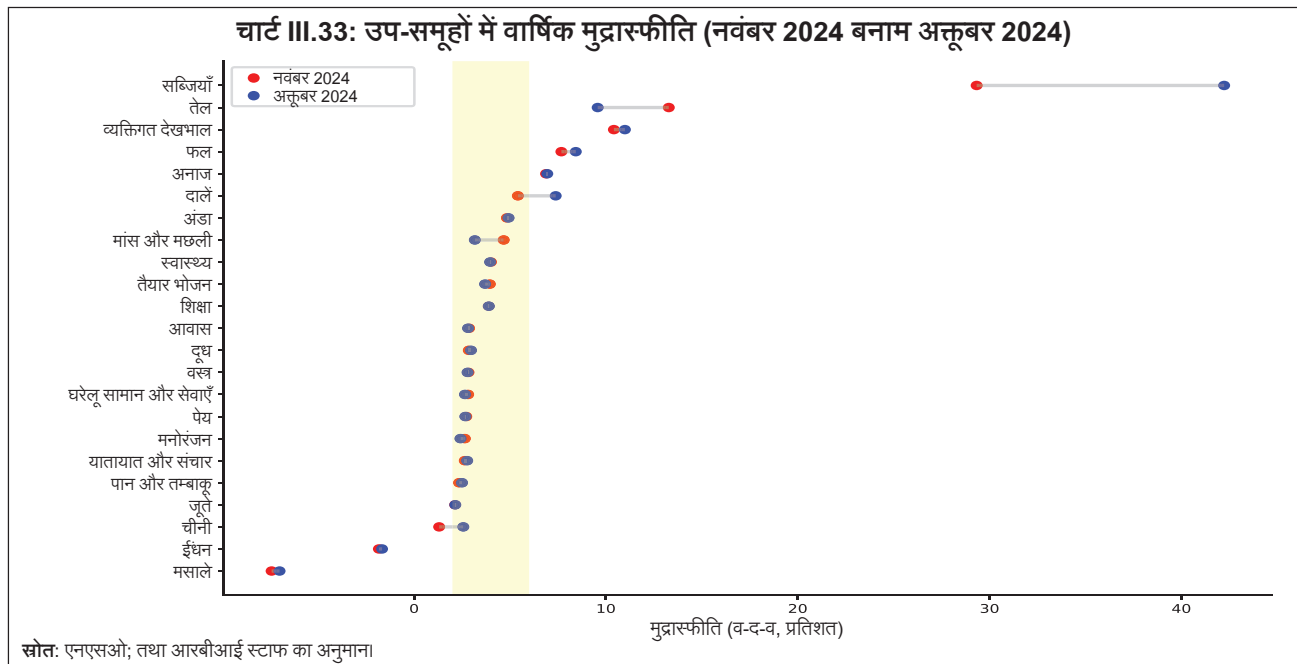
स्रोत : एनएसओ और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

²² एनएसओ द्वारा 12 दिसंबर, 2024 को जारी अनंतिम आंकड़ों के अनुसार।

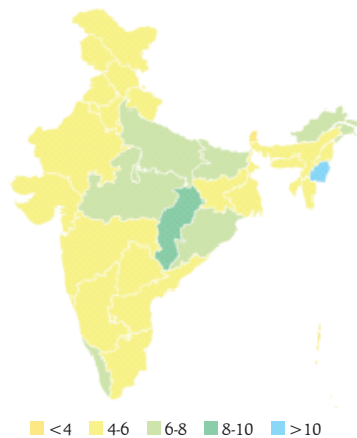


जबकि गेहूं और आटे की कीमतों में मजबूती जारी रही। खाद्य तेल की कीमतों में भी तेजी का दबाव जारी रहा। हालांकि, दालों की कीमतों में व्यापक गिरावट दर्ज की गई। प्रमुख सब्जियों में प्याज और टमाटर की कीमतों में गिरावट आई, जबकि आलू की कीमतें सीमित दायरे में रहीं (चार्ट III.35)।

पेट्रोल, डीजल और केरोसिन की खुदरा बिक्री कीमतें दिसंबर में अब तक (19 तारीख तक) अपरिवर्तित रहीं। इस अवधि के दौरान एलपीजी की कीमतें भी अपरिवर्तित रहीं (सारणी III.2)।



**चार्ट III.34: मुद्रास्फीति का स्थानिक वितरण
नवंबर 2024
(सीपीआई-संयुक्त, वर्ष-दर-वर्ष), (प्रतिशत)**



टिप्पणी: मानचित्र केवल उदाहरणार्थ है।

स्रोत: एनएसओ; तथा आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

पीएमआई के अनुसार, नवंबर में विनिर्माण और सेवा फर्मों में इनपुट लागत में तेज़ वृद्धि हुई, जिसमें सेवाओं में इनपुट लागत में

सारणी III.2: पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें

Item	Unit	घरेलू कीमतें			माह-दर-माह (प्रतिशत)		
		दिस-23	नव-24	दिस-23	नव-24	दिस-23	दिस-23
पेट्रोल	₹/लीटर	102.92	100.99	101.02	0.0	0.0	
डीज़ल	₹/लीटर	92.72	90.45	90.48	0.0	0.0	
केरोसीन (सब्सिडी वाला)	₹/लीटर	52.09	43.95	43.95	2.4	0.0	
एलपीजी (गैर-सब्सिडी)	₹/सिलेंडर	913.25	813.25	813.25	0.0	0.0	

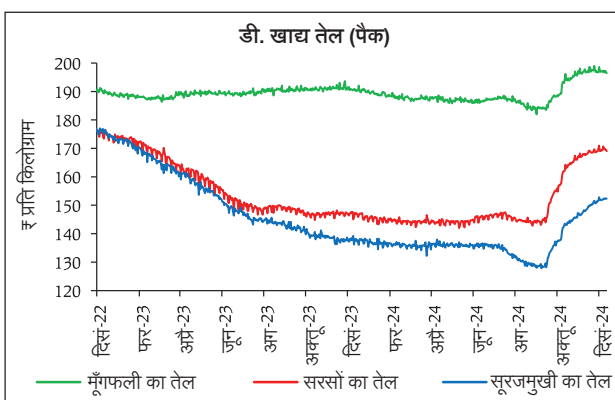
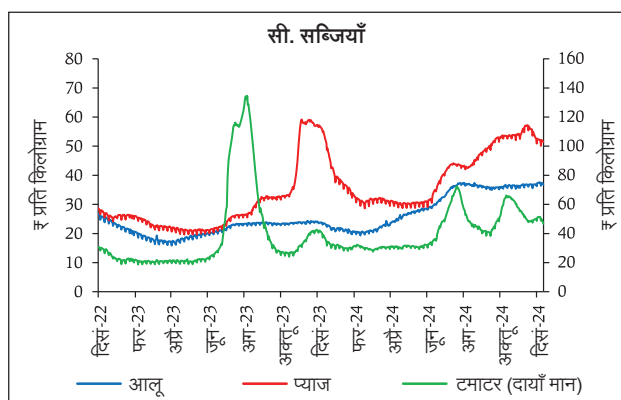
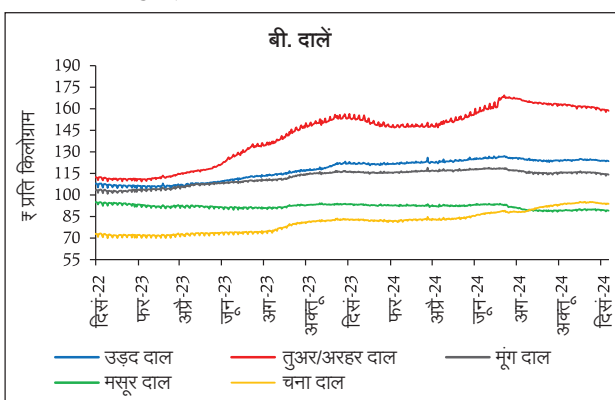
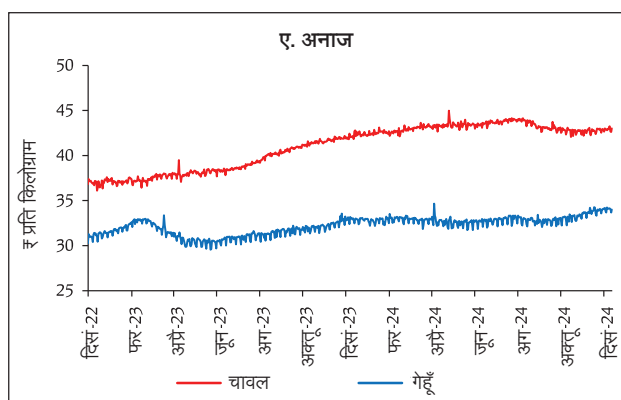
टिप्पणी: 1. *: 1-19 दिसंबर, 2024 की अवधि के लिए।

2. केरोसिन के अलावा, कीमतें चार प्रमुख महानगरों (दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई) में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) की औसत कीमतों को दर्शाती हैं। केरोसिन के लिए, कीमतें कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में सब्सिडी वाली कीमतों का औसत दर्शाती हैं।

स्रोत: आईओसीएल; पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण सेल (पीपीएसी); और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

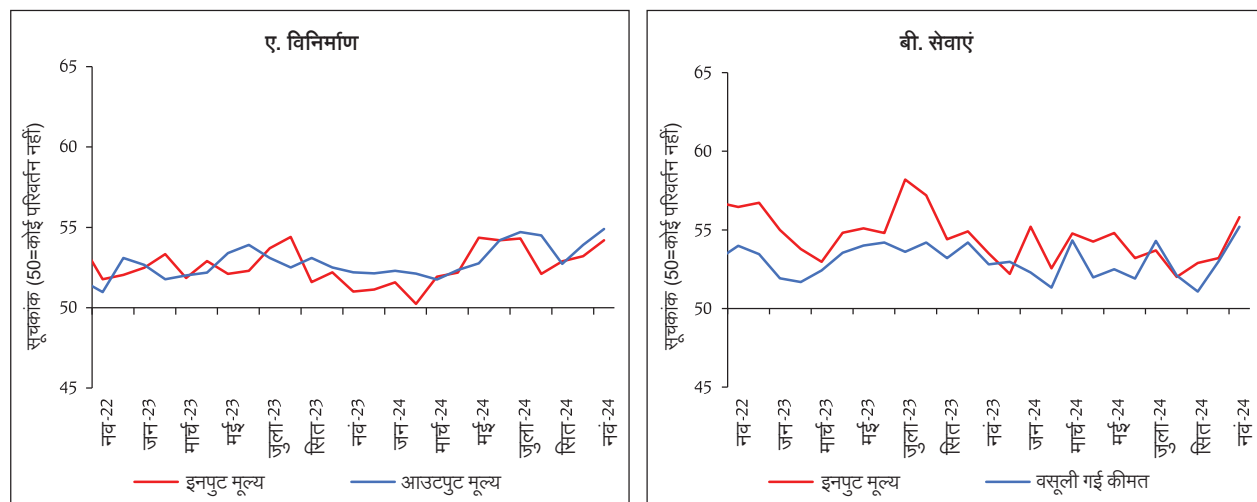
पंद्रह महीनों में सबसे बड़ा विस्तार दर्ज किया गया। विनिर्माण और सेवा फर्मों में बिक्री मूल्य दबाव में भी तेज़ी से वृद्धि हुई, जिसमें

चार्ट III.35: डीसीए आवश्यक वस्तु मूल्य



स्रोत: एनएसओ; तथा आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

चार्ट III.36: पीएमआई: इनपुट और आउटपुट मूल्य



नोट : 50 का स्तर गतिविधि में कोई परिवर्तन नहीं होने को दर्शाता है तथा 50 से ऊपर का स्तर विस्तार और इसके विपरीत को दर्शाता है।
स्रोत : एस एंड पी

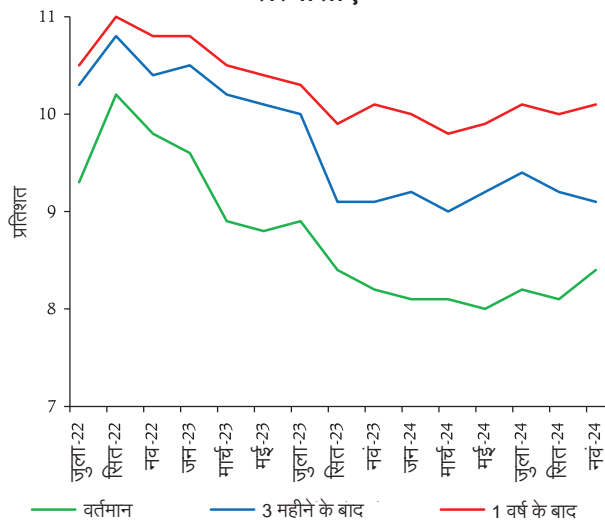
विनिर्माण फर्मों ने पिछले ग्यारह वर्षों में उच्चतम दर दर्ज की, और सेवा फर्मों ने लगभग बारह वर्षों में उत्पादन मूल्य वृद्धि की सबसे तेज़ गति दर्ज की (चार्ट III.36)।

मौजूदा मुद्रास्फीति के बारे में परिवारों की धारणा सितंबर के स्तर से नवंबर 2024 में 30 आधार अंकों (बीपीएस) तक बढ़ गई। उनकी एक साल आगे की मुद्रास्फीति की उम्मीदें 10 बीपीएस बढ़ गईं, जबकि तीन महीने आगे की उम्मीदें 10

बीपीएस तक गिर गईं (चार्ट III.37)।

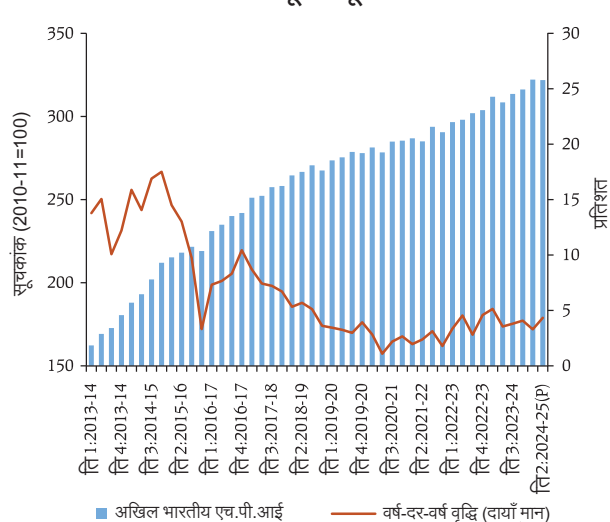
10 प्रमुख शहरों से संपत्ति पंजीकरण डेटा के आधार पर अखिल भारतीय आवास मूल्य सूचकांक (एचपीआई) में 2024-25 की दूसरी तिमाही में 4.3 प्रतिशत (वर्ष दर वर्ष) की वृद्धि हुई, जबकि पिछली तिमाही में यह 3.3 प्रतिशत और एक वर्ष पहले 3.5 प्रतिशत थी (चार्ट III.38)।

चार्ट III.37: परिवारों की औसत मुद्रास्फीति प्रत्याशाएं



स्रोत: घरेलू मुद्रास्फीति प्रत्याशा सर्वेक्षण, आरबीआई

चार्ट III.38: आवास मूल्य सूचकांक में परिवर्तन



टिप्पणी : पी. डेटा अनंतिम हैं

स्रोत: राज्य सरकारों के पंजीकरण प्राधिकरण; तथा भारतीय रिज़र्व बैंक।

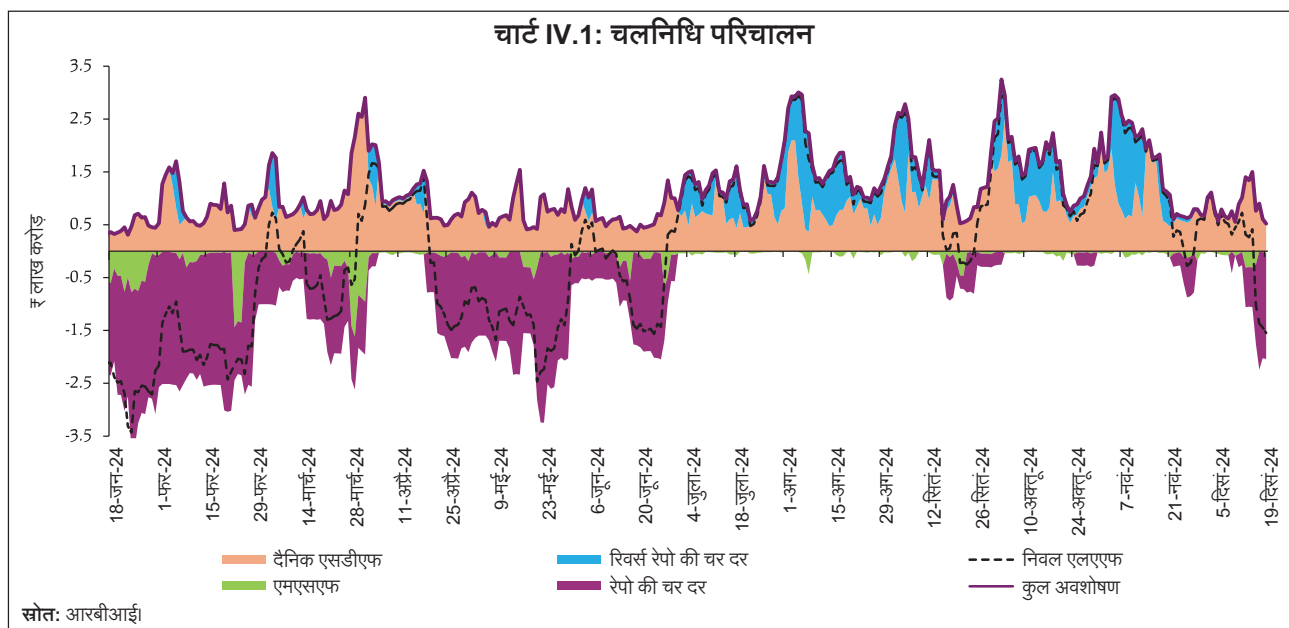
IV. वित्तीय स्थितियाँ

नवंबर 2024 की दूसरी छमाही में प्रणालीगत चलनिधि में कमी आई, क्योंकि माल और सेवा कर (जीएसटी) संग्रह के कारण सरकारी नकदी शेष में वृद्धि हुई, प्रचलन में मुद्रा में वृद्धि हुई और पूंजी बहिर्वाह हुआ। नवंबर के अंतिम सप्ताह के दौरान यह घाटे में बदल गया, इससे पहले कि दिसंबर की शुरुआत में अधिक सरकारी खर्च के कारण इसमें कमी आए। अग्रिम कर भुगतान के कारण 16-19 दिसंबर, 2024 के दौरान प्रणालीगत चलनिधि फिर से घाटे में बदल गई। हालांकि, औसतन, नवंबर की दूसरी छमाही और दिसंबर की शुरुआत में प्रणालीगत चलनिधि अधिशेष में रही, जिसमें चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत औसत दैनिक निवल अवशोषण 16 अक्तूबर से 15 नवंबर, 2024 के दौरान ₹1.72 लाख करोड़ से घटकर 16 नवंबर से 19 दिसंबर, 2024 के दौरान ₹0.39 लाख करोड़ हो गया (चार्ट IV.1)। नवंबर के दूसरे पखवाड़े में एक मुख्य और तीन फाइन-ट्यूनिंग वेरिबल रेट रिवर्स रेपो (वीआरआरआर) परिचालन किए गए, जिससे बैंकिंग प्रणाली से कुल मिलाकर ₹0.99 लाख करोड़ की रकम प्राप्त हुई। हालांकि, बड़े जीएसटी बहिर्वाह के कारण अस्थायी नकदी की तंगी को कम करने के लिए, 22-28 नवंबर, 2024 के दौरान 1-6 दिनों की परिपक्वता अवधि वाले चार फाइन-ट्यूनिंग

वेरिबल रेट रेपो (वीआरआर) परिचालन किए गए, जिससे बैंकिंग प्रणाली में कुल मिलाकर ₹1.0 लाख करोड़ की रकम आई। इसके अलावा, अग्रिम कर भुगतान के कारण नकदी की तंगी को देखते हुए, रिजर्व बैंक ने 09-20 दिसंबर, 2024 के दौरान एक मुख्य और छह फाइन-ट्यूनिंग वीआरआर परिचालन किए, जिससे बैंकिंग प्रणाली में कुल मिलाकर ₹4.4 लाख करोड़ की रकम आई।

जुलाई-नवंबर के दौरान प्रणाली में चलनिधि पर्याप्त रही, लेकिन करों के बहिर्वाह, प्रचलन में मुद्रा में वृद्धि और पूंजी प्रवाह में अस्थिरता के कारण आगामी महीनों में इसमें कमी आने की संभावना है। संभावित चलनिधि दबाव को कम करने के लिए, सभी बैंकों के नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) को 14 दिसंबर, 2024 और 28 दिसंबर, 2024 से शुरू होने वाले पखवाड़े से 25 बीपीएस प्रत्येक के दो बराबर किस्तों में घटाकर निवल मांग और समय देयताओं (एनडीटीएल) का 4.0 प्रतिशत कर दिया गया, इस प्रकार बैंकिंग प्रणाली में संचयी रूप से लगभग ₹1.16 लाख करोड़ की प्राथमिक चलनिधि जारी की गई।

16 नवंबर से 19 दिसंबर, 2024 के दौरान ₹0.92 लाख करोड़ के औसत कुल अवशोषण में से, स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) के तहत निधियों का निवेश लगभग 88 प्रतिशत रहा। 16 नवंबर से 19 दिसंबर, 2024 के दौरान सीमांत स्थायी सुविधा



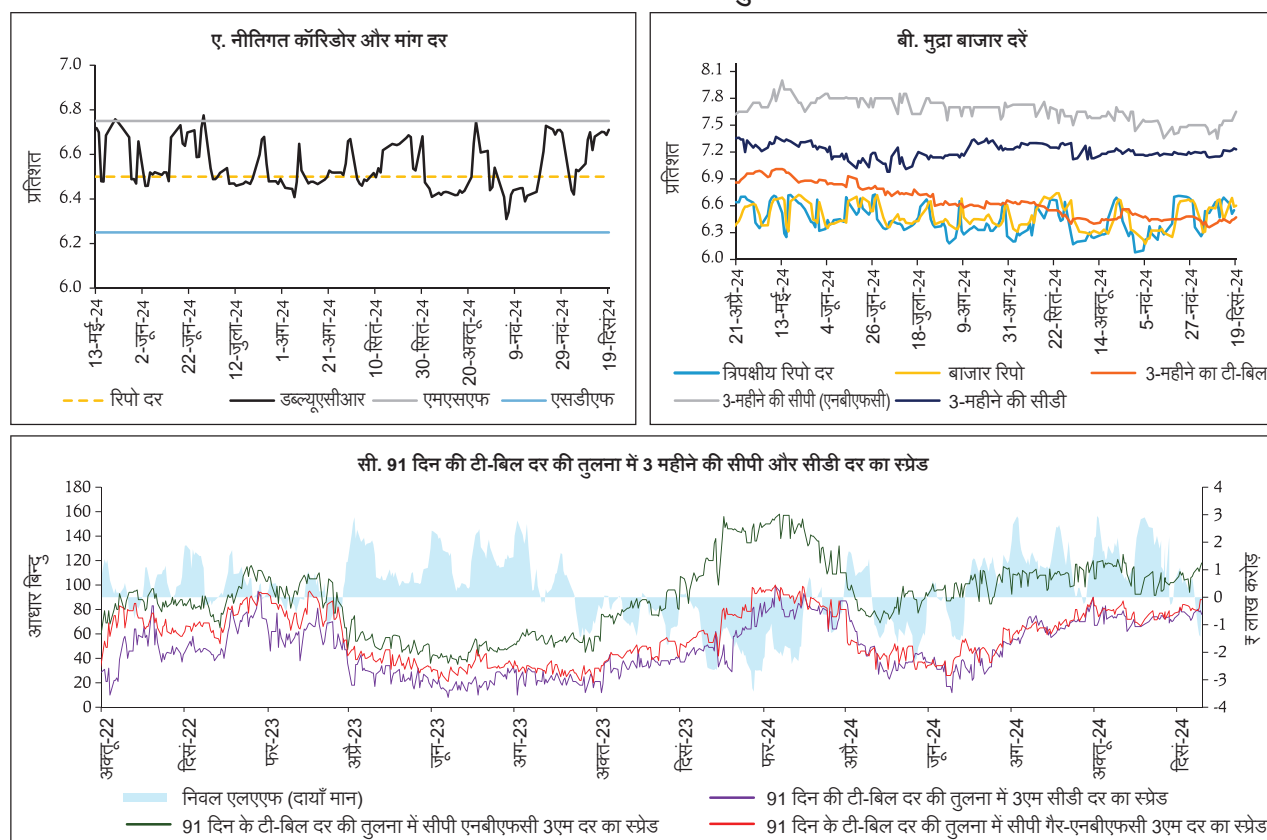
(एमएसएफ) का औसत सहारा ₹0.08 लाख करोड़ पर कम रहा।

एकदिवसीय मुद्रा बाजार में, भारित औसत कॉल दर (डबल्यूएसीआर) एलएएफ कॉरिडोर के भीतर रही, जो 16 नवंबर से 19 दिसंबर, 2024 के दौरान औसतन 6.62 प्रतिशत रही, जो 16 अक्तूबर से 15 नवंबर, 2024 के दौरान 6.48 प्रतिशत से अधिक थी (चार्ट IV.2ए)। डबल्यूएसीआर 22-29 नवंबर और 10-19 दिसंबर के दौरान थोड़े समय के लिए मजबूत हुई, हालांकि यह नीतिगत कॉरिडोर के भीतर रही। संपार्श्विकृत खंड में, त्रिपक्षीय रेपो और बाजार रेपो दोनों दरें 16 नवंबर से 19 दिसंबर, 2024 के दौरान नीतिगत रेपो दर से क्रमशः 6 आधार अंक (बीपीएस) और 5 बीपीएस अधिक रहीं (चार्ट IV.2बी)। द्वितीयक बाजार में, 91-दिवसीय टी-बिल दर पर 3 महीने के सीपी (एनबीएफसी) और सीडी दरों का प्रसार दिसंबर 2024 (19 दिसंबर तक) के दौरान - एक साल पहले 104 बीपीएस और 44

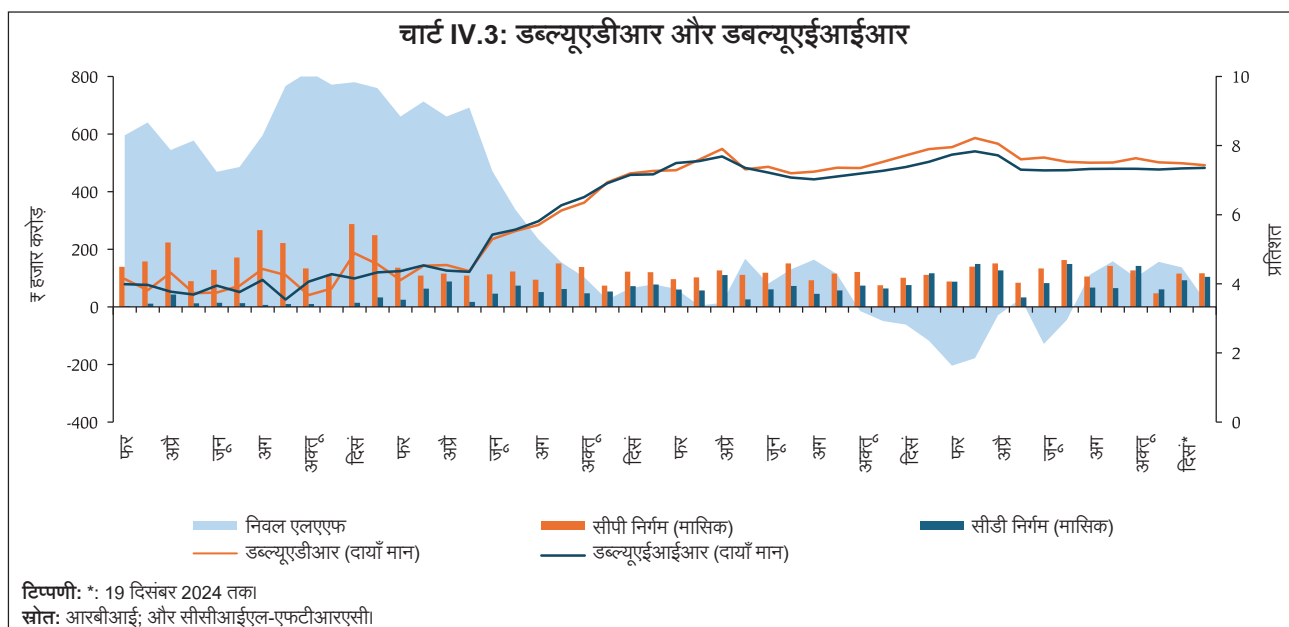
बीपीएस से अधिक क्रमशः 109 बीपीएस और 77 बीपीएस रहा (चार्ट IV.2C)। हालांकि अधिशेष चलनिधि की अवधि के दौरान प्रसार कम हो जाता है, लेकिन हाल के महीनों में मुख्य रूप से दिसंबर की दूसरी छमाही को छोड़कर 91-दिवसीय टी-बिल दरों में गिरावट के कारण वे बढ़ गए हैं।

अल्पावधि मुद्रा बाजार खंड में, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा जारी 3 महीने के ट्रेजरी बिल (टी-बिल) और 3 महीने के वाणिज्यिक पत्र (सीपी) पर प्रतिफल 16 नवंबर से 19 दिसंबर के दौरान पिछले महीने की तुलना में मामूली रूप से कम हुआ। इस अवधि के दौरान 3 महीने के जमा प्रमाणपत्र (सीडी) पर दरें सीमित रहीं (चार्ट IV.2बी)। मुद्रा बाजार में औसत जोखिम प्रीमियम (3 महीने के सीपी और 91 दिन के टी-बिल दरों के बीच विस्तारित) में 3 बीपीएस की गिरावट आई।

चार्ट IV.2 : नीति कॉरिडोर और मुद्रा बाजार दर



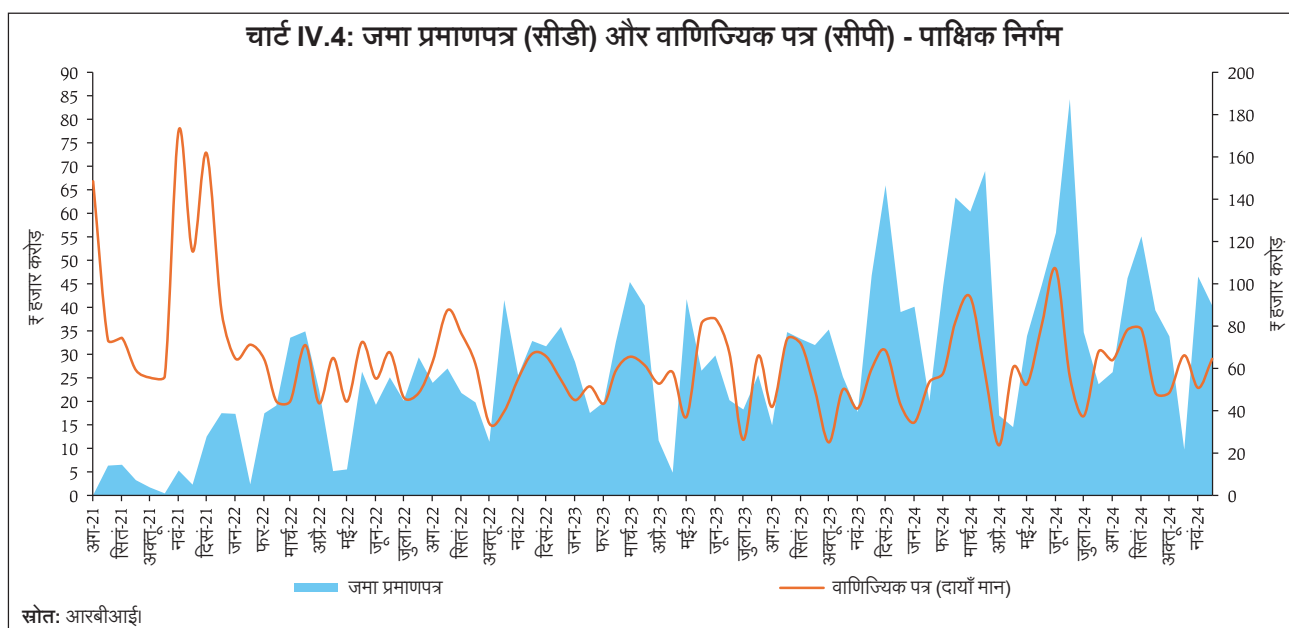
स्रोत: आरबीआई; सीसीआईएल; और ब्लूमबर्ग



दिसंबर 2024 (19 दिसंबर तक) में सीपी की भारत औसत छूट दर (डब्ल्यूएडीआर) 7.43 प्रतिशत रही, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के 7.89 प्रतिशत से कम है, क्योंकि आगे चलकर ब्याज दरें कम रहने की उम्मीद है (चार्ट IV.3)। साथ ही, सीडी की भारत औसत प्रभावी ब्याज दर (डब्ल्यूईआईआर) एक साल पहले के 7.52 प्रतिशत से कम होकर 7.36 प्रतिशत (19 दिसंबर,

2024 तक) हो गई, क्योंकि ऋण और जमा वृद्धि के बीच का अंतर कम हो गया।

प्राथमिक बाजार में, अप्रैल-नवंबर 2024 के दौरान सीडी निर्गम 68 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़कर ₹6.88 लाख करोड़ हो गया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में ₹4.09 लाख करोड़ से काफी अधिक है, जो बैंकों की वित्तपोषण आवश्यकताओं को दर्शाता है (चार्ट IV.4)। 2024-25 (नवंबर तक) के दौरान सीपी



निर्गमन ₹9.85 लाख करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में ₹8.85 लाख करोड़ से अधिक था। नवंबर 2023 में रिजर्व बैंक द्वारा एनबीएफसी को दिए जाने वाले बैंक ऋणों पर जोखिम भार बढ़ाने के साथ, ये संस्थाएँ संसाधन जुटाने के लिए वैकल्पिक बाज़ार साधनों पर निर्भर हो गई हैं।

नवंबर के दूसरे पखवाड़े में 10 वर्षीय जी-सेक प्रतिफल अपेक्षाकृत स्थिर रही, जबकि अमेरिकी खजाना प्रतिफल में मजबूती आई। 2024-25 की दूसरी तिमाही में जीडीपी वृद्धि में अपेक्षा से अधिक मंदी की पृष्ठभूमि में रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति में ढील दिए जाने की उम्मीदों पर बेंचमार्क प्रतिफल 4 दिसंबर, 2024 को लगभग तीन वर्षों में अपने सबसे निचले स्तर पर आ गई (चार्ट IV.5a)। जी-सेक प्रतिफल वक्र अवधि संरचना के मध्य खंड के साथ नीचे की ओर खिसक गया। 16 नवंबर से 19 दिसंबर के दौरान, औसत अवधि स्प्रेड (10-वर्ष माइनस 91-दिवसीय टी-बिल) 36 बीपीएस (चार्ट IV.5b) पर स्थिर रहा।

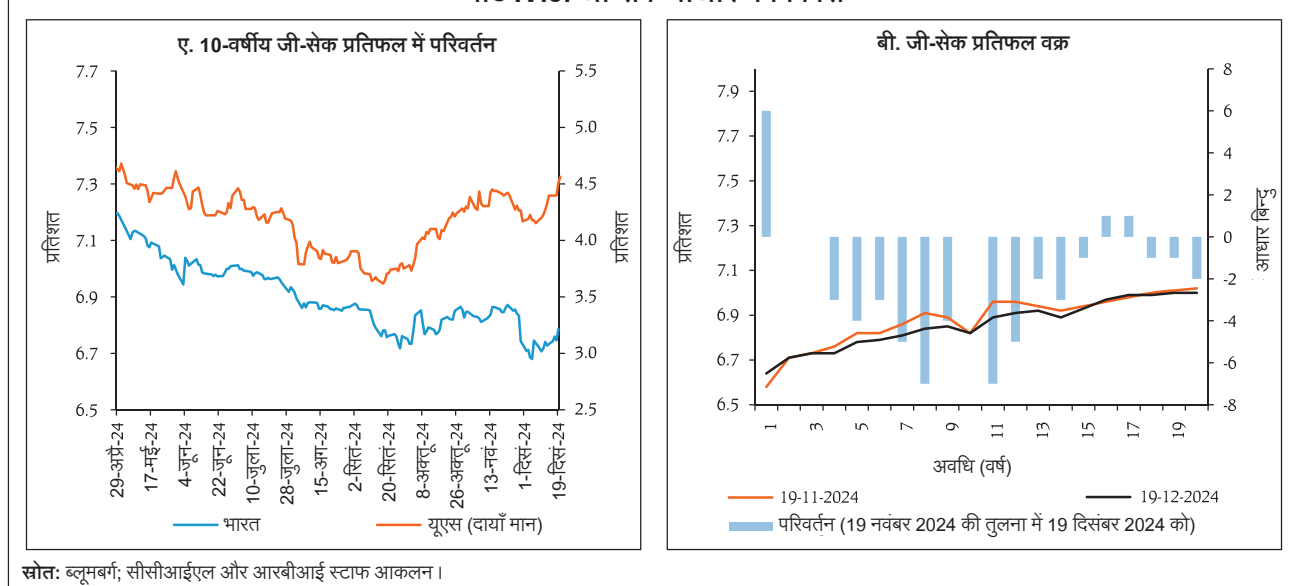
10 वर्षीय भारतीय जी-सेक प्रतिफल का 10 वर्षीय अमेरिकी बॉण्ड पर प्रसार 19 दिसंबर, 2024 को 222 बीपीएस तक गिर गया, जो सितंबर के मध्य में 310 बीपीएस और एक साल पहले 324 बीपीएस था। 29 नवंबर, 2024 के बाद घरेलू

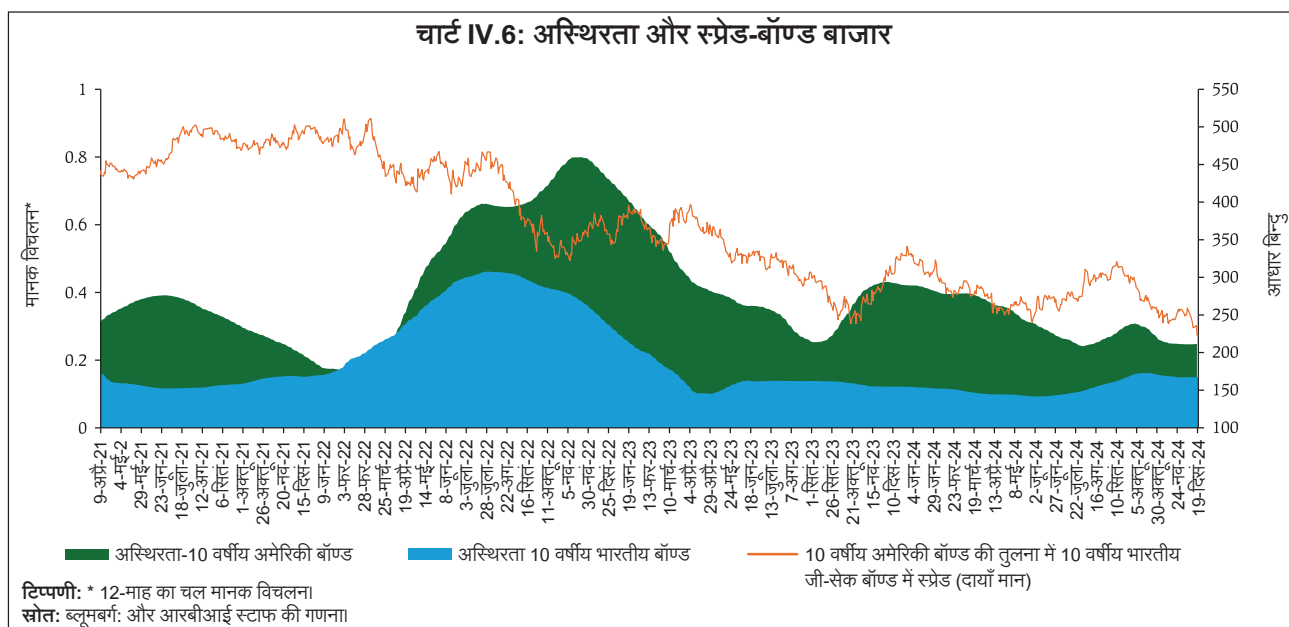
बॉण्ड प्रतिफल में तेजी से गिरावट आई और दिसंबर की शुरुआत में यह तीन साल के निचले स्तर पर पहुंच गया। अक्तूबर और नवंबर में निकासी के बाद दिसंबर 2024 में घरेलू ऋण साधनों में एफपीआई प्रवाह धनात्मक हो गया। भारतीय बॉण्ड बाजार में प्रतिफल की अस्थिरता अमेरिकी खजाना के सापेक्ष कम बनी हुई है (चार्ट IV.6)।

हाल के महीनों में कॉरपोरेट बॉण्ड जारी करने की गति बढ़ गई है क्योंकि कॉरपोरेट्स ने फंडिंग स्रोतों में विविधता लाने के लिए कम प्रतिफल का लाभ उठाया है। कुल मिलाकर, 2024-25 (नवंबर तक) के दौरान कॉरपोरेट बॉण्ड जारी करना पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान ₹4.99 लाख करोड़ की तुलना में ₹6.06 लाख करोड़ अधिक था। रेटिंग और अवधि स्पेक्ट्रम में कॉरपोरेट बॉण्ड के प्रतिफल में आम तौर पर गिरावट आई, जबकि संबंधित जोखिम प्रीमियम आम तौर पर 18 नवंबर से 18 दिसंबर, 2024 के दौरान बढ़ गया (सारणी IV.1)।

13 दिसंबर, 2024 तक रिजर्व मनी (आरएम) में 6.3 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि दर्ज की गई (एक वर्ष पहले 6.4 प्रतिशत) [चार्ट IV.7]। आरएम के सबसे बड़े घटक, प्रचलन में मुद्रा (सीआईसी) में वृद्धि 13 दिसंबर, 2024 तक 6.1 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) रही, जबकि एक वर्ष पहले यह 3.9 प्रतिशत थी।

चार्ट IV.5: जी-सेक बाजार में विकास





स्रोत पक्ष (आस्तियों) पर, आरएम में रिज़र्व बैंक की निवल घरेलू आस्तियां (एनडीए) और निवल विदेशी आस्तियां (एनएफए) शामिल हैं। 13 दिसंबर, 2024 तक विदेशी मुद्रा आस्तियों में 5.2 प्रतिशत (वर्ष दर वर्ष) की वृद्धि हुई। सोने - एनएफए का एक प्रमुख घटक - में 46.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण सोने की कीमतों से पुनर्मूल्यांकन लाभ था। परिणामस्वरूप, एनएफए में इसकी हिस्सेदारी अक्टूबर 2023 के अंत में 8.1 प्रतिशत से बढ़कर 13 दिसंबर, 2024 तक 10.7 प्रतिशत हो गई (चार्ट IV.8)।

मुद्रा आपूर्ति (एम₃) में 10.0 प्रतिशत (वर्ष दर वर्ष) की वृद्धि हुई (एक वर्ष पहले 11.2 प्रतिशत)।²³ बैंकों के पास कुल जमा राशि, जो एम3 का लगभग 87 प्रतिशत है, में 10.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई (एक वर्ष पहले 12.2 प्रतिशत)।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की ऋण वृद्धि 29 नवंबर 2024 तक 11.8 प्रतिशत तक कम हो गई (एक वर्ष पहले 16.3 प्रतिशत) [चार्ट IV.9]।

सारणी IV.1: वित्तीय बाजार - दरें और प्रसार

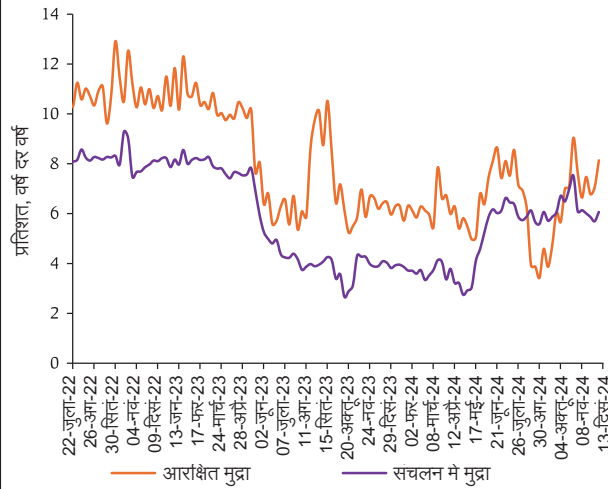
लिखत	ब्याज दरें (प्रतिशत)			प्रसार (आधार अंक)		
	18 अक्टू, 2024 – 18 नव, 2024	18 नवंबर, 2024 18 दिसंबर, 2024	उतार-चढ़ाव	(संबंधित जोखिम-मुक्त दर की तुलना में)		
				18 अक्टू, 2024 – 18 नव, 2024	18 नवंबर, 2024 18 दिसंबर, 2024	उतार-चढ़ाव
1	2	3	(4 = 3-2)	5	6	(7 = 6-5)
कॉरपोरेट बॉण्ड						
(i) एएए (1-वर्ष)	7.79	7.82	3	111	114	3
(ii) एएए (3-वर्ष)	7.75	7.68	-7	90	88	-2
(iii) एएए (5-वर्ष)	7.61	7.60	-1	72	75	3
(iv) एए (3-वर्ष)	8.50	8.47	-3	166	167	1
(v) बीबीबी- (3-वर्ष)	12.14	12.12	-2	530	533	3

टिप्पणी: प्रतिफल और स्प्रेड की गणना संबंधित अवधि के औसत के रूप में की जाती है।

स्रोत: एफआईएमएमडीए; और ब्लूमबर्ग।

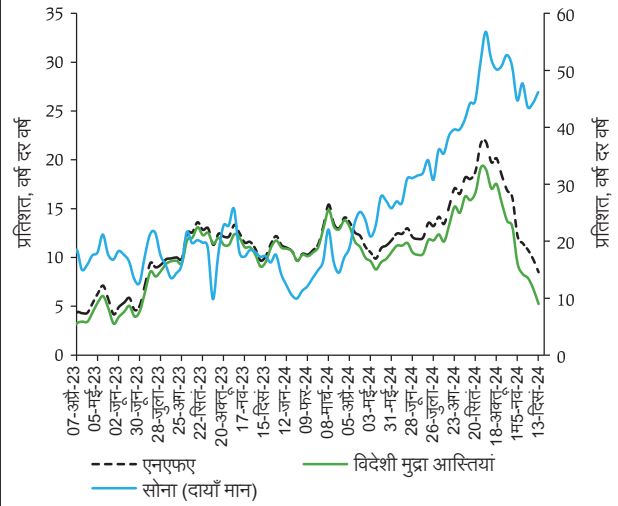
²³ किसी गैर-बैंक के बैंक में विलय के प्रभाव को छोड़कर (1 जुलाई, 2023 से प्रभावी)।

चार्ट IV.7: आरक्षित मुद्रा और संचलन में मुद्रा



टिप्पणी: आरक्षित मुद्रा का नवीनतम डेटा 13 दिसंबर 2024 तक का है।
स्रोत: आरबीआई

चार्ट IV.8: आरबीआई की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (एनएफए) - वृद्धि



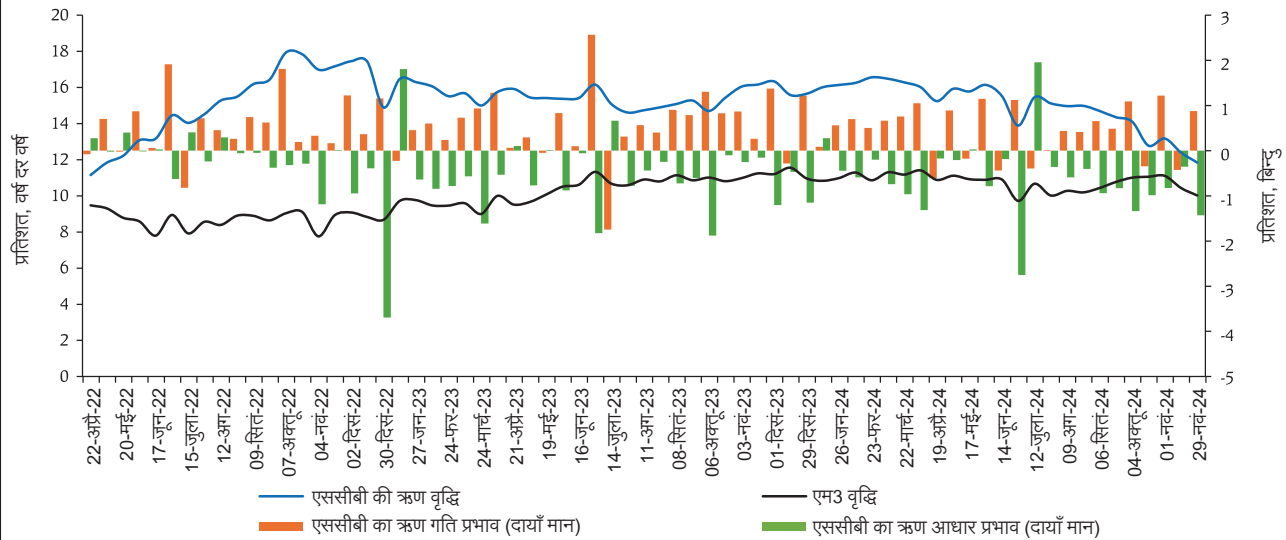
स्रोत: आरबीआई

व्यक्तिगत ऋण (आवास और गैर-आवास) सितंबर 2024 तक समग्र ऋण विस्तार का प्रमुख चालक बने रहे; उद्योग को ऋण में दोहरे अंक की वृद्धि दर्ज की गई (चार्ट IV.10)।

एससीबी द्वारा दिया जाने वाला ऋण, जो कुल बैंक ऋण का लगभग एक चौथाई है, पिछली तिमाही में दर्ज की गई उच्च वृद्धि

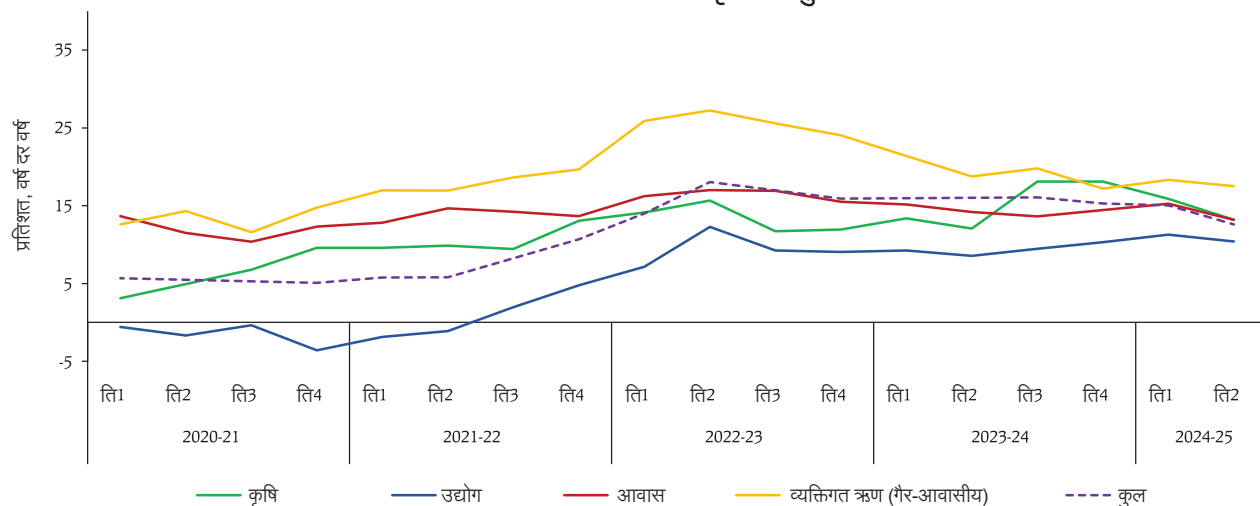
से 2024-25 की दूसरी तिमाही के दौरान कम हो गया (चार्ट IV.11)। जबकि कार्यशील पूंजी ऋणों में वृद्धि लगातार दूसरी तिमाही में तेज हुई, सावधि ऋणों में वृद्धि में कमी जारी रही (चार्ट IV.12)।

चार्ट IV.9: एम3 वृद्धि और एससीबी के ऋण वृद्धि का आधार प्रभाव और गति



स्रोत: आरबीआई

चार्ट IV.10: बैंक ऋण में वार्षिक वृद्धि - प्रमुख क्षेत्रक



टिप्पणी: तुलना के उद्देश्य से, ति2, ति3, ति4: 2023-24 और ति1: 2024-25 के वृद्धि के आंकड़ों की गणना बैंक के गैर-बैंक के साथ विलय को समायोजित करके की गई है।

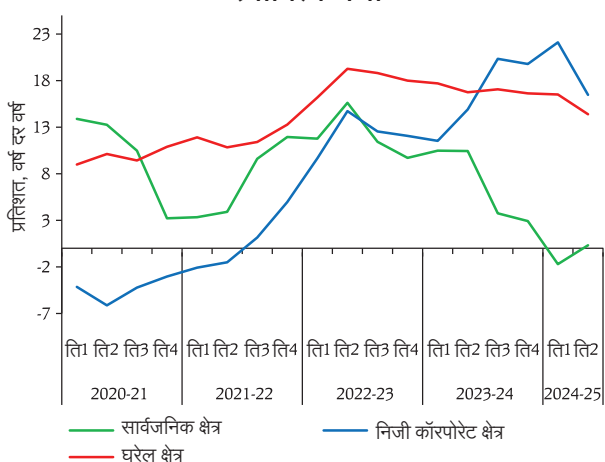
स्रोत: आरबीआई

एससीबी की जमा वृद्धि (विलय के प्रभाव को छोड़कर) अगस्त 2024 के अंत में 11.3 प्रतिशत से घटकर 29 नवंबर 2024 को 11.1 प्रतिशत हो गई (चार्ट IV.13)।

हाल ही में मौद्रिक नीति सख्त करने के चक्र के दौरान, चालू खाता और बचत खाता (सीएसए) जमा राशियों में वृद्धि सावधि जमा राशियों में वृद्धि से आगे निकल गई। कुल जमा राशियों

में सावधि जमा राशियों की हिस्सेदारी सितंबर 2024 में बढ़कर 61.4 प्रतिशत हो गई, जो एक साल पहले 59.8 प्रतिशत और मार्च 2023 में 57.2 प्रतिशत थी (चार्ट IV.14)। कुल सावधि जमा राशियों में 7 प्रतिशत से अधिक ब्याज दर वाली सावधि जमा राशियों की हिस्सेदारी सितंबर 2024 में बढ़कर 68.8 प्रतिशत हो गई, जो एक साल पहले 54.7 प्रतिशत, मार्च

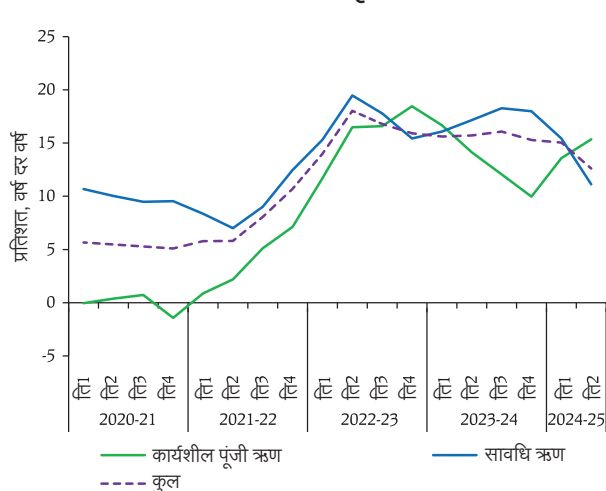
चार्ट IV.11: वार्षिक ऋण वृद्धि - उधारकर्ताओं की प्रमुख स्वामित्व श्रेणी



टिप्पणी: तुलना के उद्देश्य से, ति2, ति3, ति4: 2023-24 और ति1: 2024-25 के वृद्धि के आंकड़ों की गणना बैंक के गैर-बैंक के साथ विलय को समायोजित करके की गई है।

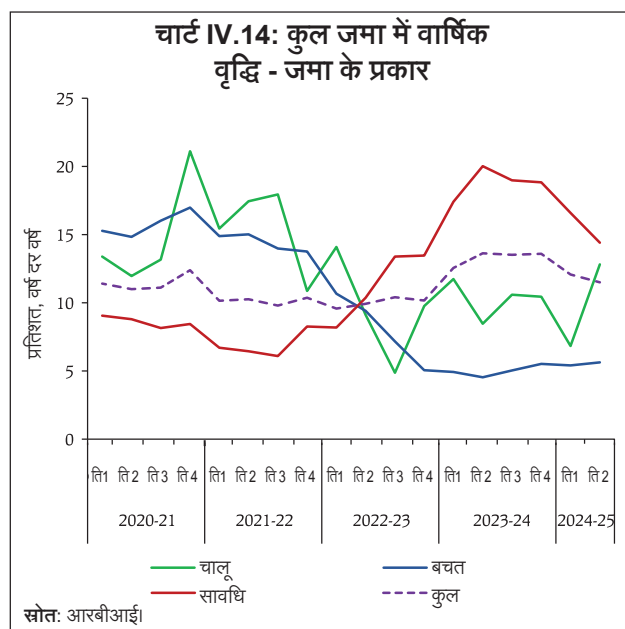
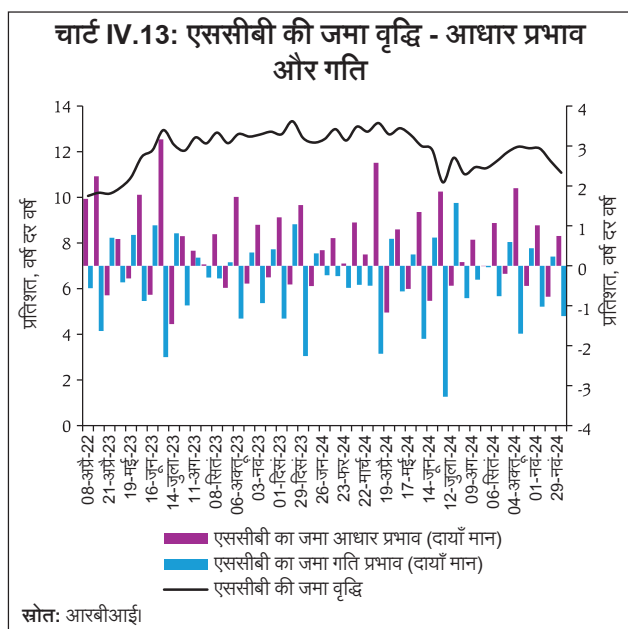
स्रोत: आरबीआई

चार्ट IV.12: वार्षिक ऋण वृद्धि - ऋण प्रकार



टिप्पणी: तुलना के उद्देश्य से, ति2, ति3, ति4: 2023-24 और ति1: 2024-25 के वृद्धि के आंकड़ों की गणना बैंक के गैर-बैंक के साथ विलय को समायोजित करके की गई है।

स्रोत: आरबीआई

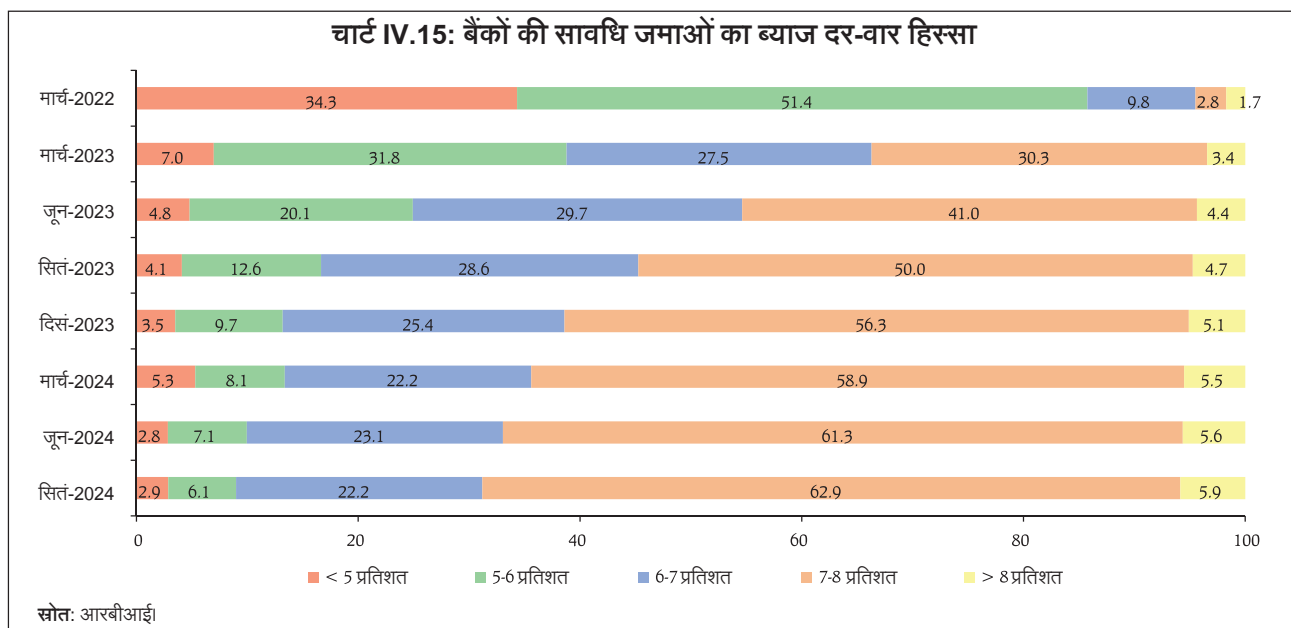


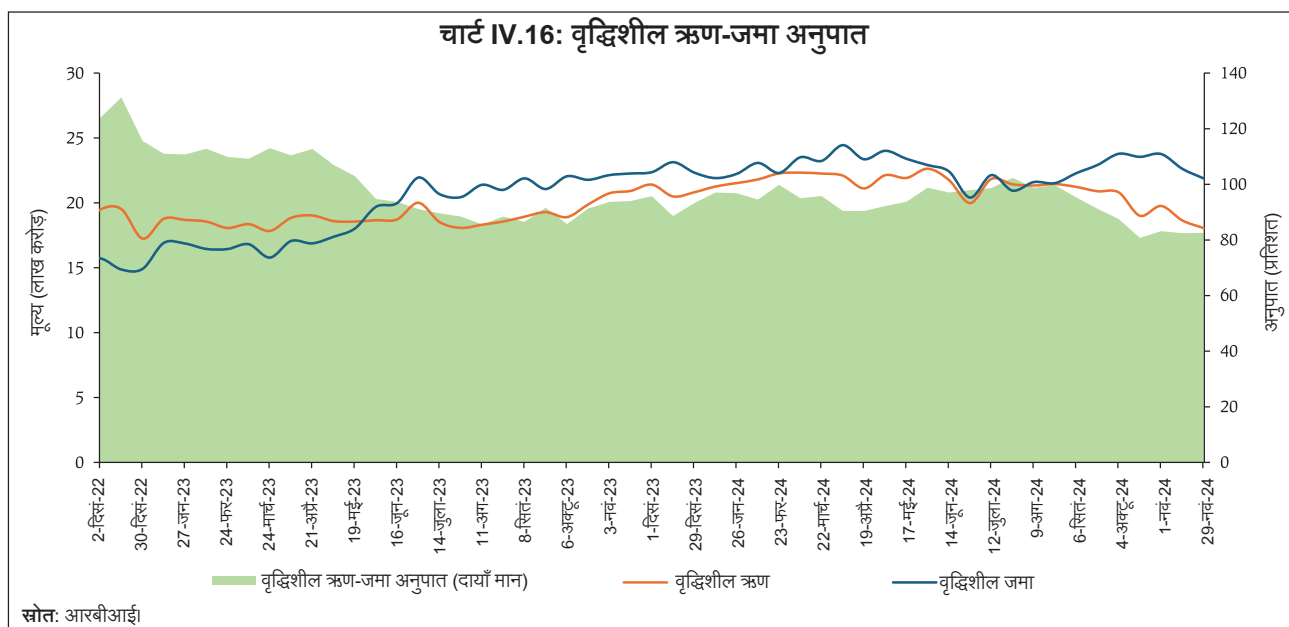
2023 में 33.7 प्रतिशत और मार्च 2022 में 4.5 प्रतिशत थी (चार्ट IV.15)।

एससीबी का वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात मार्च 2024 के अंत में 95.8 से घटकर 29 नवंबर, 2024 को 82.5 हो गया, जिसमें वृद्धिशील जमा अगस्त-नवंबर 2024 (29 नवंबर तक) के दौरान वृद्धिशील ऋण से आगे निकल गया [चार्ट IV.16]। सीआरआर और एसएलआर के लिए क्रमशः 4.5 प्रतिशत और

18 प्रतिशत की वैधानिक आवश्यकताओं के साथ, 29 नवंबर, 2024 तक ऋण विस्तार के लिए बैंकिंग प्रणाली के पास लगभग 77 प्रतिशत जमा उपलब्ध था।

मई 2022 से नीतिगत रेपो दर में 250 बीपीएस की वृद्धि के प्रतिक्रिया में, बैंकों ने अपने रेपो लिंकड एक्सटर्नल बेंचमार्क-आधारित उधार दरों (ईबीएलआर) को इसी परिमाण से संशोधित किया है। मई 2022 से नवंबर 2024 के दौरान निधि-आधारित

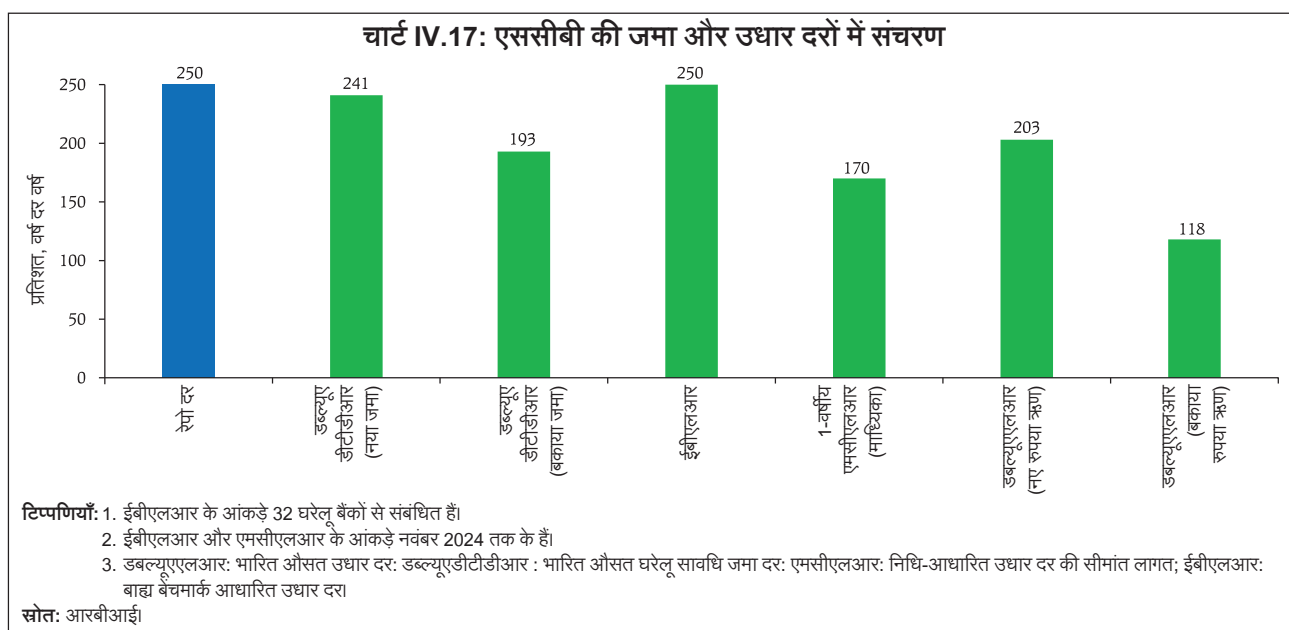




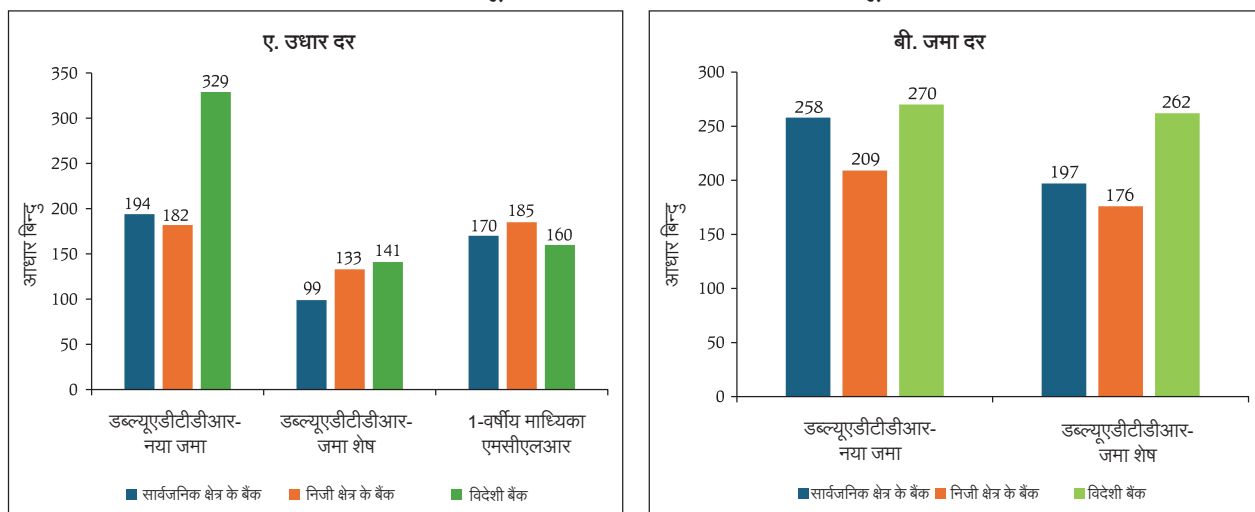
उधार दर (एमसीएलआर) की औसत 1-वर्षीय सीमांत लागत में 170 बीपीएस की वृद्धि हुई। नतीजतन, मई 2022 से अक्तूबर 2024 के दौरान नए और बकाया रुपया ऋणों पर भारित औसत उधार दरों (डब्ल्यूएलआर) में क्रमशः 203 बीपीएस और 118 बीपीएस की वृद्धि हुई। जमा पक्ष पर, इसी अवधि के दौरान नए और बकाया जमा पर भारित औसत घरेलू सावधि जमा दरों

(डब्ल्यूएडीटीडीआर) में क्रमशः 241 बीपीएस और 193 बीपीएस की वृद्धि हुई (चार्ट IV.17)।

बैंक समूहों में संचरण से संकेत मिलता है कि नए रुपए ऋणों पर डब्ल्यूएलआर में वृद्धि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के लिए निजी बैंकों (पीवीबी) की तुलना में अधिक थी। हालांकि, बकाया ऋणों के मामले में, पीएसबी के बीच संचरण कम था। जमाराशियों में, मई 2022 और अक्तूबर 2024 के दौरान



चार्ट IV.18: बैंक समूहों के बीच संचरण (मई 2022 से अक्तूबर 2024)



नोट : 1 साल के औसत एमसीएलआर पर डेटा मई 2022 से अक्तूबर 2024 की अवधि से संबंधित है।

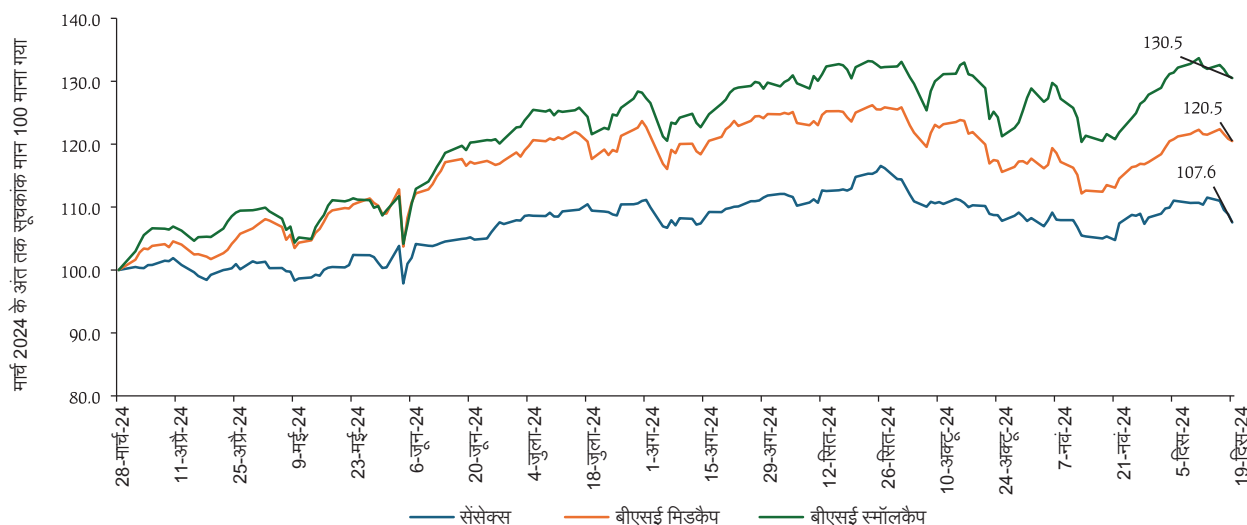
स्रोत : आरबीआई

पीवीबी की तुलना में पीएसबी के लिए नए और बकाया दोनों जमा राशियों के डब्ल्यूएडीटीडीआर में संचरण अधिक था (चार्ट IV.18)।

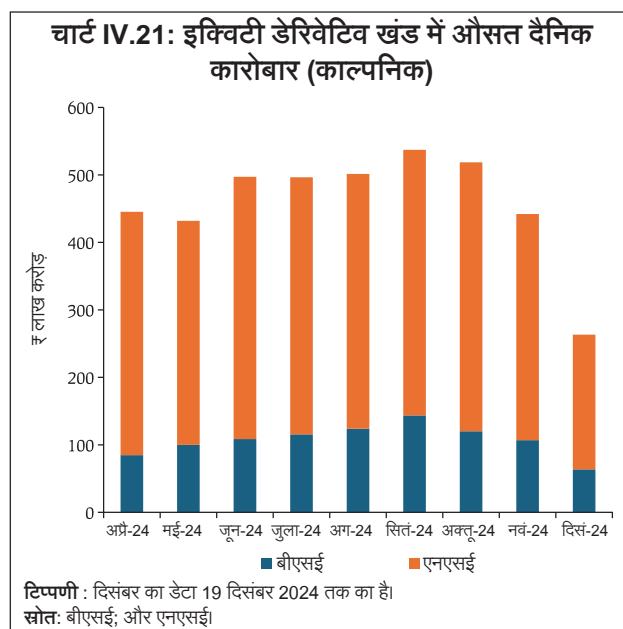
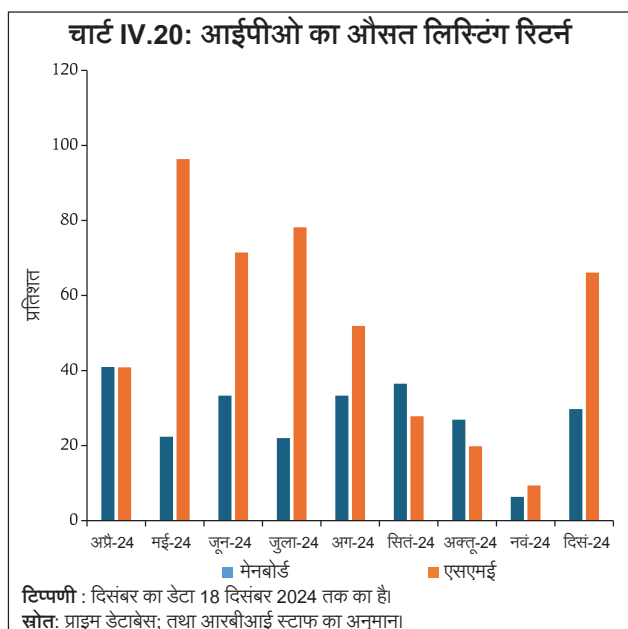
नवंबर के पहले तीन सप्ताहों में भारतीय शेयर बाजारों में गिरावट दर्ज की गई, जिसमें कमज़ोर कॉर्पोरेट आय, एफपीआई की बिकवाली, भू-राजनीतिक अनिश्चितताएँ और मूल्यांकन संबंधी चिंताएँ शामिल थीं। हालाँकि, राज्य चुनाव परिणामों की घोषणा

के बाद महीने के अंत में बाजारों में उछाल आया और दिसंबर की शुरुआत सकारात्मक वैश्विक संकेतों के कारण मज़बूती के साथ हुई। इसके बाद, प्रमुख मौद्रिक नीति घोषणाओं से पहले बाजारों में गिरावट देखी गई, जो 2025 में ब्याज दरों में कम कटौती के बारे में यूएस फ़ेड द्वारा दिए गए संकेतों से और बढ़ गई। कुल मिलाकर, 14 नवंबर, 2024 से बीएसई सेंसेक्स में 2.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 19 दिसंबर, 2024 को 79,218 पर बंद हुआ

चार्ट IV.19: इक्विटी बाजारों में रुझान



स्रोत: ब्लूमबर्ग



(चार्ट IV.19)। मिडकैप और स्मॉलकैप खंड बेंचमार्क से बेहतर प्रदर्शन करते रहे।

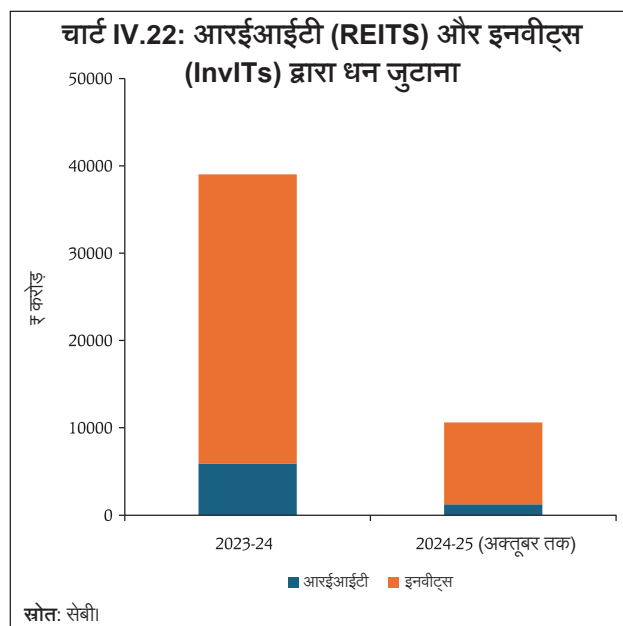
इक्विटी बाजारों में जारी अस्थिरता, प्राथमिक बाजारों के कामकाज को बढ़ाने के उद्देश्य से विनियामकीय पहलों ²⁴ के साथ मिलकर, प्राथमिक इक्विटी बाजार में धारणा को प्रभावित किया, जैसा कि नवंबर में कमजोर ग्राहकी स्तर ²⁵ और प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) के सूचीबद्ध प्रदर्शन से स्पष्ट है (चार्ट IV.20)।

निवेशक संरक्षण और बाजार स्थिरता को बढ़ाने के लिए इक्विटी सूचकांक विपन्नी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से कई विनियामकीय उपाय - जैसे सामाहिक सूचकांक विपन्नी उत्पादों का युक्तीकरण और अनुबंध के आकार में वृद्धि - नवंबर 2024 की दूसरी छमाही में प्रभावी हुए। इसके बाद, इक्विटी विपन्नी खंड में औसत दैनिक कारोबार में नरमी आई है (चार्ट IV.21)।

²⁴ <https://www.sebi.gov.in/reports-and-statistics/reports/nov-2024/consultation-paper-on-review-of-sme-segment-framework-under-sebi-icdr-विनियम-2018-और-सेबी-लोज़-विनियम-2015-पर-एसएमई-कंपनियों-पर-88627.html> के तहत कॉर्पोरेट-गवर्नंस-प्रावधानों की प्रयोज्यता

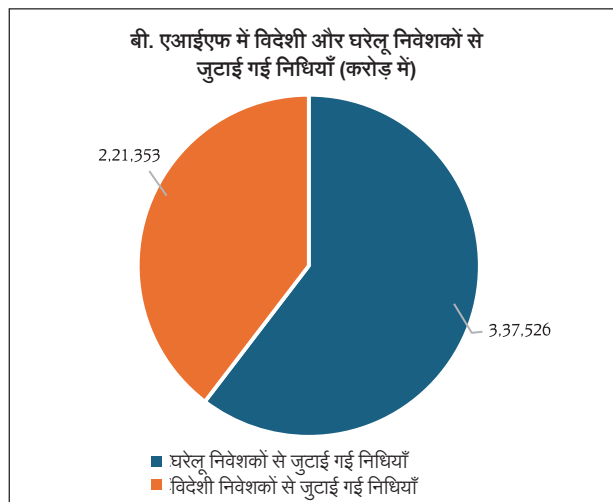
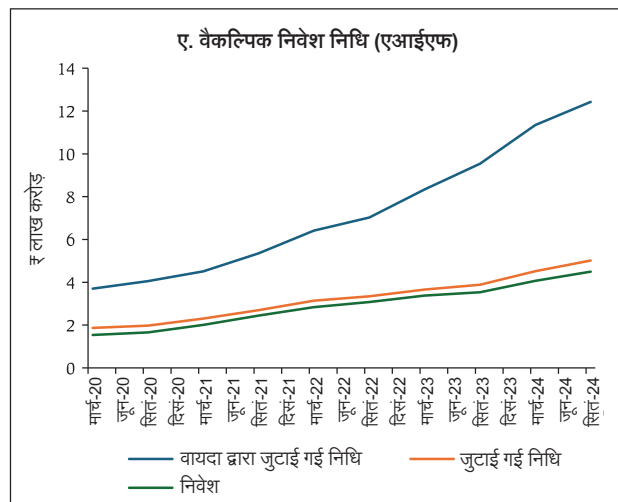
²⁵ <https://www.moneycontrol.com/news/business/markets/ipo-frenzy-cools-down-in-november-as-subscription-levels-take-a-hit-12881753.html>

चालू वित्त वर्ष में स्थावर संपदा निवेश ट्रस्ट (आरईआईटी) और इन्फ्रास्ट्रक्चर निवेश ट्रस्ट (इनविट) द्वारा संसाधन जुटाना धीमा रहा है (चार्ट IV.22)। दिसंबर में पहले लघु और मध्यम स्थावर संपदा निवेश ट्रस्ट (एसएम आरईआईटी) की शुरुआत हुई। ²⁶



²⁶ https://www.sebi.gov.in/filings/sm-reit-issues/dec-2024/property-share-investment-trust-propshare-platina_89388.html

चार्ट IV.23: वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ)



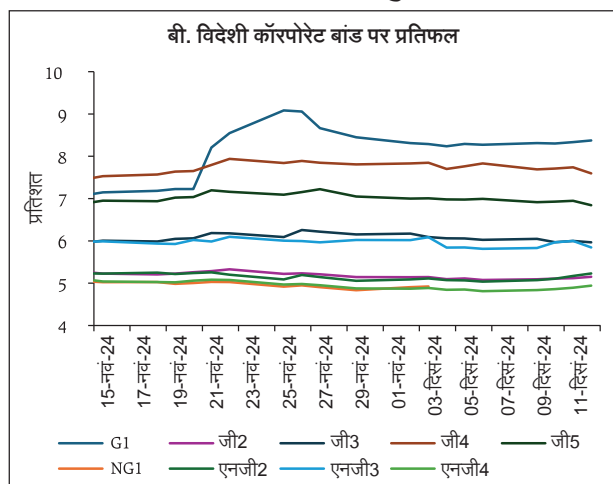
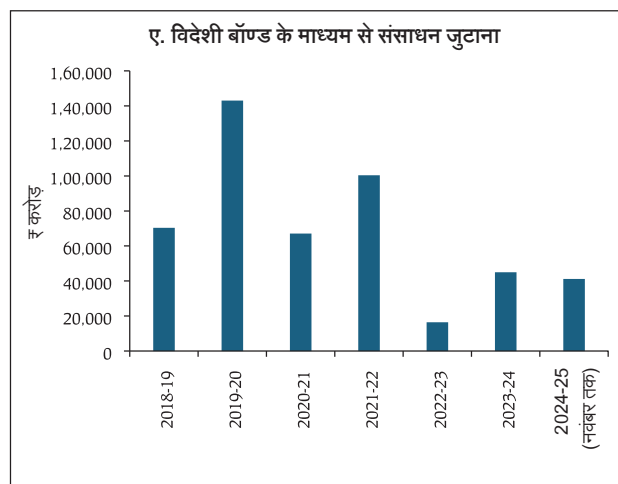
टिप्पणी: चार्ट IV.23ए. में डेटा तिमाही के अंत तक संचयी निवल आंकड़े हैं। चार्ट IV.23बी. में डेटा सितंबर 2024 के अंत तक जुटाई गई सकल निधि है।
स्रोत: सेबी।

वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) गति पकड़ रहे हैं, जो उच्च जोखिम वाले उद्यमों के लिए महत्वपूर्ण पूंजी प्रदान करते हैं²⁷ (चार्ट IV.23ए)। उल्लेखनीय रूप से, एआईएफ में निवेश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा घरेलू निवेशकों से प्राप्त किया जा रहा है (चार्ट IV.23बी)।

भारतीय फर्मों ने घरेलू संसाधन जुटाने में मदद करते हुए

विदेशी बाजारों से सक्रिय रूप से धन जुटाया है। पिछले दो वर्षों में धीमी गतिविधि के बाद, चालू वित्त वर्ष में विदेशी धन उगाहने में मामूली सुधार देखा गया है (चार्ट IV.24ए)। नवंबर के दूसरे पखवाड़े में, एक विशिष्ट समूह द्वारा जारी विदेशी बॉण्ड पर प्रतिफल में थोड़ी वृद्धि हुई (चार्ट IV.24बी)। विदेशी बाजारों में अन्य घरेलू कॉरपोरेट्स द्वारा जारी कुछ हरित बॉण्ड में भी

चार्ट IV.24: नवंबर में विदेशी कॉरपोरेट ग्रीन बॉण्ड पर प्रतिफल में क्षणिक वृद्धि हुई

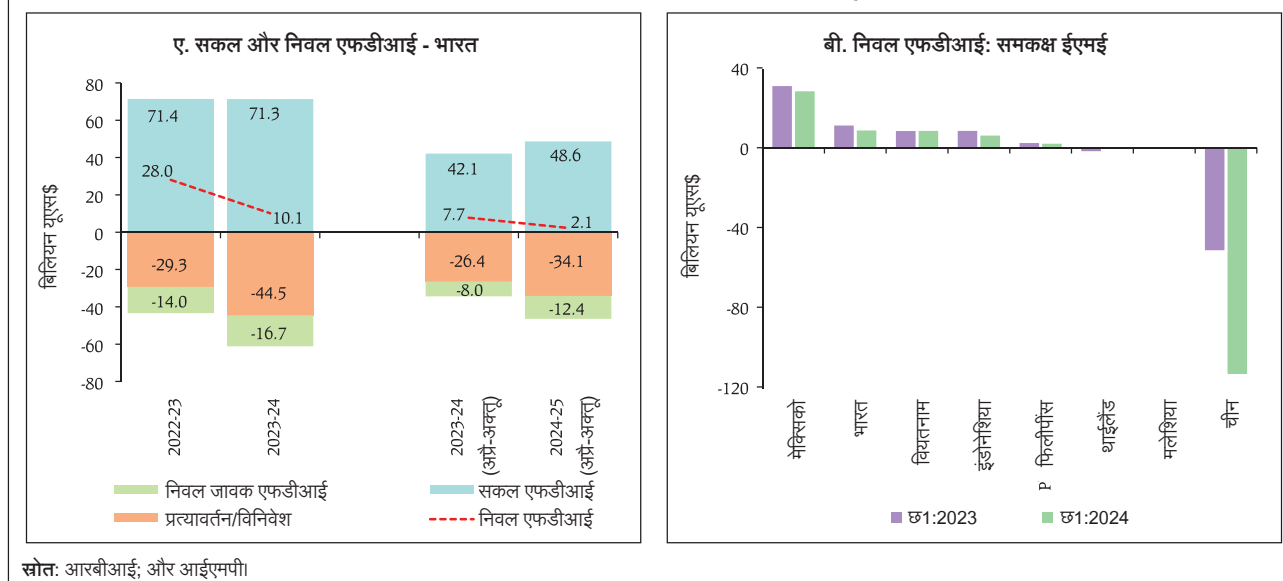


टिप्पणी: जी1 से जी5 चयनित भारतीय कॉरपोरेट संस्थाओं द्वारा जारी विदेशी ग्रीन बॉण्ड पर प्रतिफल हैं। एनजी1 से एनजी4 चयनित भारतीय कॉरपोरेट संस्थाओं द्वारा जारी विदेशी गैर-ग्रीन बॉण्ड पर प्रतिफल हैं।

स्रोत: ब्लूमबर्ग; और प्राइम डेटाबेस।

²⁷ https://www.business-standard.com/markets/news/alternative-investment-funds-gain-currency-as-fund-raise-tops-rs-5-trillion-124112601117_1.html

चार्ट IV.25: प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह



प्रतिफल में मामूली वृद्धि देखी गई, लेकिन इसका प्रभाव सीमित था और यह जल्दी ही उलट गया।

अप्रैल-अक्तूबर 2024 के दौरान सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) बढ़कर 48.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो एक साल पहले 42.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर था (चार्ट IV.25ए)। सकल एफडीआई प्रवाह का 60 प्रतिशत से अधिक विनिर्माण, वित्तीय सेवाओं, बिजली और अन्य ऊर्जा, तथा खुदरा और थोक व्यापार क्षेत्रों में निर्देशित किया गया। प्रमुख स्रोत देशों में सिंगापुर, मॉरीशस, यूएई, नीदरलैंड और अमेरिका शामिल थे, जिन्होंने इस अवधि के दौरान प्रवाह में तीन-चौथाई से अधिक का योगदान दिया।

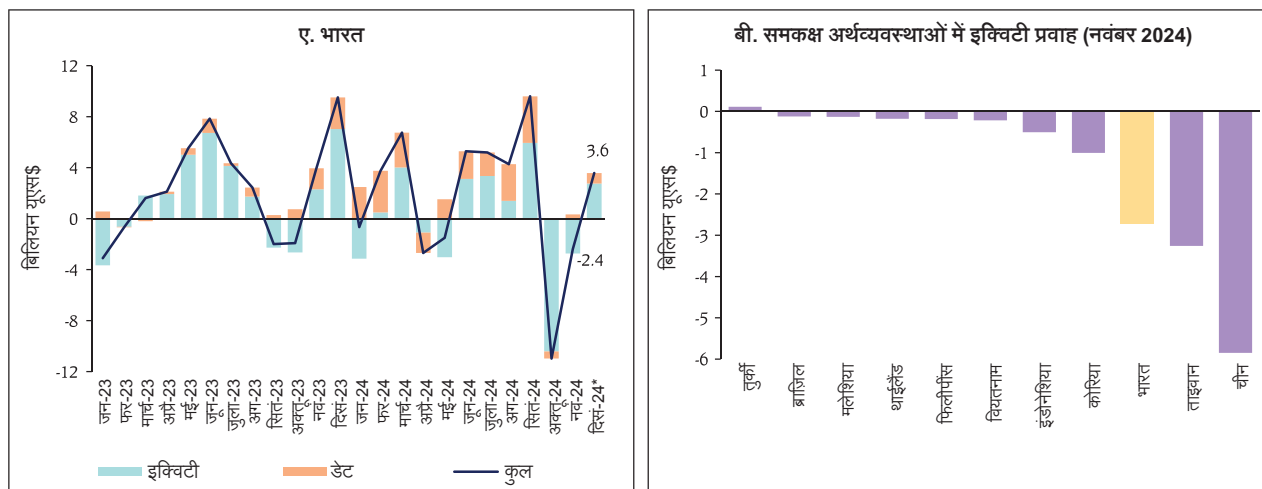
अप्रैल-अक्तूबर 2024 के दौरान निवल एफडीआई घटकर 2.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया, जो एक साल पहले 7.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिसका मुख्य कारण प्रत्यावर्तन और निवल बाह्य एफडीआई में वृद्धि है। जबकि प्रत्यावर्तन अप्रैल-अक्तूबर 2024 के दौरान एक साल पहले 26.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 34.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, वहीं निवल बाह्य एफडीआई इसी अवधि के दौरान 8.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 12.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। एक साल पहले की तुलना में 2024 की पहली छमाही

के दौरान अधिकांश सहकर्मी उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में निवल एफडीआई में इसी तरह की कमी दिखाई दे रही है (चार्ट IV.25बी)।

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) नवंबर 2024 में भारतीय वित्तीय बाजारों में निवल विक्रेता बने रहे, क्योंकि अमेरिकी चुनावों के बाद बढ़ते अमेरिकी डॉलर और अमेरिकी प्रतिफल के साथ-साथ उच्च घरेलू स्टॉक मूल्यांकन और विकास मंदी की चिंताओं ने भावनाओं को प्रभावित किया। नवंबर 2024 में निवल एफपीआई बहिर्वाह 2.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिसमें इक्विटी में 2.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवल बहिर्वाह और ऋण खंड में 0.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवल प्रवाह था। हालांकि, दिसंबर (18 दिसंबर तक) के दौरान एफपीआई प्रवाह सकारात्मक हो गया और 3.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवल प्रवाह हुआ (चार्ट IV.26ए)। क्षेत्रों के भीतर, तेल, गैस और उपभोज्य ईंधन, और ऑटोमोबाइल और ऑटो घटकों ने सबसे अधिक इक्विटी बहिर्वाह दर्ज किया,

अप्रैल-अक्तूबर 2024 के दौरान बाहरी वाणिज्यिक उधारी (ईसीबी) संवितरण के साथ-साथ नए ऋण पंजीकरण पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अधिक थे (चार्ट IV.27ए)। मूलधन के पुनर्भुगतान के कारण बहिर्वाह को समायोजित करते

चार्ट IV.26: निवल पोर्टफोलियो निवेश



टिप्पणियाँ: 1. ऋण में हाइब्रिड लिखतों के तहत निवेश भी शामिल है।

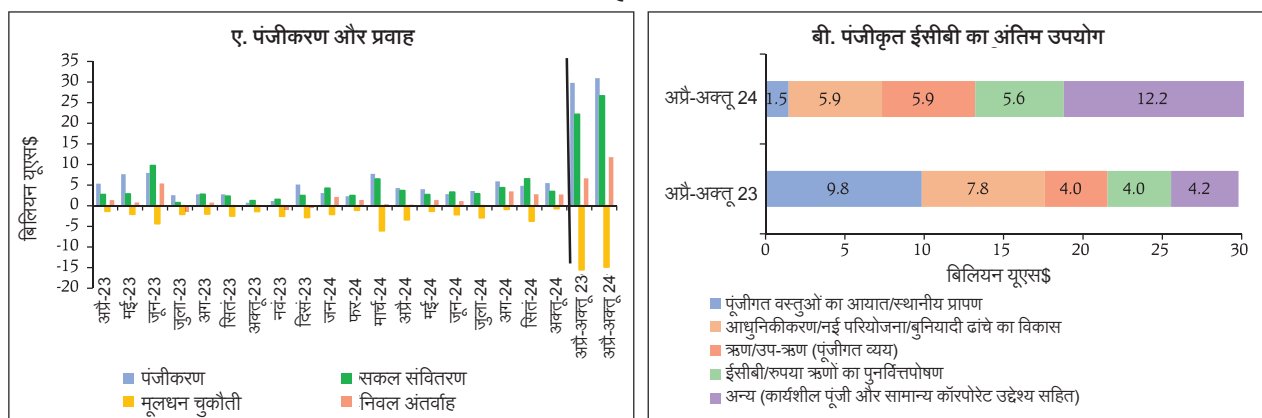
2. *: 18 दिसंबर 2024 तक का डेटा।

स्रोत: राष्ट्रीय प्रतिभूति डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल); तथा भारतीय वित्त संस्थान।

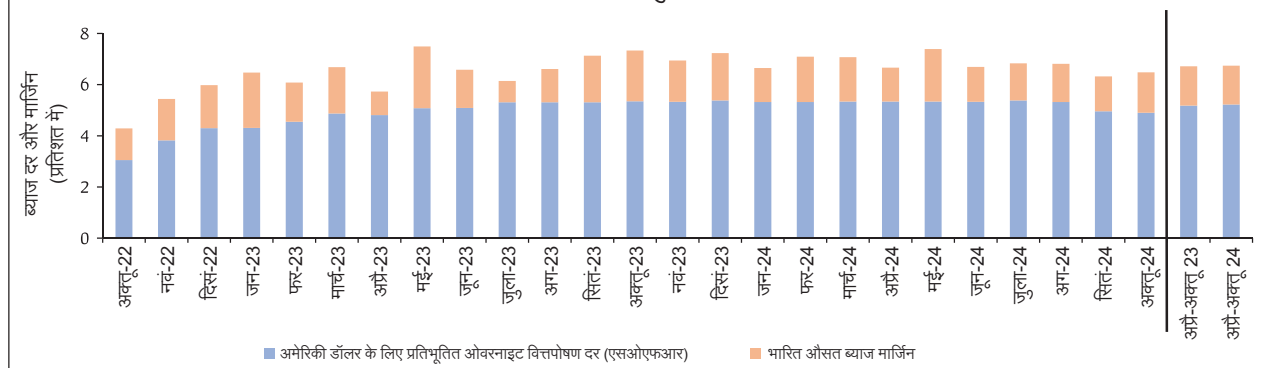
हुए, चालू वित्त वर्ष के दौरान अब तक निवल ईसीबी अंतर्वाह एक साल पहले की तुलना में 76 प्रतिशत अधिक था। अप्रैल-

अक्तूबर 2024 के दौरान पंजीकृत 40 प्रतिशत से अधिक ईसीबी को पूंजीगत व्यय उद्देश्यों के लिए निर्धारित किया गया था,

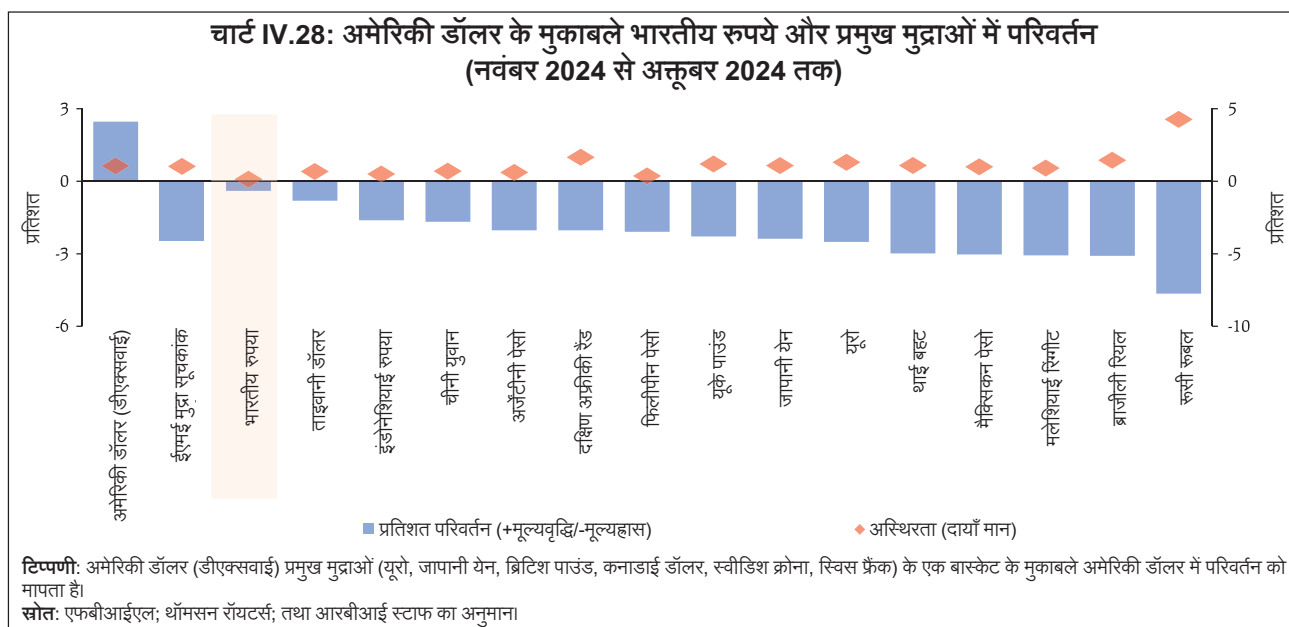
चार्ट IV.27: बाह्य वाणिज्यिक उधार



सी. ईसीबी की कुल लागत



स्रोत: ईसीबी, आरबीआई फॉर्म; तथा आरबीआई स्टाफ का अनुमान।



जिसमें आगे उधार देना और उप-उधार देना शामिल है (चार्ट IV.27बी)।

भारत औसत ब्याज मार्जिन (डबल्यूएआईएम) में वृद्धि के कारण अक्तूबर 2024 के दौरान पंजीकृत नए ईसीबी की कुल लागत में 16 बीपीएस की वृद्धि हुई। अप्रैल-अक्तूबर 2024 के दौरान पंजीकृत ईसीबी की कुल लागत 6.7 प्रतिशत रही जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के समान ही रही (चार्ट IV.27सी)।

अप्रैल-अक्तूबर 2024 के दौरान अनिवासी जमाराशियों में निवल वृद्धि लगभग दोगुनी होकर 11.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई, जो एक वर्ष पहले 6.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। ऐसा सभी तीन खातों अर्थात् अनिवासी (बाह्य) रुपया खाते [एनआर(ई)आरए], अनिवासी साधारण (एनआरओ) और विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) [एफसीएनआर(बी)] खातों में अधिक वृद्धि के कारण हुआ है।

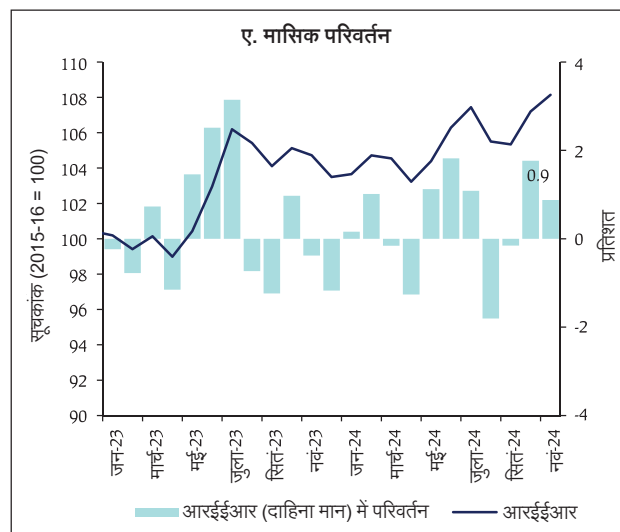
नवंबर 2024 के दौरान, ईएमई मुद्राओं को मजबूत एफपीआई बहिर्वाह, मजबूत अमेरिकी डॉलर और बढ़ती अमेरिकी प्रतिफल से दबाव का सामना करना पड़ा। इन प्रतिकूल परिस्थितियों

के बीच, नवंबर 2024 में भारतीय रुपये (आईएनआर) में 0.4 प्रतिशत (मासिक) की गिरावट आई, जो अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में मामूली थी। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद, प्रमुख मुद्राओं में आईएनआर ने सबसे कम अस्थिरता प्रदर्शित की (चार्ट IV.28)।

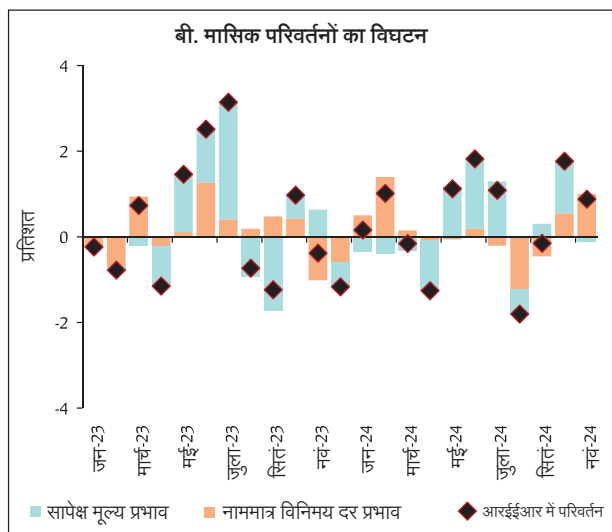
40-मुद्रा वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) के संदर्भ में, नवंबर 2024 में भारतीय रुपये में 0.9 प्रतिशत (मासिक) की वृद्धि होगी, क्योंकि नाममात्र प्रभावी शर्तों में भारतीय रुपये की वृद्धि ऋणात्मक सापेक्ष मूल्य अंतरों की भरपाई से अधिक है (चार्ट IV.29)।

2024-25 के दौरान अब तक विदेशी मुद्रा भंडार 6.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़कर 13 दिसंबर, 2024 को 652.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। वर्तमान स्तर पर, यह जून 2024 के अंत में 11 महीने से अधिक के आयात और लगभग 96 प्रतिशत बकाया बाहरी ऋण के बराबर है (चार्ट IV.30a)। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत बना हुआ है, जैसा कि रिज़र्व पर्याप्तता मैट्रिक्स के स्थायी स्तरों में परिलक्षित होता है (चार्ट IV.30बी)।

चार्ट IV.29 : 40 मुद्रा वास्तविक प्रभावी विनिमय दर में मासिक परिवर्तन



स्रोत : आरबीआई



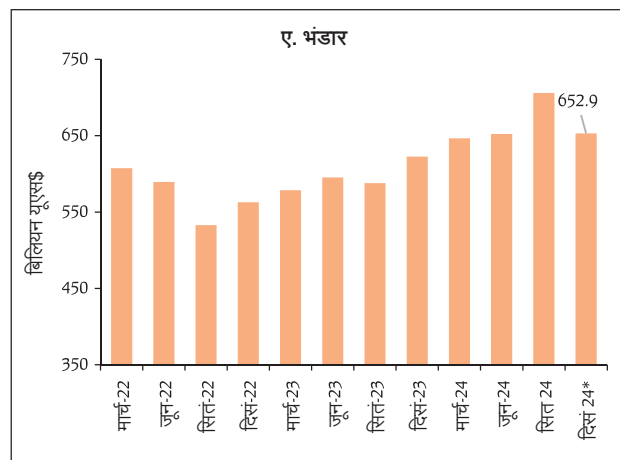
भुगतान प्रणालियाँ

डिजिटल भुगतान के अधिकांश तरीकों ने नवंबर 2024 में सालाना आधार पर विस्तार दर्ज किया, हालांकि अक्तूबर के त्योहारी महीने से इसमें मंदी आई (सारणी IV.2)। उल्लेखनीय रूप से, भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) और एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) का उपयोग करने वाले लेन-देन

में मजबूत वृद्धि दर्ज की गई। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (एनईटीसी) प्रणाली ने नवंबर में मात्रा और मूल्य दोनों के संदर्भ में उच्च वृद्धि (सालाना) प्रदर्शित की।

2024-25 के दौरान अब तक (अक्तूबर 2024 तक), नए कार्ड जारी करने में वृद्धि हुई है, जो मुख्य रूप से डेबिट कार्ड द्वारा संचालित है। त्योहारी सीज़न (चार्ट IV.31) के कारण अक्तूबर

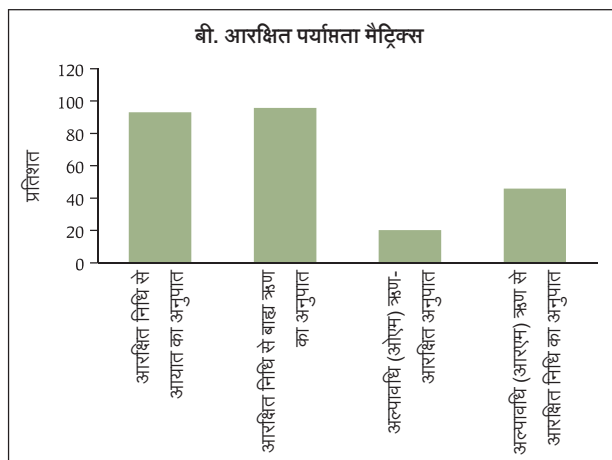
चार्ट IV.30: विदेशी मुद्रा भंडार



टिप्पणीयाँ: 1.: 13 दिसंबर के आंकड़े हैं।

2. ओएम: मूल परिपक्वता; आरएम: अवशिष्ट परिपक्वता। जून 2024 के लिए नवीनतम उपलब्ध रिजर्व डेटा और वार्षिक व्यापारिक आयात और बाहरी ऋण का उपयोग करके आरक्षित पर्याप्तता मैट्रिक्स की गणना की गई है।

स्रोत : आरबीआई; संबंधित केंद्रीय बैंक की वेबसाइटें; तथा आरबीआई स्टाफ के अनुमान।



सारणी 5 : चुनिन्दा भुगतान प्रणालियों में वृद्धि दर

(वर्षानुवर्ष प्रतिशत)

भुगतान प्रणाली संकेतक	लेनदेन मात्रा				लेनदेन का मूल्य			
	अक्टू-23	अक्टू-24	नव-23	नव-24	अक्टू-23	अक्टू-24	नव-23	नव-24
आरटीजीएस	18.0	19.3	6.2	9.6	16.6	26.8	10.6	9.1
एनईएफटी	38.2	45.4	45.7	21.5	19.6	27.3	17.5	5.4
यूपीआई	56.2	45.4	53.7	37.8	41.6	37.0	46.1	23.9
आईएमपीएस	2.2	-5.3	1.9	-13.6	15.5	16.9	17.7	4.4
एनएसीएच	-1.5	64.5	65.9	-9.3	11.9	43.5	27.2	9.9
एनईटीसी	13.0	7.9	12.3	11.9	24.4	10.4	14.1	14.5
बीबीपीएस	26.6	101.0	29.5	88.8	59.2	299.2	66.7	266.4

नोट: आरटीजीएस: तत्काल सकल निपटान; एनईएफटी: राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण; यूपीआई: एकीकृत भुगतान इंटरफेस; आईएमपीएस: तत्काल भुगतान सेवा; एनएसीएच: राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह; एनईटीसी: राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह; और बीबीपीएस: भारत बिल भुगतान प्रणाली।

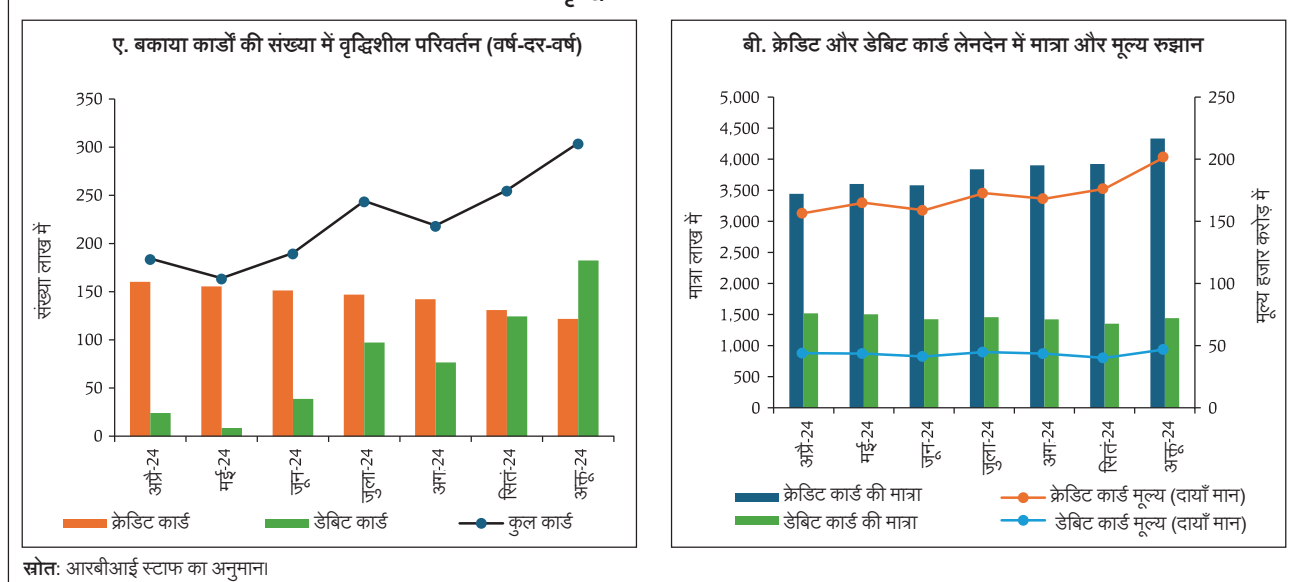
स्रोत : आरबीआई

2024 में क्रेडिट और डेबिट कार्ड लेनदेन की मात्रा और मूल्य दोनों में गति बनी रही।

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) ने कई नई सुविधाएँ शुरू की हैं, जिनमें भारत इंटरफ़ेस फ़ॉर मनी (भीम) ऐप की नई राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) योगदान सुविधा शामिल है, जो वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देती है और तेज़ प्रक्रिया तथा आसान पहुँच के साथ सेवानिवृत्ति योजना को सरल

बनाती है।²⁸ इसके अतिरिक्त, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए आधार भुगतान ब्रिज (एपीबी) और ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (एसीएच) लेनदेन के लिए एक नया उत्पाद प्रकार लागू किया गया है, जो 23 नवंबर, 2024 से प्रभावी होगा, जिसमें रिज़र्व बैंक प्रायोजक होगा।²⁹ राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (एनएसीएच) के सदस्य बैंक, निगम और एग्रीगेटर इन परिवर्तनों में भाग लेंगे। एनपीसीआई ने ऑनलाइन मैडेट गेटवे सिस्टम (ओएनएमएजीएस) एप्लिकेशन के लिए एडवांसड

चार्ट IV.31: कार्ड वृद्धि और लेनदेन गतिविधि में रुझान



²⁸ एनपीसीआई प्रेस विज्ञप्ति, 13 नवंबर, 2024।

²⁹ एनपीसीआई परिपत्र, 16 नवंबर, 2024।

एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड (ईएस) को भी अनिवार्य बना दिया है, जो आवर्ती भुगतानों के लिए इलेक्ट्रॉनिक मँडेट का प्रबंधन करता है। यह तेज़, अधिक कुशल एन्क्रिप्शन और उद्योग मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करेगा।³⁰

6 दिसंबर, 2024³¹ को विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर अपने वक्तव्य में, रिज़र्व बैंक ने एमएसएमई और व्यक्तियों के लिए विदेशी मुद्रा मूल्य निर्धारण में पहुँच और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए भारत कनेक्ट³² के साथ एफएक्स-रिटेल प्लेटफॉर्म (सीसीआईएल द्वारा 2019 में लॉन्च किया गया) को जोड़ने का प्रस्ताव दिया। पायलट बैंक और गैर-बैंक प्रणालियों के माध्यम से यूएसडी लेनदेन को सक्षम करेगा, जिसमें व्यापक विस्तार की योजना बनाई गई है। इसके अतिरिक्त, रिज़र्व बैंक ने छोटे वित्त बैंकों (एसएफबी) को यूपीआई के माध्यम से पूर्व-स्वीकृत क्रेडिट लाइनों का विस्तार करने की अनुमति देने का प्रस्ताव दिया, जिससे 'न्यू-टू-क्रेडिट' ग्राहकों के लिए छोटी-टिकट, छोटी अवधि के उत्पादों तक पहुँच की सुविधा होगी।

फिनटेक क्षेत्र में, रिज़र्व बैंक ने वित्तीय क्षेत्र में एआई (फ्री-एआई) के जिम्मेदार और नैतिक सक्षमता के लिए एक रूपरेखा विकसित करने के लिए एक समिति के गठन का प्रस्ताव दिया है। डिजिटल धोखाधड़ी का समाधान करने के लिए, रिज़र्व बैंक "शून्य वित्तीय धोखाधड़ी" नामक एक हैकथॉन आयोजित कर रहा है, जिसमें मूल खातों पर एक विशिष्ट समस्या विवरण शामिल है जिसका उद्देश्य उनके दुरुपयोग को रोकने के लिए अभिनव समाधानों को बढ़ावा देना है। रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब (आरबीआईएच) द्वारा संचालित एक एआई/एमएल -आधारित मॉडल, MuleHunter.AI ने मूल बैंक खातों का पता लगाने में आशाजनक परिणाम दिखाए हैं। दो प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ सफल परीक्षणों के बाद, रिज़र्व बैंक इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए आरबीआईएच के साथ व्यापक सहयोग के लिए बैंकों को प्रोत्साहित करता है।

V. निष्कर्ष

वैश्विक अर्थव्यवस्था 2025 में सुदृढ़ता के साथ प्रवेश करने के लिए तैयार है, क्योंकि वास्तविक आय में सुधार, स्थिर श्रम बाजार

और वैश्विक व्यापार में धीरे-धीरे सुधार के कारण मुद्रास्फीति और मौद्रिक नीति में तेजी से सुधार हो रहा है। हालांकि, वर्तमान भू-राजनीतिक तनाव, बढ़ते संरक्षणवाद और बड़े सार्वजनिक ऋण के रूप में चुनौतियाँ बनी हुई हैं। इन घटनाक्रमों का उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उनकी मुद्राएं और इक्विटी 2024 में व्यापार और पूंजी प्रवाह के लिए अत्यधिक अनिश्चित वातावरण में देखी जाने वाली गिरावट के तेज दौर के प्रति संवेदनशील हैं।

भारत की विकास दर 2024-25 की दूसरी छमाही में बढ़ने की उम्मीद है, जो मुख्य रूप से सुदृढ़ घरेलू निजी खपत मांग से प्रेरित है। रिकॉर्ड स्तर के खाद्यान्न उत्पादन से समर्थित, विशेष रूप से ग्रामीण मांग में तेजी आ रही है। बुनियादी ढांचे पर निरंतर सरकारी खर्च से आर्थिक गतिविधि और निवेश को और बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। हालांकि, वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियाँ विकास और मुद्रास्फीति के लिए उभरते दृष्टिकोण के लिए जोखिम पैदा करती हैं।

भारत के सुदृढ़ विकास पथ के बारे में भविष्य की उम्मीदें भी सकारात्मक जलवायु कार्रवाई के मद्देनजर अधिक स्थिर आधार के साथ मिल रही हैं, जिसमें अक्षय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी), ग्रीन हाइड्रोजन और कार्बन बाजार को संस्थागत बनाने की दिशा में कदम बढ़ाने पर नीतिगत ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। ये सम्मिलित प्रयास निवल-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने की दिशा में एक आशाजनक मार्ग का संकेत देते हैं। कार्बन ट्रेडिंग के लिए वैश्विक ढाँचों का लाभ उठाना और ग्रीन बॉण्ड सहित जलवायु वित्त को बढ़ाना, विकास और उत्सर्जन के बीच अलगाव को और मजबूत करेगा। इसके साथ ही, भारत विकास को बढ़ावा देने, उत्पादकता में सुधार करने और उत्पादों और सेवाओं की पहुँच बढ़ाने के लिए डिजिटलीकरण की लहर पर सवार है, जो अधिक समझदार उपभोक्ता व्यवहार में बदलाव और ऑनलाइन शॉपिंग की गहरी पहुँच, विशेष रूप से छोटे शहरों में, से प्रेरित है। यह उछाल बढ़ते निवेशक विश्वास और भारत के फिनटेक आरोहण को आगे बढ़ाने वाली नवीन ऊर्जा की गति को भी रेखांकित करता है।

³⁰ एनपीसीआई परिपत्र, 18 नवंबर, 2024।

³¹ आरबीआई प्रेस विज्ञप्ति, 6 दिसंबर, 2024।

³² पहले इसे भारत बिल भुगतान प्रणाली के नाम से जाना जाता था।